सोशल मीडिया से जुड़ें
Parivehan_Vishesh

RNI No :- DELHIN/2023/86499
DCP Licensing Number :
F.2 (P-2) Press/2023

www.newsparivahan.com

परिवहन विशेष

वर्ष 02, अंक 168, नई दिल्ली । बुधवार, 28 अगस्त 2024, मूल्य ₹ 5, पेज 8

देश का पहला ट्रांसपोर्ट दैनिक समाचार पत्र

आज का सुविचार

अपने किरदार की हिफाजत जान से बढ़कर कीजिये, क्योंकि इसे जिंदगी के बाद भी याद किया जाता है।

03 दिल्ली विधानसभा: हो सकते है वक्त से पहले चुनाव

06 विश्व बैंक रिपोर्ट को खारिज करे भारत

08 संस्कारशाला: मानसिक स्वास्थ्य का महत्व - सोशल मीडिया की बढ़ती...

दिल्ली मे पंजीकृत व्यवसायिक वाहन मालिकों और महिलाओं के लिए परिवहन विभाग द्वारा आया एक खुशी का पैगाम

संजय बाटला

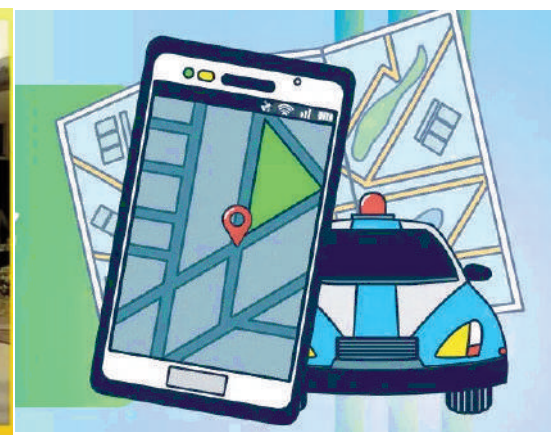

नईदिल्ली। पिछले दो साल से जिस आदेश के आने का वाहन मालिकों को इन्तजार था आखिर आज वह परिवहन विभाग दिल्ली द्वारा जारी कर ही दिया गया। इस आदेश मे लेकिन परिवहन विभाग ने उन मालिकों के बारे मे कोई आदेश जारी नही किए जिनकी फीस एक महीने से लेकर 23 महीने तक की एडवांस में डिम्ट्स के पास जमा है। आप की जानकारी हेतु बता दें दिल्ली परिवहन विभाग ने दिनाक 27/08/2024 को एनआईसी के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर कर पूरी वीएलटीडी परियोजना डिम्ट्स से हटाकर एनआईसी को सौप दी जिस कारण अब डिम्ट्स को जमा होने वाली फीस तत्काल प्रभाव से हटा दी गई जो आज तक ली जा रही थी। डिम्ट्स नए वाहनों से लेकर 8 साल पुराने पंजीकृत वाहनों से 2 साल की ओर 8 से अधिक पुराने वाहनों से एक साल की फीस एकमुस्त एडवांस में जमा करती थी। **अब सवाल यह उठता है की जब आज से डिम्ट्स का कार्य खत्म हो गया तो डिम्ट्स के पास वाहन मालिकों की फीस एडवांस में जमा है को वापिस करने के आदेश दिल्ली परिवहन विभाग के उपायुक्त रामनाथन जिसके हस्ताक्षर इस जारी आदेश पर है के द्वारा क्यो नही किए गए।** क्या किसी नियम/ कानून/ धारा में यह प्रमाणित है की एडवांस ली गई फीस वापिस नहीं की जाएगी ? क्या कम्पनी के फायदे के लिए वाहन चालकों द्वारा एडवांस फीस की वापसी के आदेश उपायुक्त द्वारा जारी नही किए गए? यहां आपकी जानकारी हेतु बता दें की दिल्ली मे निर्भया कांड जैसी दर्दनाक और अपमान जनक दुर्घटना महिलाओ के साथ दुबारा नहीं हो के प्रति पैनिक बटन वीएलटीडी के आदेश जारी हुए थे जिसके नाम पर गृह सचिव कमेटी और उच्च न्यायालय को दिखाने के लिए परिवहन विभाग ने अपनी 50 % हिस्सेदारी वाली कम्पनी डिम्ट्स को वाहन चालकों से फीस लेने के निर्देश जारी कर वाहन चालकों से फीस बटोरना शुरू करवा दिया था पर पैनिक बटन को वाहनों में कार्यान्वित करने के लिए डाटा बेस सेंटर शुरू नही करवाया था। परिवहन विभाग द्वारा दो वर्ष पहले उस सेंटर को बनाने में लगने वाली पूरी रकम भारत सरकार से प्राप्त कर बैंक में जमा कर रखी थी और फिर भी सेंटर शुरू नही किया था। **आज दिल्ली मे सार्वजनिक वाहनों में सफर करने वाली महिलाओ को इतने वर्षो के इंतजार के बाद पैनिक बटन सेवा उपलब्ध हों ही गई जो खुशी की बात है** पर वाहन मालिकों का एडवांस पैसा जो डिम्ट्स के पास जमा है तत्काल प्रभाव से उसे भी वापिस करने के आदेश जारी होने चाहिए और **उपायुक्त रामनाथन के खिलाफ जांच के आदेश, "आखिर इस बात को आयुक्त परिवहन के समक्ष प्रस्तुत कर एडवांस पैसे की वापसी के आदेश उपायुक्त परिवहन रामनाथन ने क्यो नही पारित करवाए।**

नागपुर में शुरू होगी देश की पहली इलेक्ट्रिक एलिवेटेड बस सेवा

परिवहन विशेष न्यूज

केंद्रीय सड़क परिवहन मंत्री नितिन गडकरी ने कहा है कि नागपुर में देश की पहली इलेक्ट्रिक एलिवेटेड बस सेवा शुरू की जाएगी। यह विशेष बस सेवा नागपुर में रिंग रोड पर पचास किलोमीटर की दूरी तक चलेगी। इस उद्देश्य के लिए मशहूर ऑटोमोबाइल कंपनी टाटा और स्कोडा के संयुक्त उपक्रम द्वारा यह विशेष बस तैयार की जा रही है और यह बस 18 मीटर लंबी होगी। नितिन गडकरी ने कहा कि इस विशेष बस में यात्रियों को हवाई जहाज जैसी सभी सुविधाएं दी जाएंगी।

नितिन गडकरी ने दावा किया है कि इस इलेक्ट्रिक बस सेवा का किराया एसटी या नगर निगम द्वारा संचालित डीजल बस सेवा से 30 प्रतिशत कम होगा। नितिन गडकरी ने कहा कि देश में एलिवेटेड रूट पर इलेक्ट्रिक बस सेवा का यह पहला प्रयोग होगा और इसे नागपुर के अति व्यस्त रिंग रोड पर 50 किलोमीटर की दूरी तक लागू किया जाएगा। नितिन गडकरी ने नेचुरल फार्मिंग पुस्तक के विमोचन और एग्रो विजन किसान भवन के भूमि पूजन के दौरान यह जानकारी दी।

केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने यह भी कहा कि देश में इथेनॉल आधारित पेट्रोल पंप शुरू किए जा रहे हैं। मैंने देश की सभी बड़ी ऑटोमोबाइल कंपनियों को इथेनॉल से चलने वाले वाहन बनाने के लिए कहा है। उन्होंने कहा कि कोई भी किसान अनाज पैदा करके समृद्ध नहीं बन सकता। किसान जैव ईंधन उत्पादक फसलों के माध्यम से ईंधन उत्पादन में योगदान देकर समृद्ध बन सकते हैं।

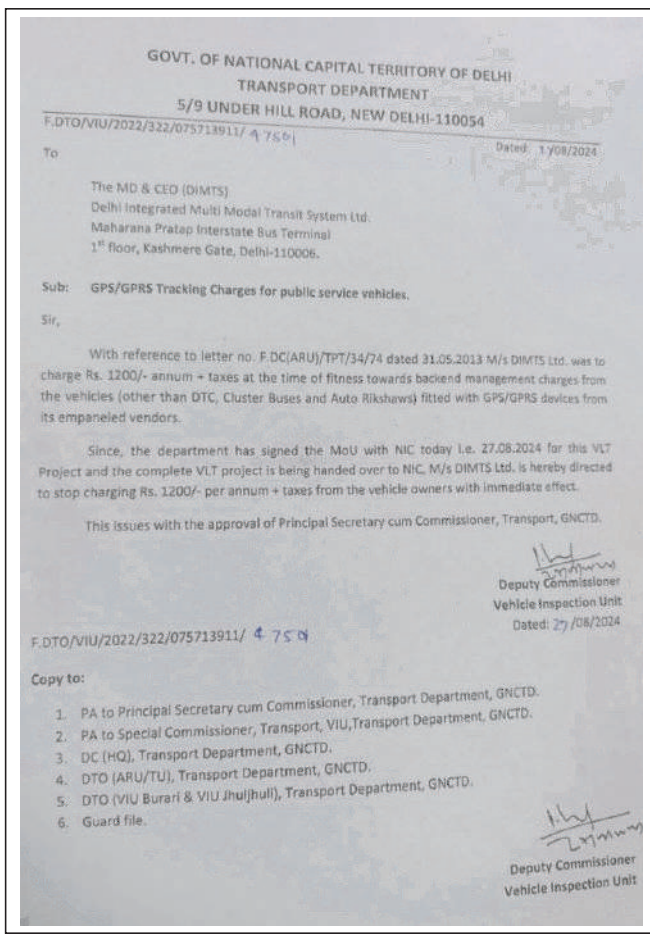

GOVT. OF NATIONAL CAPITAL TERRITORY OF DELHI
TRANSPORT DEPARTMENT
5/9 UNDER HILL ROAD, NEW DELHI-110054

F.DTO/VIU/2022/322/075713911/ 4756 Dated: 1/08/2024

To

The MD & CEO (DIMTS)
Delhi Integrated Multi Modal Transit System Ltd.
Maharana Pratap Interstate Bus Terminal
1st floor, Kashmere Gate, Delhi-110006.

Sub: GPS/GPRS Tracking Charges for public service vehicles.

Sir,

With reference to letter no. F.DC(ARU)/TPT/34/74 dated 31.05.2013 M/s DIMTS Ltd. was to charge Rs. 1200/- annum + taxes at the time of fitness towards backend management charges from the vehicles (other than DTC, Cluster Buses and Auto Rikshaws) fitted with GPS/GPRS devices from its empaneled vendors.

Since, the department has signed the MoU with NIC today i.e. 27.08.2024 for this VLT Project and the complete VLT project is being handed over to NIC, M/s DIMTS Ltd. is hereby directed to stop charging Rs. 1200/- per annum + taxes from the vehicle owners with immediate effect.

This issues with the approval of Principal Secretary cum Commissioner, Transport, GNCTD.

Deputy Commissioner
Vehicle Inspection Unit
Dated: 27/08/2024

F.DTO/VIU/2022/322/075713911/ 4759

Copy to:

1. PA to Principal Secretary cum Commissioner, Transport Department, GNCTD.
2. PA to Special Commissioner, Transport, VIU,Transport Department, GNCTD.
3. DC (HQ), Transport Department, GNCTD.
4. DTO (ARU/TU), Transport Department, GNCTD.
5. DTO (VIU Burari & VIU Jhuljhuli), Transport Department, GNCTD.
6. Guard file.

Deputy Commissioner
Vehicle Inspection Unit

सरकारी राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली परिवहन विभाग 5/9 अंडर हिल रोड, नई दिल्ली 110054

एफ.डीटीओ/वीआईयू/ 2022/322/075713911/47661 दिनाक: 1/08/2024

एमडी और सीईओ (डीआईएमटीएस) दिल्ली इंटीग्रेटेड मल्टी मॉडल ट्रांजिट सिस्टम लिमिटेड, महाराणा प्रताप अतरराज्यीय बस टीमनल 1 माजल, कश्मारा गट, दिल्ली-110006।1

विषयः *सार्वजनिक सेवा वाहनों के लिए जीपीएस/ जीपीआरएस ट्रैकिंग शुल्क ।*

महोदय, पत्र क्रमांक के संदर्भ में एफ. डीसी (एआरयू)/टीपीटी/ 34/74 दिनांक 31.05.2013 मेसर्स डीआईएमटीएस लिमिटेड को रु. का शुल्क लेना था। अपने पैनल में शामिल विक्रेताओं से जीपीएस/जीपीआरएस उपकरणों से सुसज्जित वाहनों (डीटीसी, क्लस्टर बसों और ऑटो रिक्शा के अलावा) से बैकएंड प्रबंधन शुल्क के लिए फिटनेस के समय 1200/- प्रति वर्ष + कर। चूंकि, विभाग ने इस वीएलटी परियोजना के लिए आज यानी 27.08.2024 को एनआईसी के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं और पूरी वीएलटी परियोजना एनआईसी को सौंपी जा रही है, इसलिए मेसर्स डीआईएमटीएस लिमिटेड को रुपये चार्ज करना बंद करने का निर्देश दिया जाता है। 1200/- प्रति वर्ष + वाहन मालिकों से कर तत्काल प्रभाव से।

क्या आप जानते है ?

परिवहन विशेष न्यूज

भारत में सड़क सुरक्षा पर ध्यान देने के लिए संसद के भीतर विशेष समितियाँ गठित की जाती हैं, जो सड़क सुरक्षा से संबंधित मुद्दों की समीक्षा और सिफारिशें करती हैं। एक प्रमुख समिति जो सड़क सुरक्षा पर ध्यान देती है, वह है:

संसदीय स्थायी समिति: सड़क सुरक्षा

सड़क सुरक्षा पर संसदीय स्थायी समिति: **संरचना:** यह समिति संसद की स्थायी समितियों में से एक है, जिसका मुख्य उद्देश्य सड़क सुरक्षा से संबंधित मुद्दों की समीक्षा करना और संबंधित मंत्रालयों तथा विभागों से सिफारिशें प्राप्त करना है।

कार्यक्षेत्र: समिति सड़क सुरक्षा से संबंधित नीतियों, कानूनों, और योजनाओं की समीक्षा करती है। यह सड़क दुर्घटनाओं, ट्रैफिक प्रबंधन, और सड़क निर्माण मानकों पर भी ध्यान देती है।

समिति की सदस्यता और प्रमुख सदस्य सड़क सुरक्षा पर स्थायी समिति के सदस्य आमतौर पर विभिन्न दलों के सांसद होते हैं और ये सदस्य संसद के सत्र के दौरान निर्वाचन के आधार पर नियुक्त किए जाते हैं। समिति के प्रमुख सदस्य और अध्यक्ष आमतौर पर प्रमुख दलों के अनुभवी सांसद होते हैं।

अध्यक्ष: अध्यक्ष की नियुक्ति: समिति का अध्यक्ष आमतौर पर सत्तारूढ़ दल से नियुक्त किया जाता है, लेकिन कुछ मामलों में यह विपक्षी दल से भी हो सकता है। अध्यक्ष का चयन संसद के द्वारा किया जाता है और यह व्यक्ति समिति की बैठकों का संचालन करता है और समिति की रिपोर्ट तैयार करता है।

सदस्य: सदस्यों की नियुक्ति: समिति के सदस्य संसद के विभिन्न दलों से होते हैं, जो सड़क सुरक्षा पर विचार-विमर्श और सिफारिशों के लिए चुने जाते हैं। सदस्यों का चयन आमतौर पर उनके अनुभव, विशेषज्ञता और संबंधित मुद्दों के प्रति उनकी जागरूकता पर आधारित होता है।

समिति के कार्य और जिम्मेदारियाँ: सड़क सुरक्षा कानूनों की समीक्षा: मौजूदा सड़क सुरक्षा कानूनों और नीतियों की समीक्षा करना और सुधार के लिए सिफारिशें प्रस्तुत करना। **आवश्यक सुधारों की सिफारिशें:** सड़क दुर्घटनाओं और ट्रैफिक प्रबंधन में सुधार के लिए उपाय सुझाना। **जनता की समस्याओं की सुनवाई:** सड़क सुरक्षा से संबंधित जनता की शिकायतों और सुझावों की समीक्षा करना। **अनुसंधान और रिपोर्ट तैयार करना:** सड़क सुरक्षा से संबंधित अनुसंधान करना और उसकी रिपोर्ट संसद में प्रस्तुत करना।

सड़क सुरक्षा पर संसद की समितियाँ सड़क दुर्घटनाओं में कमी लाने, सड़क सुरक्षा मानकों को सुधारने, और ट्रैफिक नियमों के पालन को बढ़ावा देने के लिए महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं।

समिति की विशिष्ट जानकारी, सदस्यता और अध्यक्ष का विवरण समय-समय पर संसद की वेबसाइट या संबंधित सरकारी प्रकाशनों पर उपलब्ध रहता है।

दिल्ली की सड़कों पर कब से दौड़ेगी मोहल्ला बसें, केजरीवाल सरकार ने दिया बड़ा अपडेट

दिल्ली में लास्ट-माइल कनेक्टिविटी को बेहतर बनाने के लिए जल्द ही सड़कों पर छोटी इलेक्ट्रिक बसें उतरने वाली हैं। जिसे मोहल्ला बस नाम दिया गया है है। हालांकि अभी दिल्ली के लोगों को इसके लिए थोड़ा इंतजार करना होगा। इन बसों की पार्किंग और रखरखाव के लिए 16 डिपो स्टेशन बनाए गए हैं। दिल्ली सरकार ने 2025 तक 2080 बसों को उतारने का लक्ष्य रखा है।

नई दिल्ली। दिल्ली के निवासियों को मोहल्ला बसों में चढ़ने के लिए थोड़ा और इंतजार करना पड़ सकता है क्योंकि परिवहन विभाग अभी भी मार्गों को अंतिम रूप देने पर काम कर रहा है और अभी तक बसें नहीं आ सकी हैं।

अधिकारियों के मुताबिक दिल्ली परिवहन निगम और दिल्ली इंटीग्रेटेड मल्टी-मोडल ट्रांजिट सिस्टम (डीआईएमटीएस) जल्द ही दो नए मार्गों इंडियन एयरलाइन कालोनी/प्रिया सिनेमा से लोक कल्याण मार्ग मेट्रो स्टेशन और लोक कल्याण मार्ग से वसंत विहार तक ट्रायल रन शुरू करेंगे।

अक्षरधाम मेट्रो स्टेशन से मयूर विहार फेज-3 पहले से चल रहा ट्रायल

दो मार्गों प्रधान एन्क्लेव पुस्ता से मजलिस पार्क मेट्रो स्टेशन और अक्षरधाम मेट्रो स्टेशन से मयूर विहार फेज-3 पेपर मार्केट पर परीक्षण पहले से ही चल रहा है। डीटीसी और डीआइएमटीएस अधिक जानकारी प्राप्त करने के लिए दो नए मार्गों पर ट्रायल रन शुरू करेंगे।

इन बसों की पार्किंग और रखरखाव के लिए 16 डिपो बनाए गए हैं। इन डिपो में चार्जिंग बुनियादी ढांचे को स्थापित करने का काम चल रहा है और आगे बढ़ाया जाएगा। परिवहन विभाग के एक अधिकारी ने कहा कि कंपनी से बसों के आने में देरी हुई है।

बसों की लॉन्चिंग सितंबर के मध्य तक संभव

विभाग इन बसों को अगस्त के अंत तक लांच करने का लक्ष्य बना रहा था, लेकिन अब बसों की लांचिंग सितंबर के मध्य तक हो सकती है। एआई की मदद से इन बसों के रूटों को अंतिम रूप देने का काम हो रहा है। एक अन्य अधिकारी ने कहा कि मार्गों के बारे में चर्चा करने के लिए अगले सप्ताह आइआईटी-दिल्ली के साथ एक बैठक आयोजित की जाएगी जिसके बाद मार्गों को अंतिम रूप देने पर दिल्ली के परिवहन मंत्री कैलाश गहलोत के साथ एक और बैठक होगी। ये बसें छह बैटरी पैक से सुसज्जित हैं, जिनकी कुल क्षमता 196 किलोवाट है।

छह सीटें गुलाबी रंग की हैं, जो महिलाओं के लिए आरक्षित

जो 45 मिनट की चार्जिंग के साथ 200 किमी से अधिक की दूरी तय करती हैं। नौ मीटर लंबी बसों में 23 यात्री सीटें हैं और खड़े होने की क्षमता 13 है। छह सीटें गुलाबी रंग की हैं, जो उन्हें महिला यात्रियों के लिए आरक्षित हैं।

इस योजना के तहत 2,080 बसें होंगी और सरकार की योजना इन सभी को 2025 तक शुरू करने की है। इनमें से 1,040 डीटीसी द्वारा और बाकी डीआईएमटीएस द्वारा संचालित की जाएंगी।

टेंपल्स ऑफ लिबरलाइजेशन एंड वेलफेयर एलाइड ट्रस्ट (पंजीकृत)

TOLWA

website : www.tolwa.in
Email : tolwadelhi@gmail.com
bathlasanjaybathla@gmail.com

रजिस्टर्ड अंडर सैक्शन 60 विद रजिस्ट्रेशन नंबर (152/02-03-2020), एमएसएमई रजिस्ट्रेशन नंबर उद्यम -डीएल - 0026470, नीति आयोग रजिस्ट्रेशन नंबर वीओ/एनजीओ/0303274/25-01-2022 दर्पण

रजिस्टर्ड कार्यालय :- 3, प्रियदर्शिनी अपार्टमेंट, ए -4 पश्चिम विहार, न्यू दिल्ली 110063
कॉरपोरेट कार्यालय :- 529, समयपुर, मेंन बवाना रोड, नियर बैंक ऑफ़ बड़ौदा दिल्ली 110042

राष्ट्र हित | उद्योग हित | मजदूर हित

दिल्ली परिवहन मजदूर संघ (मान्यता प्राप्त)
के नेतृत्व में
दि.: 28/08/2024
विशाल धरना प्रदर्शन

- डी.टी.सी के बेडे में नई बसें शीघ्र खरीदी जाए।
- सभी अनुबन्धित चालकों/संवाहकों को स्थायी किया जाए तथा स्थायी होने तक स्थायी चालकों/संवाहकों के मूल वेतन के बरावर वेतन दिया जाए।
- कार्मिक अनुभाग द्वारा शीघ्र स्थानान्तरण नीती बनायी जाए किसी भी कर्मचारी को उसके निवास से अधिकतम 12-15 किमी. के अन्दर स्थित डिपो में ही स्थानान्तरित किया जाए।
- सभी सेवारत/सेवानिवृत कर्मचारियों/अधिकारियों पर कैशलैस मेडिकल योजना लागू की जाए।
- अनुकम्पा के आधार पर भर्ती संवाहकों को स्थायी किया जाए तथा विक्लांग संवाहकों का उत्पीडन बंद किया जाए, पार्ट टाइम सफाई कर्मचारियों को फुल टाइम किया जाए।
- दिल्ली परिवहन मजदूर संघ को मुख्यालय में कार्यालय आवंटित किया जाए, आदि।

मुख्य वक्ता- डॉ. दीपेंद्र चाहर (महामंत्री) भारतीय मजदूर संघ (दिल्ली प्रदेश)
विशेष उपस्थिति : श्रीमती कमलजीत सहरावत (सांसद) दक्षिण पश्चिम क्षेत्र

कैलाश चन्द मलिक (अध्यक्ष) | विनोद मलिक (कार्यकारी अध्यक्ष) | विजेन्द्र सिंह (महामंत्री)

दिल्ली परिवहन मजदूर संघ (मान्यता प्राप्त)
सम्बद्ध - भारतीय मजदूर संघ (दिल्ली प्रदेश) एवं भारतीय परिवहन मजदूर महासंघ

30 अगस्त को मनाया जाएगा बछ बारस, पुत्र की दीर्घायु के लिए महिलाएं करती हैं व्रत

भविष्यवक्ता और कुण्डली विश्लेषक डा. अनीष व्यास ने बताया कि पूजा के लिए भैंस का दूध और दही, भीगा हुआ चना और मोठ ले। मोठ-बाजरे में घी और चीनी मिलाये ।गाय के रोली का टीका लगाकर चावल के स्थान पर बाजरा लगाये।

बछ बारस 30 अगस्त 2024 को मनाया जाएगा। इस दिन गौमाता की बछड़े सहित पूजा की जाती है। माताएं अपने पुत्रों को तिलक लगाकर तलाई फोड़ने के बाद लड्डू का प्रसाद देती है यानि पुत्रवान महिलाये अपने पुत्र की मंगल कामना के लिए व्रत रखती है और पूजा करती है। पाल बालाजी ज्योतिष संस्थान जयपुर-जोधपुर के निदेशक ज्योतिषाचार्य अनीष व्यास ने बताया कि इस दिन गेंहू से बने हुए पकवान और चाकू से कटी हुई सब्जी नही खाये जाते हैं। बाजरे या ज्वार का सोगरा और अंकुरित अनाज की कढ़ी व सूखी सब्जी बनाई जाती है। महिलाओं द्वारा सुबह गौमाता की विधिवत पूजा अर्चना करने के बाद घरों या सामूहिक रूप से बनी मिट्टी व गोबर से बनी तलैया को अच्छी तरह सजाकर उसमें कच्चा दूध और पानी भरकर उसकी कुमकुम, मौली, धूप दीप प्रज्वलित कर पूजा करते हैं और बछबारस की कहानी सुनी जाती है। महिलाओं द्वारा सुबह गौमाता की विधिवत पूजा अर्चना करने के बाद घरों या सामूहिक रूप से बनी मिट्टी व गोबर से बनी तलैया को अच्छी तरह सजाकर उसमें कच्चा दूध और पानी भरकर उसकी कुंकुम, मौली, धूप दीप प्रज्वलित कर पूजा करते हैं और बछबारस की कहानी सुनी जाती है।

ज्योतिषाचार्य डा. अनीष व्यास ने बताया कि बछ बारस प्रतिवर्ष जन्माष्टमी के चार दिन पश्चात भाद्रपद महीने के कृष्ण पक्ष की द्वादशी के दिन 30 अगस्त को मनाया जाता है इसलिए इस गोवत्स द्वादशी भी कहते है। भगवान कृष्ण के गाय और बछड़ो से बड़ा प्रेम था इसलिए इस त्यौहार को मनाया जाता है और ऐसा माना जाता है की बछ बारस के दिन गाय और बछड़ो की पूजा करने से भगवान कृष्ण सहित गाय में निवास करने वाले सैकड़ो देवताओ का आशीर्वाद मिलता है जिससे घर में खुशहाली और सम्पन्नता आती है। बछबारस का पर्व राजस्थानी महिलाओं में ज्यादा लोकप्रिय है।

बछबारस पूजन की सामग्री और पूजा विधि

भविष्यवक्ता और कुण्डली विश्लेषक डा. अनीष व्यास ने बताया कि पूजा के लिए भैंस का दूध और दही, भीगा हुआ चना और मोठ ले। मोठ-बाजरे में घी और चीनी मिलाये ।गाय के रोली का टीका लगाकर चावल के स्थान पर बाजरा लगाये। बायने के लिए एक कटोरी में भीगा हुआ चना , मोठ ,बाजरा और रुपया रखे। इस दिन बछड़े वाले गाय की पूजा की जाती है यदि गाय की पूजा नही कर सकते तो एक पाटे पर मिटटी से बछबारस बनाते है और उसके बीच में एक गोल मिटटी की बावडी बनाते है। फिर उसको थोडा दूध दही से भर देते है। फिर सब चीजे चढाकर पूजा करते है। इसके बाद रोली ,दक्षिण चढाते है। स्वयम को तिलक

निकालते है। हाथ में मोठ और बाजरे के दाने को लेकर कहानी सुनाते है। बछबारस के चित्र की पूजा भी की जा सकती है।

भविष्यवक्ता और कुण्डली विश्लेषक डा. अनीष व्यास ने बताया कि बहुत समय पहले की बात है एक गाँव में एक साहूकार अपने सात बेटो और पोतो के साथ रहता था। उस साहूकार ने गाँव में एक तालाब बनवाया था लेकिन बारह सालो तक वो तालाब नही भरा था। तालाब नही भरने का कारण पूछने के लिए उसने पंडितो को बुलाया। पंडितो ने कहा कि इसमें पानी तभी भरेगा जब तुम या तो अपने बड़े बेटे या अपने बड़े पोते की बलि दोगे। तब साहूकार ने अपने बड़ी बहु को तो पीहर भेज दिया और पीछे से अपने बड़े पोते की बलि दे दी। इतने में गरजते बरसते बादल आये और तालाब पूरा भर गया।

इसके बाद बछबारस आयी और सभी ने कहा की "अपना तालाब पूरा भर गया है इसकी पूजा करने चलो" ।साहूकार अपने परिवार के साथ तालाब की पूजा करने गया ।वह दासी से बोल गया था की गेहुला को पका लेना ।गेहुला से तात्पर्य गेहू के धान से है। दासी समझ नही पाई। दरअसल गेहुला गाय के बछड़े का नाम था। उसने गेहुला को ही पका लिया। बड़े बेटे की पत्नी भी पीहर से तालाब पूजने आ गयी थी। तालाब पूजने के बाद वह अपने बच्चो से प्यार करने लगी तभी उसने बड़े बेटे के बारे में पुछा।

तभी तालाब में से मिटटी में लिपटा हुआ उसका बड़ा बेटा निकला और बोला की माँ मुझे भी तो प्यार करो ।तब सास बहु एक दुसरे को देखने लगी। सास ने बहु को बलि देने वाली सारी बात बता दी। फिर सास ने कहा की बछबारस माता ने हमारी लाज रख ली और हमारा बच्चा वापस दे दिया। तालाब की पूजा करने के बाद जब वह वापस घर लौटे तो उन्होंने देखा बछड़ा नही था। साहूकार ने दासी से पूछा की बछड़ा कहा है तो दासी ने कहा कि "आपने ही तो उसे पकाने को कहा था"।

साहूकार ने कहा की "एक पाप तो अभी उतरा ही है तुमने दूसरा पाप कर दिया "। साहूकार ने पका हुआ बछड़ा मिटटी में दबा दिया। शाम को गाय वापस लौटी तो वह अपने बछड़े को ढूंढने लगी और फिर मिटटी खोदने लगी। तभी मिटटी में से बछड़ा निकल गया। साहूकार को पता चला तो वह भी बछड़े को देखने गया। उसने देखा कि बछडा गाय का दूध पीने में व्यस्त था। तब साहूकार ने पुरे गाँव में यह बात फैलाई कि हर बेटे की माँ को बछबारस का व्रत करना चाहिए और तालाब पूजना चाहिए। हे बछबारस माता ! जैसा साहूकार की बहु को दिया वैसा हमे भी देना ।कहानी कहते सुनते ही सभी की मनोकामना पूर्ण करना। इसके बाद गणेश जी की कहानी कहे।

बायना निकालना

भविष्यवक्ता और कुण्डली विश्लेषक डा. अनीष व्यास ने बताया कि एक कटोरी मोंठ ,बाजरा रखकर उसके उपर रुपया रख देवे। इनको रोली और चावल से छींटा देवे ।दोनों हाथ जोडकर कटोरी को पल्ले से ढककर चार बार कटोरी के उपर हाथ फेर ले। फिर स्वयम के तिलक निकाले। यह बायना सांस को पाँव छुकर देवे। बछबारस के दिन बेटे की माँ बाजरे की ठंडी रोटी खाती है। इस दिन भैंस का दूध ,बेसन ,मोंठ आदि खा सकते है। इस दिन गाय का दूध, दही, गेहूं और चावल नही खाया जाता है।

उद्यापन

भविष्यवक्ता और कुण्डली विश्लेषक डा. अनीष व्यास ने बताया कि जिस साल लड़का हो या जिस साल लडके की शादी हो उस साल बछबारस का उद्यापन किया जाता है। सारी पूजा हर वर्ष की तरह करे। सिर्फ थाली में सवा सेर भीगे मोठ बाजरा की तरह कुद्दी करे। दो दो मुट्ठी मोई का (बाजरे की आटे में घी ,चीनी मिलाकर पानी में गूँथ ले) और दो दो टुकड़े खीरे के तेरह कुडी पर रखे। इसके उपर एक तीयल (दो साडीया और ब्लाउज पीस) और रुपया रखकर हाथ फेरकर सास को छुकर दे। इस तरह बछबारस का उद्यापन पूरा होता है।

महत्व

भविष्यवक्ता और कुण्डली विश्लेषक डा. अनीष व्यास ने बताया कि यह पर्व पुत्र की मंगल-कामना के लिए किया जाता है। इस पर्व पर गीली मिट्टी की गाय, बछड़ा, बाघ तथा बाघिन की मूर्तियां बनाकर पाट पर रखी जाती हैं तब उनकी विधिवत पूजा की जाती है। भारतीय धार्मिक पुराणों में गौमाता में समस्त तीर्थ होने की बात कहीं गई है। पूज्यनीय गौमाता हमारी ऐसी मां है, जिसकी बराबरी न कोई देवी-देवता कर सकता है और न कोई तीर्थ. गौमाता के दर्शन मात्र से ऐसा पुण्य प्राप्त होता है, जो बड़े-बड़े यज्ञ, दान आदि कर्मों से भी नहीं प्राप्त हो सकता। ऐसी मान्यता है कि सभी देवी-देवताओं एवं पितरों को एक साथ खुश करना है तो गौभक्ति-गौसेवा से बढ़कर कोई अनुष्ठान नहीं है। गौ माता को बस एक ग्रास खिला दो, तो वह सभी देवी-देवताओं तक अपने आप ही पहुंच जाता है। भविष्य पुराण के अनुसार गौमाता कि पृष्ठदेश में ब्रह्म का वास है, गले में विष्णु का, मुख में रुद्र का, मध्य में समस्त देवताओं और रोमकूपों में महर्षिगण, पूंछ में अनंत नाग, खूरों में समस्त पर्वत, गौमूत्र में गंगादि नदियां, गौमय में लक्ष्मी और नेत्रों में सूर्य-चन्द्र विराजित हैं इसीलिए बछ बारस या गोवत्स द्वादशी के दिन महिलाएं अपने बेटे की सलामती, लंबी उम्र और परिवार की खुशहाली के लिए यह पर्व मनाती है। इस दिन घरों में विशेष कर बाजरे की रोटी जिसे सोगरा भी कहा जाता है और अंकुरित अनाज की सब्जी बनाई जाती है. इस दिन गाय की दूध की जगह भैंस या बकरी के दूध का उपयोग किया जाता है।

अगर भारत में टेलीग्राम बैन हो गया तो इस्तेमाल कर सकते हैं ये 5 बेस्ट अल्टरनेटिव विकल्प, जानें कौन-कौन से हैं?

पिछले कुछ सालों से भारत में टेलीग्राम का इस्तेमाल तेजी से बढ़ा है। पूरे विश्व के साथ-साथ भारतीय यूजर्स को भी टेलीग्राम ऐप के फीचर्स काफी पसंद हैं। इसकी सुरक्षा विशेषताओं और सुविधाजनक इस्तेमाल के कारण, कई लोगों ने इसे अपने प्राइमरी मैसेंजर के रूप में अपना लिया है।

इन दिनों टेलीग्राम काफी चर्चा में है, वजह टेलीग्राम के सीईओ को गिरफ्तार कर लिया गया है। वहीं अब ऐसी खबरें आ रही हैं कि टेलीग्राम भारत में भी बंद हो सकता है। हालांकि, पिछले कुछ सालों से भारत में टेलीग्राम का इस्तेमाल तेजी से बढ़ा है। पूरे विश्व के साथ-साथ भारतीय यूजर्स को भी टेलीग्राम ऐप के फीचर्स काफी पसंद हैं। इसकी सुरक्षा विशेषताओं और सुविधाजनक इस्तेमाल के कारण, कई लोगों ने इसे अपने प्राइमरी मैसेंजर के रूप में अपना लिया है।

भारत सरकार टेलीग्राम की मौजूदगी और उनकी सुरक्षा नीतियों की जांच कर रही है। अगर टेलीग्राम ने भारत की राष्ट्रीय सुरक्षा के साथ कोई भी गलत नीतियों का पालन किया होगा तो उसे देश में प्रतिबिंधित कर दिया जाएगा। वहीं अगर आप भी टेलीग्राम यूजर्स हैं और बैन होने के बाद आपका क्या होगा... तो टेलीग्राम के विकल्प के तौर पर भारत में मौजूद इन 5 ऐप्स के बारे में सोच सकते हैं।

1. WhatsApp- व्हाट्सएप भारत ही नहीं पूरी दुनिया में सबसे लोकप्रिय मैसेंजर ऐप्स में से एक है। जो भआरत में व्यापक रूप से इस्तेमाल किया जाता है। हालांकि, इसकी सिक्योरिटी फीचर्स टेलीग्राम की तुलना में कम मजबूत हैं लेकिन फिर भी लोगों के लिए ये एक विश्वसनीय विकल्प है। व्हाट्सएप में एंड-टू एंड एनक्रिप्शन है, जो आपके मैसेजों को सुरक्षित रखता है। इसके अलावा, व्हाट्सएप में ग्रुप चैट, वॉइस और वीडियो कॉल, स्टेटस अपडेट जैसी कई सुविधाएं हैं।

2.Signal- सिग्नल एक ओपन सोर्स मैसेंजर ऐप है, जो अपनी स्ट्रॉग सिक्योरिटी फीचर्स के लिए जाना जाता है। ये एक पूरी तरह से एनक्रिप्टेड मैसेंजर है, जो आपके मैसेजों को सुरक्षित रखता है। सिग्नल में ग्रुप चैट, वॉइस और वीडियो कॉल और स्टेटस अपडेट जैसी सुविधाएं भी हैं। इसके अलावा, सिग्नल में एक ऑटो डिलीट फीचर भी है, जो आपके मैसेजों को एक निश्चित समय के बाद ऑटोमैटिकली हटा देता है।

3. Mattermost- मैटरोस्ट एक व्यावसायकि मैसेंजर ऐप है जो अपनी हाई-लेवल सिक्योरिटी और अनुकूलन क्षमताओं के लिए जाना जाता है। ये पूरी तरह से एनक्रिप्टेड मैसेंजर, जो आपके मैसेजों को सुरक्षित रखता है। मैटरमोस्ट में ग्रुप चैट, वॉइस और वीडियो कॉल और स्टेटस अपडेट जैसी सुविधाएं भी हैं। इसके अलावा मैटरमोस्ट में एक प्रशासक नियंत्रण पैनल भी है जो आपको ऐप की सेटिंग्स को कस्टमाइज़ करने की परमिशन देता है।

4. ThickClient- थिकक्लाइंट एक सुरक्षित और निजी मैसेंजर ऐप है, जो अपनी स्ट्रॉग सिक्योरिटी फीचर्स के लिए जाना जाता है। ये एक पूरी तरह से एनक्रिप्टेड मैसेंजर है, जो आपके मैसेजों को सुरक्षित रखता है। थिकक्लाइंट में ग्रुप चैट, वॉइस और वीडियो कॉल और स्टेटस अपडेट जैसी सुविधाएं भी हैं। इसके अलावा, थिकक्लाइंट में एक ऑटो डिलीट फीचर है जो आपके मैसेजों को एक निश्चित समय के बाद ऑटोमैटिकली हटा देता है।

5.Microsoft Teams- माइक्रोसॉफ्ट टीम्स सिर्फ एक मैसेंजिंग ऐप नहीं, बल्कि उससे भी कहीं ज्यादा है। इसके माध्यम से आप कई तरीकों से फायदे उठा सकते हैं। ये ऐप एक व्यापक कॉलेबरेशन प्लेटफॉर्म है जो पूरे माइक्रोसॉफ्ट 365 सूट के साथ एकीकृत होता है। टीम एंड टू एंड एनक्रिप्शन सिक्योरिटी प्रदान करता है। जिससे ये व्यवसायों और शैक्षणिक संस्थानों के लिए एक सुरक्षित विकल्प बन जाता है।

जिद्दी डार्क सर्कल्स और झुर्रियां होगी दूर, बस घर पर बनाएं इमली का फेस पैक

आजकल ज्यादातर लोगों के चेहरे पर झुर्रियां और डार्क सर्कल्स देखने को मिलते हैं, जिस वजह से चेहरे की खूबसूरती कहीं गायब हो जाती है। इमली का ये फेस पैक चेहरे को नेचुरल ग्लो देने के साथ ही झुर्रियां और डार्क सर्कल्स की समस्या को खत्म कर देगा। आइए जानते हैं इसे कैसे बनाएं।

खराब लाइफस्टाइल और गलत खानपान के चलते लोगों के समय से पहले चेहरे पर झुर्रियां दिखाई देती। इसके साथ ही डार्क सर्कल्स और दाग-धब्बों ने चेहरे की चमक को कहीं गायब ही कर दिया है। लेकिन आज हम आपको इस लेख में खूबसूरती निखारने के लिए सबसे बेहतरीन इमली फेस पैक के बारे में बताने जा रहे हैं, जिसके इस्तेमाल से झुर्रियां और आंखों के नीचे काले घेरे सब मिनटों में गायब हो जाएंगे। आइए जानते हैं इमली फेस पैक बनाने की विधि।

इमली और मुल्तानी मिट्टी का फेस पैक

अगर आप चेहरे की टैनिंग, झुर्रियां और दाग-धब्बों से परेशान हैं तो आप इस पैक को बनाने के लिए सबसे पहले आप इमली के गूदे के साथ 1 चम्मच मुल्तानी मिट्टी, 1 चम्मच शहद और एक चम्मच नींबू का रस मिलाकर सभी चीजों का पेस्ट बनाकर चेहरे पर 10-15 मिनट तक लगा लें। इसके बाद जब यह सूख जाए तब हल्के हाथ से मसाज करते हुए इसे धो लें। इमली का यह जादुई फेस पैक झुर्रियां, दाग-धब्बों और डार्क सर्कल्स को दूर कर देगा।

इमली और सूजी का फेस पैक

अगर आप अपनी बढ़ती उम्र कम करना चाहते हैं तो इस फेस पैक का प्रयोग जरुर करें। सबसे पहले आप गर्म पानी में इमली डालें ताकि इमली का गूदा सॉफ्ट हो जाए। इसके बाद इमली के गूदे में 1 चम्मच सूजी, 1 चम्मच शहद , 1 चम्मच बेसन और गुलाब जल मिलाकर पेस्ट बना लें। इस पैक को आप चेहरे पर 20 मिनट तक लगाएं रखें। इसके बाद चेहरे को धो लें और फिर मॉश्चराइजर लगा लें।

प्राकृतिक सौंदर्य और धार्मिकता का संगम है चित्रकूट

सती अंजनी देवी का मन्दिर चित्रकूट का एक प्रमुख धार्मिक स्थल है। इसे अंजनी माता का मन्दिर भी कहा जाता है। यह मंदिर भगवान हनुमान की माता के प्रति श्रद्धा अर्पित करता है और यहाँ पर भक्त नियमित रूप से पूजा अर्चना करने आते हैं।

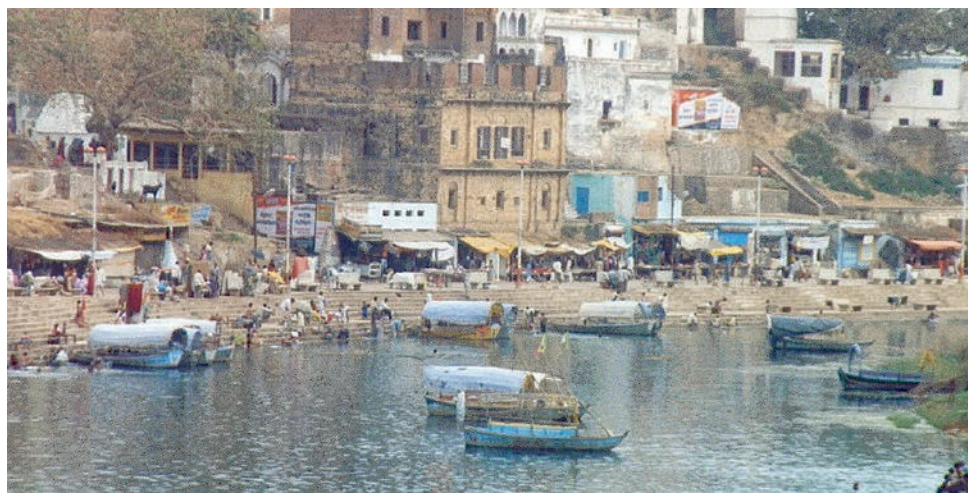

चित्रकूट, मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश की सीमा पर स्थित एक प्राचीन और पवित्र स्थल है। यह स्थल धार्मिक, ऐतिहासिक और प्राकृतिक दृष्टि से अत्यंत महत्वपूर्ण है। चित्रकूट का नाम भारतीय धार्मिक ग्रंथों में प्रमुख स्थान पर है और यहाँ की हरियाली, झरने और धार्मिक स्थल इसे पर्यटकों के लिए एक आदर्श गंतव्य बनाते हैं। आइए जानते हैं चित्रकूट के प्रमुख पर्यटन स्थलों के बारे में:

1. रामघाट

रामघाट, चित्रकूट का सबसे महत्वपूर्ण धार्मिक स्थल है। यह घाट यमुनापार के तट पर स्थित है और यहाँ पर हर वर्ष लाखों श्रद्धालु स्नान करने आते हैं। इस घाट पर भगवान राम और माता सीता के साथ बिताए गए वर्षों की कथाएँ प्रचलित हैं। यहाँ की धार्मिक माहौल और सुंदरता एक अद्वितीय अनुभव प्रदान करती है।

2. कश्मीरी ताल

कश्मीरी ताल एक प्राकृतिक झील है जो चित्रकूट की खूबसूरत वादियों में स्थित है। यह ताल पर्यटकों के लिए एक शांत और सौम्य वातावरण प्रदान करती है। यहाँ पर नाव की सवारी करके आप झील के शांत पानी का आनंद ले सकते हैं और आसपास की हरी-भरी हरियाली का मजा ले सकते हैं।

3. चित्रकूट के झरने

चित्रकूट में कई सुंदर झरने हैं जो प्राकृतिक सौंदर्य और शांति का अनुभव कराते हैं:

रामकुण्ड झरना: यह झरना भगवान राम के नाम पर रखा गया है और यहाँ पर जल की धारा एक अद्वितीय दृश्य प्रस्तुत करती है।

जानकी कुंड: यह झरना भी धार्मिक महत्व रखता है और यहाँ पर श्रद्धालु जल स्नान करने आते हैं।

4. सती अंजनी देवी का मन्दिर

सती अंजनी देवी का मन्दिर चित्रकूट का एक प्रमुख धार्मिक स्थल है। इसे अंजनी माता का मन्दिर भी कहा जाता है। यह मंदिर भगवान हनुमान की माता के प्रति श्रद्धा अर्पित करता है और यहाँ पर भक्त नियमित रूप से पूजा अर्चना करने आते हैं। मंदिर की स्थापत्य कला और धार्मिक महत्व इसे विशेष बनाते हैं।

5. भगवान राम के वनवास स्थल

चित्रकूट, भगवान राम के वनवास के दौरान एक महत्वपूर्ण स्थल रहा है। यहाँ पर कई स्थान हैं जिनसे जुड़ी हुई कथाएँ और धार्मिक महत्व हैं। इन स्थलों की यात्रा करते हुए आप रामायण की कथाओं और भगवान राम के वनवास की घटनाओं को महसूस कर सकते हैं।

6. भरत मिलाप मन्दिर

भरत मिलाप मन्दिर, चित्रकूट का एक ऐतिहासिक और धार्मिक स्थल है। यह मंदिर भगवान राम और उनके भाई भरत के मिलन की स्मृति में बनाया गया था। मंदिर की वास्तुकला और धार्मिक वातावरण यहाँ पर आने वाले भक्तों को एक अद्वितीय अनुभव प्रदान करते हैं।

7. गुह्येश्वरी देवी का मन्दिर

गुह्येश्वरी देवी का मन्दिर चित्रकूट के प्रमुख धार्मिक स्थलों में से एक है। यह मन्दिर देवी दुर्गा की एक रूप में पूजा जाता है और यहाँ की शांतिपूर्ण और दिव्य वातावरण भक्तों को एक अद्वितीय आध्यात्मिक अनुभव प्रदान करती है।

8. सप्तऋषि आश्रम

सप्तऋषि आश्रम, चित्रकूट का एक महत्वपूर्ण आश्रम है जहाँ पर प्राचीन ऋषियों और साधुओं ने तपस्या की थी। यहाँ की साधना और ध्यान की विधियाँ पर्यटकों को एक गहरा आध्यात्मिक अनुभव प्रदान करती हैं।

निष्कर्ष

चित्रकूट, धार्मिक और प्राकृतिक सौंदर्य का एक अनूठा संगम है। यहाँ की धार्मिक स्थल, प्राकृतिक झरने, और शांतिपूर्ण वातावरण आपको एक अविस्मरणीय अनुभव प्रदान करेंगे। चाहे आप आध्यात्मिक शांति की खोज में हों या प्राकृतिक सौंदर्य का आनंद लेना चाहते हों, चित्रकूट एक आदर्श गंतव्य साबित होगा।

फेक एसएमएस अलर्ट! पीआईबी ने न्यू इंडिया पोस्ट पैन कार्ड घोटाले की चेतावनी दी, जानें प्रामाणिकता जांचने के लिए ये आसान टिप्स

परिवहन विशेष

हाल ही में पीआईबी ने इंडिया पोस्ट के संदेशों के रूप में आने वाले एसएमएस घोटालों के बारे में चेतावनी दी है, जिसमें अकाउंट ब्लॉक होने से बचने के लिए तत्काल पैन कार्ड अपडेट करने का आग्रह किया गया है।

आज के समय में साइबर ठग फर्जी संदेश भेजकर धोखाधड़ी कर रहे हैं। ऐसे में हमे सावधान रहने की जरुरत है। अभी हाल ही में प्रेस सूचना ब्यूरो (पीआईबी) ने एसएमएस घोटालों में आई तेजी के बारे में नागरिकों को सचेत किया है, जो इंडिया पोस्ट के संदेशों के रूप में लोगों को धोखा देने का प्रयास करते हैं। इन धोखाधड़ी वाले संदेशों में दावा किया जाता है कि प्राप्तकर्ताओं को अपने इंडिया पोस्ट पेमेंट्स बैंक खातों को ब्लॉक होने से बचाने के लिए अपने पैन कार्ड विवरण को तत्काल अपडेट करना चाहिए, जिससे अनजान पीड़ित संभावित वित्तीय संकट में फंस सकते हैं।

पीआईबी ने फैक्ट चेक एक्स पर जारी किया

एक्स पर शेयर किए गए एक बयान में, पीआईबी फैक्ट चेक टीम ने पुष्टि की कि ये एसएमएस संदेश पूरी तरह से धोखाधड़ी वाले हैं। उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि इंडिया पोस्ट पैन कार्ड अपडेट के बारे में ऐसी सूचनाएं नहीं भेजता है और लोगों से इस तरह की भ्रामक प्रथाओं के प्रति सतर्क रहने का आग्रह किया।

आम तौर पर धोखाधड़ी वाला संदेश कुछ इस तरह का हो सकता है: रप्रिय उपयोगकर्ता, आपका इंडिया पोस्ट पेमेंट्स बैंक खाता आज ब्लॉक कर दिया गया है। कृपया अपना पैन कार्ड तुरंत अपडेट करें। यहां क्लिक करें: https://surl.li/iccpf." यह संदेश तात्कालिकता की भावना पैदा करने के लिए बनाया गया है, ताकि प्राप्तकर्ता लिंक पर क्लिक करके संभवतः संवेदनशील जानकारी का खुलासा कर सकें।

धोखाधड़ी के शिकार से कैसे बचें

अप्रत्याशित संदेशों के प्रति सावधानी बरतें

यदि आपको किसी अज्ञात प्रेषक या किसी ऐसे संगठन से संदेश प्राप्त होता है, जिसके साथ आप आमतौर पर संपर्क नहीं करते हैं, तो इसे संदेह की दृष्टि से देखें।

लिंक पर क्लिक करने से बचें

ध्यान रहे कि अप्रत्याशित या संदिग्ध संदेशों में दिए गए लिंक अक्सर फिशिंग प्रयासों का हिस्सा होते हैं जिनका उद्देश्य व्यक्तिगत डेटा प्राप्त करना होता है।

आधिकारिक चैनलों के माध्यम से जानकारी सत्यापित करें

यदि आपको कोई संदेश प्राप्त होता है जो किसी वैध कंपनी से आया हुआ प्रतीत होता है, तो उसकी प्रामाणिकता की पुष्टि करने के लिए सीधे कंपनी की आधिकारिक वेबसाइट या फोन नंबर के माध्यम से संपर्क करें।

एसएमएस के माध्यम से व्यक्तिगत जानकारी साझा न करें

बैंक खाता संख्या या पासवर्ड जैसी संवेदनशील जानकारी कभी भी किसी टेक्स्ट संदेश के जवाब में साझा नहीं की जानी चाहिए।

संदिग्ध संदेशों की रिपोर्ट करें

यदि आपको कोई धोखाधड़ी वाला एसएमएस मिलता है, तो इसकी रिपोर्ट अपने मोबाइल सेवा प्रदाता और उपयुक्त प्राधिकारियों को करें।

अपना डिवाइस अपडेट करें

अपने डिवाइस को नियमित रूप से अपडेट करना सुनिश्चित करें।

भारत जोड़ो पदयात्रा एक समीक्षा का विमोचन किया

सुषमा रानी

नई दिल्ली। दिल्ली प्रदेश कांग्रेस कमेटी कार्यालय में आज आज मशहूर लेखक व विचारक डॉ के एस भारद्वाज द्वारा लिखी गई व अद्रिक पब्लिकेशन प्राइवेट लिमिटेड द्वारा पब्लिश पुस्तक भारत जोड़ो पदयात्रा एक समीक्षा का विमोचन दिल्ली प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष देवेंद्र यादव ने किया।

विमोचन के मौके पर अनिल भारद्वाज मिडिया इंचार्ज, भीष्म शर्मा, सुरेंद्र कुमार, वीर सिंह धींगान, अश्वनी भारद्वाज पत्रकार, अरविंद सिंह, डॉ एस पी सिंह, जुबेर अहमद, करावल नगर जिलाध्यक्ष आदेश भारद्वाज के साथ कई अन्य महत्वपूर्ण लोग उपस्थित रहे।

पुस्तक के लेखक डॉ के एस भारद्वाज, देवेंद्र यादव, अनिल भारद्वाज, आदेश भारद्वाज ने पुस्तक और भारत जोड़ो यात्रा पर अपने अपने विचार रखते हुए कहा कि अलग-अलग लोगों ने भारत जोड़ो यात्रा पर अपनी अपनी राय रखी, यात्रा की समीक्षाएं की। लेकिन यात्रा को लेकर अपने विचारों को पुस्तक के रूप में संजोकर पेश करना अपने आप में एक बेहतरीन मिसाल है। किसी भी अवसर को लेकर हमारे सबके अलग विचार होते हैं लेकिन एक लेखक के रूप में इस यात्रा के सकारात्मक पहलू, नकारात्मक पहलुओं के अलावा इसका सामाजिक और सामरिक महत्व समझना बहुत बड़ी बात है।

उन्होंने कहा कि यह पुस्तक राहुल गांधी के उन प्रयासों का दस्तावेज है जो इस यात्रा के माध्यम से राहुल गांधी ने सत्ताधारी लोगों के सामने पेश किए। भारतीय राजनीति के पुनर्जागरण में जुटे राहुल गांधी ने भारत जोड़ो यात्रा के माध्यम से ना सिर्फ सांप्रदायिकता को चुनौती दी बल्कि इस लोकतंत्र को घृणा, नफरत और तानाशाही से बचाने के सत्याग्रह का आगाज भी किया। यह पुस्तक उन मिथकों पर भी करारी चोट करती है जो दुष्प्रचार राहुल गांधी के खिलाफ किए गए। कैसे अकेले पड़ते जा रहे नागरिकों से यात्रा के दौरान राहुल गांधी मिलते रहे, उनके दुखों, उनकी परेशानियों, उनके अनुभवों को आत्मसात करते रहे। और डॉ के एस भारद्वाज जी द्वारा लिखी यह पुस्तक सही मायने में हमें यह बताती है कि एक नेता और जनता के सीधे संवाद की महत्वता को इस तरह की यात्रा से ही रेखांकित किया जा सकता था।

इस पुस्तक के लिखे जाने तक या भारत जोड़ो यात्रा के दोनों चरण समाप्त हो जाने से यह यात्रा रुकी नहीं है। स्टेशन के कुलियों से मिलना, धान लगाते हुए किसानों के साथ उनके खेत में धान लगाना, कीर्तिनगर के बढ़ईयों से मिलना, रामेश्वर सब्जी वाले से मिलना, रामचेत मोची से मिलना या सुनील टैक्सी वाले से मिलना या जीटीबी नगर लेबर चौक पर रोज काम की तलाश में खड़े रहने वाले मज़दूरों से मिलना या गोपालपुर गाँव में मकान बनाते हुए राजमिस्त्री के साथ ईटो की चिनाई करना इस यात्रा के लघु रूप हैं जो अनवरत चलते रहेंगे और मुझे उम्मीद है कि डॉक्टर के एस भारद्वाज जी की पुस्तकें भी अपनी समीक्षाएं लेकर आती रहेंगी।

16 अगस्त 2024 को पीडब्ल्यूडी विभाग में 7 नए ग्रुप A अधिकारियों की नियुक्ति की गई है : सौरभ भारद्वाज

सुषमा रानी

नई दिल्ली। 27 अगस्त दिल्ली सचिवालय में हुई एक प्रेस वार्ता को संबोधित करते हुए दिल्ली के स्वास्थ्य मंत्री सौरभ भारद्वाज ने कहा कि जब दिल्ली में कोई बड़ा संकट आता है और हम सबूत के आधार पर यह आरोप लगाते हैं, कि इस संकट के पीछे दोषी भारतीय जनता पार्टी द्वारा शासित केंद्र सरकार द्वारा लगाए गए उपराज्यपाल महोदय हैं, तो उपराज्यपाल कार्यालय से बड़ा ही ऊलजलूल सा जवाब आता है। अपनी बात को सत्यापित करने हेतु उदाहरण देते हुए मंत्री सौरभ भारद्वाज ने कहा, कि कुछ दिनों पहले मैंने ही एक प्रेस वार्ता के माध्यम से आप सभी लोगों को यह बात बताई थी, कि दिल्ली के आशा किरण होम शेल्टर में 13 लोगों की मृत्यु हो गई थी और छानबीन करने पर यह बात सामने आई थी, कि आशा किरण होम शेल्टर में डॉक्टर और पैरामेडिकल स्टाफ की भारी कमी थी, जबकि वहां पर रहने वाले लोग जो कि मानसिक और शारीरिक रूप से पीड़ित हैं, उनके लिए डॉक्टर और पैरामेडिकल स्टाफ का होना बेहद जरूरी है I ट्रांसफर और पोस्टिंग का अधिकार सीधे तौर पर उपराज्यपाल महोदय के अधीन आता है, तो इन्हीं की गलती से यह मृत्यु हुई। उन्होंने कहा कि आरोप के जवाब में तुरंत उपराज्यपाल महोदय के कार्यालय से एक जवाब जारी किया गया, जिसमें कहा गया कि क्योंकि NCCSA की बैठक नहीं हो पाई इसलिए हम आशा किरण होम शेल्टर में मेडिकल स्टाफ और डॉक्टर को की तैनाती नहीं कर सके। उन्होंने कहा हालांकि बाद में कोर्ट की फटकार के बाद इस मामले में डॉक्टर और पैरामेडिकल स्टाफ की तैनाती बिना NCCSA से कर दी गई है, परंतु क्योंकि उपराज्यपाल महोदय कार्यालय से झूठ परोसा जाता है, वही काम उन्होंने यहां भी किया।

एक अन्य उदाहरण देते हुए मंत्री सौरभ भारद्वाज ने कहा कि कुछ दिनों पहले मैंने यह बात भी उठाई थी, कि दिल्ली सरकार के अस्पतालों में डॉक्टर और पैरामेडिकल स्टाफ की भारी कमी है। सामान्यतः एक अस्पताल को संभालने के लिए एक डायरेक्टर या एक मेडिकल सुपरिंटेंडेंट होना चाहिए। परंतु हालत यह है कि एक व्यक्ति को कई कई अस्पतालों की जिम्मेदारी दी हुई है, जिसके कारण वह अपनी जिम्मेदारियां को सही तरीके से नहीं निभा पा रहा है। इस मामले में भी उपराज्यपाल कार्यालय से वही ऊलजलूल जवाब दिया गया, क्योंकि NCCSA की बैठक नहीं हो पाई इसलिए हम अस्पतालों में डॉक्टर और अन्य पैरामेडिकल स्टाफ की तैनाती नहीं कर पाए हैं। मंत्री सौरभ भारद्वाज ने कहा कि मैंने जब से दिल्ली के स्वास्थ्य मंत्री का पदभार संभाला है तब से लेकर अब तक मैं उपराज्यपाल महोदय को लगभग आधा दर्जन बार पत्र लिखकर इस बात से अवगत करा चुका हूं, कि दिल्ली के अस्पतालों में लगभग 30% डॉक्टर और स्पेशलिस्ट के पद खाली पड़े हैं, सैकड़ो पद पैरामेडिकल स्टाफ के खाली पड़े हैं, उन पदों पर जल्द से जल्द डॉक्टर और पैरामेडिकल स्टाफ की नियुक्ति की जाए। उन्होंने कहा कि मेरे इन पत्रों के जवाब में भी उपराज्यपाल महोदय के कार्यालय से बड़ा ही अटपटा सा जवाब हमारे पास आया कि हमारे पास लगभग 25-26 स्पेशलिस्ट की लिस्ट आ गई है, परंतु हम इनकी तैनाती नहीं कर पा रहे हैं क्योंकि दिल्ली के मुख्यमंत्री उपलब्ध नहीं है और NCCSA की बैठक नहीं हो पा रही है।

इसी प्रकार से दिल्ली के अंबेडकर मेडिकल कॉलेज में घटित एक घटना का उदाहरण देते हुए मंत्री सौरभ भारद्वाज ने कहा कि उस मेडिकल कॉलेज में दो छात्राओं के साथ एक प्रोफेसर ने शारीरिक शोषण करने की कोशिश की और शिकायत करने के बाद उप राज्यपाल महोदय जिनके अधीन सीधे तौर पर सर्विसेज विभाग आता है, उनके कार्यालय से कोई कार्यवाही नहीं की गई ना तो उस दोषी प्रोफेसर को हटाया गया और ना ही कॉलेज के प्रिंसिपल के खिलाफ कोई कार्यवाही की गई और प्रश्न पूछने पर वही अटपटा सा जवाब उपराज्यपाल कार्यालय से आया, क्योंकि NCCSA की बैठक नहीं हो सकी, इसलिए हम उस प्रोफेसर और प्रिंसिपल के खिलाफ कोई कार्यवाही नहीं कर सके I मंत्री सौरभ भारद्वाज ने कहा, कि जब यह खबर मीडिया में बहुत ज्यादा उठी और दबाव बना तो मजबूरन उपराज्यपाल महोदय को उस दोषी प्रोफेसर को सस्पेंड करना पड़ा। मंत्री सौरभ भारद्वाज ने कहा कि बंगाल में घटित घटना को लेकर तो भारतीय जनता पार्टी खूब शोर मचाती है, परंतु जब इसी प्रकार की घटना दिल्ली में हुई तो भाजपा शासित केंद्र सरकार द्वारा नियुक्त किए गए उपराज्यपाल महोदय ने दोषी प्रोफेसर और प्रिंसिपल के खिलाफ तो कोई कार्यवाही की ही नहीं, उल्टा कॉलेज के प्रशासन ने उन दोनों लड़कियों को झूठे मामले में फसाने की साजिश की।

मंत्री सौरभ भारद्वाज ने उप राज्यपाल कार्यालय के झूठ का पर्दाफाश करते हुए कुछ सबूत पत्रकारों के साथ साझा किया I उन्होंने 16 अगस्त 2024 का पीडब्ल्यूडी विभाग का एक आदेश की प्रति पत्रकारों के साथ साझा करते हुए कहा, कि जब कभी भी दिल्ली सरकार अस्पतालों में डॉक्टर और पैरामेडिकल स्टाफ की नियुक्ति की बात करती है तो उपराज्यपाल कार्यालय से बहाना बनाया जाता है, क्योंकि मुख्यमंत्री मौजूद नहीं है और NCCSA की बैठक नहीं हो पा रही है, इसलिए डॉक्टर और अन्य पैरामेडिकल स्टाफ की नियुक्ति नहीं की जा सकती I परंतु इस आर्डर के मुताबिक पीडब्ल्यूडी विभाग द्वारा 7 ग्रुप ए के नए अधिकारियों की नियुक्ति की गई है। पीडब्ल्यूडी विभाग के एक अन्य आदेश की प्रति पत्रकारों के साथ साझा करते हुए उन्होंने बताया, कि 25 जून 2024 को भी पीडब्ल्यूडी विभाग में एक नए ग्रुप ए अधिकारी की नियुक्ति की गई है तथा दो अधिकारियों के ट्रांसफर किए गए हैं I मंत्री सौरभ भारद्वाज ने उपराज्यपाल कार्यालय पर आरोप लगाते हुए कहा, कि ट्रांसफर पोस्टिंग और नियुक्ति तो की जा रही है, परंतु जहां उनका अपना मन होता है, वहां की जा रही है और जहां दिल्ली सरकार को जरूरत है, वहां पर NCCSA की बैठक और मुख्यमंत्री के उपस्थित न होने का बहाना बना दिया जाता है।

मंत्री सौरभ भारद्वाज ने मीडिया के माध्यम से दिल्ली के उपराज्यपाल महोदय से कुछ प्रश्न पूछे जो निम्न प्रकार से हैं.....

1) यदि ट्रांसफर पोस्टिंग हो सकते थे और हो रहे हैं तो उपराज्यपाल कार्यालय ने दिल्ली की जनता को गुमराह क्यों किया?

2) क्या दिल्ली वालों को गुमराह करने के लिए उपराज्यपाल महोदय दिल्ली की जनता से माफ़ी मांगेंगे?

3) यदि उपराज्यपाल महोदय NCCSA की बैठक का हवाला सही दे रहे थे, तो क्या पीडब्ल्यूडी में हुए ट्रांसफर और पोस्टिंग के लिए अपने चहेते अफ़सर पीडब्ल्यूडी प्रिंसिपल सेक्रेटरी अंबरासू को निलंबित करेंगे?

मीडिया के माध्यम से दिल्ली के उपराज्यपाल महोदय विनय सक्सेना से अनुरोध करते हुए मंत्री सौरभ भारद्वाज ने कहा कि यदि वह सच्चे हैं तो अपनी कथनी और करनी में फर्क ना करते हुए पीडब्ल्यूडी विभाग के प्रिंसिपल सेक्रेटरी अंबरासू को तुरंत प्रभाव से, नए अधिकारियों की नियुक्ति और पुराने अधिकारियों के ट्रांसफर करने के लिए निलंबित करें। उन्होंने कहा कि मैं भली भांति इस बात को जानता हूं कि उपराज्यपाल महोदय पीडब्ल्यूडी प्रिंसिपल सेक्रेटरी अंबरासू को निलंबित नहीं करेंगे, क्योंकि उपराज्यपाल महोदय के कार्यालय से झूठ परोसा जाता है। जहां उनका अपना समन होता है, वहां पर नए अधिकारियों की नियुक्ति भी की जाती है और पुराने अधिकारियों के ट्रांसफर भी किए जाते हैं, परंतु जहां दिल्ली वालों के हक की बात होती है, वहां पर NCCSA की बैठक न होने का बहाना बना दिया जाता है।

दिल्ली विधानसभा: हो सकते है वक्त से पहले चुनाव

परिवहन विशेष। एसडी सेठी।

नई दिल्ली। दिल्ली विधानसभा चुनाव वक्त से पहले कराए जा सकते हैं।इस बार शायद नवंबर या दिसंबर में कराये जाने की उम्मीद है। बता दें कि पिछली बार 8 फरवरी को मतदान हुआ था। राज्य चुनाव आयोग ने इसके लिए तैयारी शुरू कर दी है। उल्लेखनीय है कि राजधानी दिल्ली दिल्ली में फरवरी 2025 से पहले विधानसभा का गठन होना है। इसी के मद्देनजर ही जनवरी के आखिर में या फरवरी के शुरू में चुनाव की उम्मीद थी। लेकिन सूत्रो के मुताबिक चुनाव नवंबर-दिसंबर में हो सकते है। इसके लिए मतदातासूची रिवीजन का काम अगले माह सितंबर में शुरू हो जाएगा।

गौरतलब है कि 2019 में दिल्ली विधानसभा चुनाव 8 फरवरी को हुए थे। और 11 फरवरी को बाकायदा मतगणना, हुई थी।इस बार यह चुनाव समय से पहले हो सकता है। दरअसल दिल्ली के मुख्य निर्वाचन अधिकारी कार्यालय के पत्र ने इन कयासो को बढा दिया है। पत्र में सभी विभाग प्रमुखों से मैनपावर की स्थिति मांगी गई है।यह जानकारी अधिकारियो के ग्रेड के हिसाब से मांगी गई है।इससे चुनाव ड्यूटी तय की जा सकेगी। तमाम संबंधित विभागो द्वारा 7 दिनों के भीतर यह जानकारी देने की हिदायत दी है।

बता दे कि पिछले10 साल से दिल्ली की सत्ता पर काबिज आम आदमी पार्टी ने समय से पहले चुनाव का अंदेशा देखते हुए प्रचार अभियान भी शुरू कर दिया है। पूर्व उपमुख्यमंत्री मनीष सिसौदिया पदयात्रा कर रहे है। पार्टी ने बूथ मैपिंग भी शुरू कर दी है। उधर बीजेपी ने आम आदमी पार्टी के 5 पार्षदो को पार्टी में शामिल कर लिया है।इससे पहले 1 मंत्री और 1 विधायक भी पाला बदलकर बीजेपी में आ चुके है। भाजपा ने भी संगठन स्तर पर अपनी तैयारी तेज कर दी है। कमजोर सीटों पर दूसरे दलों के मजबूत कंडीडेटस को चुनावी समर में उतारा जाएगा। वहीं लोकसभा में कांग्रेस को मिली करारी हार के बाद कांग्रेस ने दिल्ली में अकेले लडने का फैसला लिया है। पार्टी स्तर पर कांग्रेस भी अपने संगठन को मजबूत करना शुरू कर दिया है। इसील के मद्देनजर कांग्रेस 2 अक्टूबर से दिल्ली जोडो यात्रा निकालेगी। फिलहाल कांग्रेस ने जिला कमेटियों की मासिक बैठन शुरू कर दी है। और उम्मीदवारो के पैनल पर मंथन शुरू हो गया है। उल्लेखनीय है कि वर्तमान दिल्ली विधानसभा में कुल विधायकों की संख्या 70 में से आदमी पार्टी के 62 विधायक है। वहीं बीजेपी के 08 विधायक है। वही कांग्रेस का कोई विधायक नहीं है।

मंत्री ने दिए अधिकारियों को निर्देश-जलजमाव को रोकने के लिए उठाए जाए शॉर्ट-टर्म व लॉंग-टर्म सोल्यूशन

नई दिल्ली। दिल्ली में जलजमाव की समस्या को दूर करने के मद्देनज़र पीडब्ल्यूडी मंत्री आतिशी ने मंगलवार को विभाग के अधिकारियों के साथ रिंग रोड पर धौलाकुआँ फ़्लाइओवर व उसके आसपास की सड़कों का निरीक्षण किया।

बता दे कि, 23 अगस्त को हुई अप्रत्याशित बारिश के कारण रिंग रोड पर धौलाकुआँ फ़्लाइओवर के नीचे जलजमाव की समस्या पैदा हुई थी। लोगों को दोबारा यहाँ ऐसी समस्या का सामना न करना पड़े इसे लेकर पीडब्ल्यूडी मंत्री ने आज यहाँ निरीक्षण किया।

यहाँ अधिकारियों ने पीडब्ल्यूडी मंत्री से साझा करते हुए बताया कि, धौलाकुआँ के इस पॉइंट पर जलजमाव की वजह यहाँ का कटोरनुमा आकार है। मात्र कुछ घंटों में ही भारी बरसात के कारण यहाँ ढलान की वजह से बाक़ी सड़कों का पानी भी आकर इकट्ठा हो गया। जिस वजह से जल-निकासी में समय लगा।

इसपर पीडब्ल्यूडी मंत्री ने अधिकारियों को निर्देश दिए कि, इस पॉइंट से जलजमाव को दूर करने के लिए शॉर्ट-टर्म व लॉंग-टर्म सोल्यूशन उठाए जाए। उन्होंने अधिकारियों को यहाँ मौजूदा ड्रेनेज सिस्टम को प्रति घंटा 100 मिमी बरसात के अनुरूप अपग्रेड करने के निर्देश दिए।

साथ ही अधिकारियों को निर्देश दिए कि, यहाँ पर्याप्त मात्रा में मोबाइल पंप तैनात कर पंपिंग कैपेसिटी बढ़ाई जाए ताकि भविष्य में जलजमाव न हो और लोगों को समस्या का सामना न करना पड़े।

उन्होंने कहा कि, धौलाकुआँ और इसके आसपास की सड़कें दिल्ली के सबसे महत्वपूर्ण मार्गों में शामिल है। ऐसे में अधिकारी यहाँ

सेंट जॉन एम्बुलेंस ब्रिगेड द्वारा अरुणा आसिफ अली व राजकीय उच्चतर माध्यमिक बाल विधालय मदनपुर खादर स्कुली छात्र छात्राओं को इमरजेंसी मेडिकल रिस्पांडर (सीपीआर) का प्रशिक्षण दिया गया

परिवहन विशेष

कोविड-19 महामारी के बाद, कई लोगों को लंबे समय तक रहने वाले लक्षणों का सामना करना पड़ रहा है, जिससे मामलों में वृद्धि हो सकती है गंभीर दिल के दौरे से होने वाली मौतों में, विशेषकर युवा व्यक्तियों में। पढ़ा-लिखा कर बड़ा करना युवा पीढ़ी को जागरूक करने का बीड़ा दिल्ली ब्रिगेड ने उठाया है शैक्षणिक क्षेत्र में आपातकालीन प्रतिक्रिया और चरण-दर-चरण प्री-हॉस्पिटल सीपीआर प्रक्रियाओं पर सत्र संस्थाएँ, जो जीवन बचाने में मदद कर सकती हैं। हमने स्कूल के अनुरोध पर सत्र आयोजित किए हैं 24 अगस्त 2024 को दो स्कूलों में अधिकारी, एक सत्र सुबह और दूसरा शाम को साउथ ईस्ट डिस्ट्रिक्ट में बदलाव. सत्र का उद्देश्य युवाओं और बच्चों के बीच जागरूकता पैदा करना और समझ विकसित करना है हृदय और श्वसन संबंधी आपात स्थितियों से निपटना। इसमें सुरक्षा निर्देश, पहचान और शामिल थे चरण-दर-चरण क्रियाएँ, और सीपीआर (कार्डियोपल्मोनरी रिससिटेशन) का प्रदर्शन विवरण इस प्रकार है; सत्र 1 पहला सत्र अरुणा आसफ अली सरकारी सर्वोदय कन्या विद्यालय तुगलकाबाद एक्सटेंशन में आयोजित किया गया। नई दिल्ली-110019 (स्कूल आईडी-1925061) 24 अगस्त 2024 को प्रातः 08 बजे से प्रातः 10:30 बजे तक। 1460 लड़कियाँ इस सत्र में छात्रों और 40 शिक्षकों ने भाग लिया। व्यवस्था का संचालन सुश्री मधु बाला जी ने किया ।

सत्र 2 दूसरा सत्र राजकीय बालक वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय मदन पुर खादर में आयोजित किया गया। नई दिल्ली-110076 (स्कूल आईडी- 1925403) 24 अगस्त 2024 को दोपहर 2:00 बजे से शाम 4:00 बजे तक। 80 छात्र और इस सत्र में 10 शिक्षकों ने भाग लिया। श्री मोहम्मद राहिल स्कुल की ओर से व्यवस्था का समन्वय किया.

छात्रों ने किसी हताहत को संभालने और स्थानांतरित करने का भी अभ्यास किया। यह सत्र उत्साहपूर्वक संपन्न हुआ छात्रों और शिक्षकों से बातचीत और प्रतिक्रियाएँ।

दोनों सत्र अत्यधिक संवादात्मक थे। प्रतिभागियों को प्रश्न पूछने के लिए प्रोत्साहित किया गया प्रभावी पूर्व-अस्पताल प्राप्त करने के लिए सही तकनीकों का उपयोग करके डमी पर अभ्यास करने का अवसर सीपीआर परिणाम छात्रों को यह भी सिखाया गया कि किसी दुर्घटना को कैसे संभालना है और कैसे शिफ्ट करना है। सत्र छात्रों और शिक्षकों दोनों की उत्साहपूर्ण प्रतिक्रियाओं के साथ संपन्न हुआ।

श्री के नेतृत्व में दक्षिण पूर्व और दक्षिण जिलों के दिल्ली ब्रिगेड अधिकारियों की एक टीम। पी डी वेरखिया, सहायक आयुक्त; सुश्री मोनिका, कोर ऑफिसर (नर्सिंग); और श्री श्याम, कोर अधिकारी, सुश्री द्वारा सहायता प्रदान की गई श्री प्रदीप कुमार एम्बुलेंस ऑफिसर श्री दिनेश यादव एम्बुलेंस सदस्य ने आयोजन और संचालन किया सत्र. स्कूल अधिकारियों ने सत्र की सराहना की और इसे और अधिक विस्तारित करने की इच्छा व्यक्त की स्कूल, क्योंकि यह बहुमूल्य जीवन-रक्षक ज्ञान प्रदान करता है।

दिल्ली ब्रिगेड जीएनसीटी के सभी शैक्षणिक संस्थानों में इस जागरूकता को फैलाने के लिए प्रतिबद्ध है दिल्ली, क्योंकि यह आज के संदर्भ में महत्वपूर्ण है।

ग्रुप हाउसिंग समेत इन भूखंड योजना में आवेदन के लिए कुछ दिन शेष, जल्दी करें अप्लाई

अपना घर का सपना देखने वालों के लिए यीडा की आवासीय भूखंड स्कीम भले खत्म हो गई हो लेकिन यमुना प्राधिकरण की ग्रुप हाउसिंग संस्थागत श्रेणी की भूखंड योजना आदि अभी भी चालू है। इसके समाप्त होने की अंतिम तारीख 30 अगस्त है। इसलिए बिना देरी किए आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। लेख के माध्यम से पढ़ें पूरी जानकारी।

ग्रेटर नोएडा। यमुना प्राधिकरण की ग्रुप हाउसिंग, संस्थागत, नर्सिंग होम आदि की भूखंड योजना समाप्त होने जा रही हैं। इन योजना में आवेदन के लिए तीस अगस्त अंतिम तारीख है। प्राधिकरण (YEIDA news) सितंबर में बोली के आधार पर योजना में भूखंडों का आवंटन करेगा।

यमुना प्राधिकरण (Yamuna Authority) ने एक अगस्त को संस्थागत श्रेणी में अस्पताल, नर्सिंग होम, नर्सरी स्कूल, ग्रुप हाउसिंग के लिए भूखंड योजना निकाली थी। इन सभी योजना में भूखंडों के आवंटन का आधार नीलामी है। प्राधिकरण ने इन योजनाओं से अच्छा राजस्व मिलने की उम्मीद है। योजना तीस अगस्त को समाप्त हो जाएंगी। सितंबर में इन योजनाओं में बोली लगाई जाएगी।

धिकरण की आवासीय भूखंड योजना भी 23 अगस्त को खत्म

मेडिकल डिवाइस पार्क और ऑफिस के लिए भूखंडों की योजना पहले ही समाप्त हो चुकी है। मेडिकल डिवाइस पार्क में साक्षात्कार व ऑफिस भूखंडों के लिए नीलामी के आधार पर भूखंडों का आवंटन होगा। प्राधिकरण की आवासीय भूखंड योजना भी 23 अगस्त को समाप्त हो चुकी है।

इस योजना में लॉटरी दस अक्टूबर को होगी। प्राधिकरण ने भूखंड योजना में मिलने आवेदनों की जांच शुरू कर दी है। जांच के बाद लाटरी के लिए योग्य आवेदकों की सूची प्राधिकरण की वेबसाइट पर अपलोड कर आवेदन की कमियों को सुधारने का अवसर दिया जाएगा।

होटल के लिए निकाली भूखंड योजना

प्राधिकरण ने होटल के लिए भूखंड योजना (Noida Bhukhand Yojana) निकाली है। योजना में चार भूखंड शामिल हैं। सभी भूखंड सेक्टर 29 में हैं। तीन भूखंड 3400 वर्गमीटर व एक भूखंड 6400 वर्गमीटर का है। योजना में आवेदन के लिए 17 सितंबर तक का समय दिया गया है। बोली के आधार पर भूखंडों का आवंटन किया जाएगा।

गाजियाबाद में 30 अगस्त को चलेगा बुलडोजर, भारी पुलिस बल के साथ 27 बीघे जमीन कराई जाएगी कब्जा

परिवहन विशेष न्यूज

वर्षों पहले मंडी समिति ने अतिक्रमण के खिलाफ कार्रवाई करने की कोशिश की थी। कुछ लोगों ने हंगामा और पत्थरबाजी कर दी थी। पुलिस बल कम होने से कार्रवाई रोकनी पड़ी थी। समिति को अतिक्रमण हटाने में सफलता नहीं मिली थी। इस बार पहले से बड़े स्तर पर कार्रवाई होगी। इससे पहले मंडी समिति की ओर से सभी को इसकी सूचना दे दी गई है।

गाजियाबाद। नवीन फल और सब्जी मंडी में पहली बार 30 अगस्त को बड़े स्तर पर कार्रवाई कर 27 बीघे में बने फसल बेचने के चबूतरों को कब्जा मुक्त कराया जाएगा। कार्रवाई का आदेश दैनिक जागरण की खबर का संज्ञान लेकर मंडी निदेशक लखनऊ की ओर से दिया गया है। अरबों रुपये की भूमि पर बने किसानों के चबूतरों पर लोगों ने कब्जा कर लिया था।

इस संबंध में नगर मजिस्ट्रेट ने कार्रवाई के दौरान पर्याप्त पुलिस बल और पीएसी तैनात कराने के लिए पुलिस उपायुक्त ट्रांस हिंडन को पत्र लिखा है। मंडी में बागपत, बुलंदशहर, हापुड़, मेरठ, गौतमबुद्ध नगर सहित अन्य जिलों से प्रतिदिन हजारों किसान व व्यापारी आते हैं। किसानों को फसल बेचने के लिए मंडी समिति द्वारा चबूतरे बनाए गए हैं।

दैनिक जागरण की खबर का असर

किसानों के चबूतरों पर कुछ दुकानदारों ने कब्जा कर रखा है। अतिक्रमण करने वाले कुछ दुकानदारों पर लाइसेंस भी नहीं है। मंडी समिति पर ही किसानों के प्लेटफार्म पर कब्जा कराने का आरोप है।

किसानों को चबूतरे पर सब्जी व फल बेचने नहीं दिया जाता है। मजबूरी में किसानों को सड़क पर फल व सब्जी बेचने पड़ रही है। दैनिक जागरण ने किसानों की पीड़ा पर प्रमुखता से खबर प्रकाशित की। वहीं मंडी में हो रही अवैध अतिक्रमण पर लगातार खबरें प्रकाशित की।

ऐसे कुछ के कुछ व्यापारियों ने दैनिक जागरण की खबर के साथ मुख्यमंत्री से शिकायत की। मंडी व्यापारी मंडी निदेशक से मिलने गए थे। जिसके बाद मंडी वित्त नियंत्रक ने मंडी में पहुंचकर निरीक्षण किया।

किसानों के चबूतरों पर लोगों ने किया कब्जा

जांच में पाया गया कि मंडी में किसानों के चबूतरों पर लोगों ने कब्जा कर लिया है। इसकी पूरी रिपोर्ट मुख्यालय भेजी गई। मंडी निदेशक के आदेश पर 30 अगस्त को 27 बीघे भूमि पर बने चबूतरों पर अवैध कब्जे को खाली कराया जाएगा।

आठ परिवारों को फ्लैट खाली करने की चेतावनी, बिल्डर ने कहा- लिफ्ट और बिजली कर देंगे बंद

परिवहन विशेष न्यूज

चिंटेल्स पैराडिसो के जे टावर में रहने वाले आठ परिवारों को बिल्डर ने फ्लैट खाली करने की चेतावनी दी है। कंपनी ने 27 अगस्त से लिफ्ट बंद करने और 30 अगस्त से बिजली काटने का फैसला लिया है। आईआईटी दिल्ली और जिला प्रशासन ने टावर को असुरक्षित घोषित किया था। अधिकांश परिवार फ्लैट खाली कर चुके हैं लेकिन आठ परिवार अभी भी वहां रह रहे हैं।

गाजियाबाद। गुरुग्राम। सेक्टर-109 स्थित चिंटेल्स पैराडिसो सोसायटी के जे टावर में रहने वाले आठ परिवारों को चिंटेल्स इंडिया लिमिटेड की तरफ से फ्लैट खाली करने को लेकर सख्त चेतावनी दी गई है। कंपनी ने नोटिस जारी करते हुए 27 अगस्त से लिफ्ट का संचालन बंद करने और 30 अगस्त से बिजली की आपूर्ति को काटने का निर्णय लिया है।

यह कदम आईआईटी दिल्ली और जिला प्रशासन गुरुग्राम द्वारा टावर को असुरक्षित घोषित किए जाने के बाद उठाया गया है। गौरतलब है कि जनवरी 2023 में आईआईटी दिल्ली की रिपोर्ट के अनुसार जे टावर को रहने के लिए असुरक्षित माना गया था। जिसके बाद अधिकांश परिवार अपने फ्लैट्स खाली कर चुके हैं। आठ परिवार अभी भी इस टावर में रह रहे हैं और उन्होंने फ्लैट्स खाली करने से इनकार कर दिया है।

15 दिनों में फ्लैट खाली करने का था आदेश

जिला उपायुक्त निशांत कुमार यादव ने भी सात अगस्त को आपदा प्रबंधन अधिनियम के तहत जे टावर को असुरक्षित घोषित कर 15 दिनों के भीतर खाली करने का आदेश जारी किया था। चिंटेल्स सोसायटी के जे टावर में रहने वाले निवासी देबब्रता दत्ता का आरोप है कि बिल्डर उन्हें परेशान कर रहा है।

लिफ्ट और बिजली की सप्लाई होगी बंद

उनका कहना है कि फ्लैट मालिकों को छह महीने का किराया और स्थानांतरित शुल्क दिया जाना चाहिए। उन्होंने यह भी मांग की है कि टावर का दोबारा निर्माण कब से शुरू होगा, इस बारे में कोई स्पष्ट जानकारी नहीं दी गई है।

सोसायटी के आरडब्ल्यूए अध्यक्ष राकेश हुड्डा का कहना है कि जिला प्रशासन ने विस्थापन के आदेश नहीं दिए हैं। बिना विस्थापन की व्यवस्था के निवासियों से फ्लैट्स खाली करने की उम्मीद नहीं की जा सकती। हुड्डा का कहना है कि जिला प्रशासन को निवासियों का सहयोग करना चाहिए। इस संबंध में बिल्डर प्रबंधन को निवासियों के साथ बातचीत करने के लिए दिशा-निर्देश जारी किए जाने चाहिए।

चिंटेल्स इंडिया लिमिटेड के वरिष्ठ उपाध्यक्ष जेएन यादव का कहना है कि लिफ्ट के संचालन से होने वाली वाइब्रेशन टावर को नुकसान पहुंचा सकती है इसलिए लिफ्ट को बंद किया जा रहा है। इसके बाद बिजली की सप्लाई भी बंद कर दी जाएगी।

जीपीएल सोसायटी में हंगामे के बाद पावर बैकअप बहाल

बादशाहपुर सेक्टर-70 स्थित जीपीएल ईडन हाइट्स में हंगामा होने के बाद पावर बैकअप बहाल कर दिया गया है। रखरखाव राशि न देने पर सोसायटी की आरडब्ल्यूए ने कुछ लोगों का पावर बैकअप कट कर दिया था।

इस पर लोगों ने विरोध जताया। लोगों का कहना है कि जो लोग समय पर रखरखाव राशि दे रहे हैं। उनको भी परेशान किया जा रहा है। हंगामा होने पर पुलिस भी मौके पर पहुंची। दोनों पक्षों को समझा बूझकर शांत किया गया।

मनमानी पर उतरी RWA

जीपीएल ईडन हाइट्स के रहने वाले सुनीर मित्तल का कहना है कि आरडब्ल्यूए मनमानी पर उतरी हुई है। समय पर रखरखाव शुल्क दे रहे हैं। जिसके बावजूद बोला जा रहा है कि सोसाइटी घाटे में चली गई है। अब फ्लैट मालिकों पर इस राशि को जबरन डाल दिया है। राशि नहीं देने पर जनरेटर से दी जा रही बिजली को काटा जा रहा है।

शनिवार को डीएचबीवीएन की बिजली जाने पर बिजली सप्लाई को काट दिया। आरडब्ल्यूए प्रधान प्रीति पुरोहित ने बताया कि आम सभा की बैठक में एजेंडा पास हुआ है। अधिकांश फ्लैट मालिकों ने राशि दे दी है। करीब 15 फ्लैट मालिक डिफाल्टर हैं। ये राशि नहीं दे रहे हैं। इन्हें तीन दिन की मोहलत दी है। राशि जमा नहीं करने पर जनरेटर से बिजली नहीं दी जाएगी।

16 साल बाद मिला घर का 'लाडला', इकलौती बहन ने भाई के हाथ में बांधी राखी; माता-पिता की आंखों से छलके खुशी के आंसू

परिवहन विशेष न्यूज

करीब 16 साल पहले एक युवक अपने परिवार से बिछड़ गया था। अब फेसबुक के जरिए लाडला बेटा अपने परिवार में पहुंच गया। इतने लंबे समय बाद बेटे को देख परिजनों की आंखें भर आई। वहीं इकलौती बहन ने रक्षाबंधन पर भाई के हाथ में राखी बांधी। बेटे के मिल जाने से परिवार में खुशी का माहौल है।

साहिबाबाद। नोएडा में कोतवाली जारचा क्षेत्र स्थित सैथली गांव के सेना से सेवानिवृत्त अमरपाल सिंह का लापता बेटा 16 साल बाद फेसबुक के माध्यम से मिल गया है। इससे परिवार में खुशी का माहौल है।

अमरपाल सिंह के परिवार में दो बेटे गौरव, सौरव व एक बेटी अंजली है। ग्रामीणों ने बताया कि सर्विस के दौरान अमरपाल की पोस्टिंग देहरादून में थी। उसी दौरान 16 साल पहले आठ साल का गौरव देहरादून से गुम हो गया था।

इसके बाद परिवार के लोगों ने काफी जगह तलाश किया, लेकिन उसका कहीं सुराग नहीं लगा। रिटायर होने के बाद देहरादून से सैथली गांव आकर परिवार के साथ रहने लगे।

दिल्ली में एक परिवार के साथ रहने लगा था

उधर, गौरव परिवार से बिछड़ने के बाद बस में बैठकर दिल्ली आ गया, जहां बस अड्डों व मंडियों में समय काटने लगा। अचानक उसे दिल्ली में एक भला परिवार मिल गया, जिसके बच्चे नहीं थे। गौरव उनके साथ रहने लगा। समय बीतता गया पर गौरव अपने माता-पिता को नहीं भूला। इसी बीच दिल्ली के परिवार ने उसे परचून की दुकान खोलवा दी, लेकिन गौरव अपने पिता का नाम फेसबुक पर डालकर सर्च करता रहा।

फेसबुक के जरिए परिवार से मिला युवक

वहीं, एक दिन अचानक उसे फेसबुक पर पिता की तस्वीर मिली, जिसे पहचान कर उसने माता-पिता से संपर्क किया। दिल्ली के परिवार ने उसके माता-पिता से संपर्क किया तो वह मिलने के लिए बताए गए पते पर दिल्ली पहुंच गए। गौरव ने माता-पिता को पहचान लिया। रक्षाबंधन के दिन गौरव घर वापस आया। बहन ने भाई की कलाई पर 16 साल बाद राखी बांधी। परिवार में खुशी की लहर है।

नया परिदृश्य और नई आकांक्षाएं

डॉ. शिबन कृष्ण रैणा

जैसे-जैसे चुनाव नजदीक आ रहे हैं, देश और अंतरराष्ट्रीय समुदाय की नजरें जम्मू और कश्मीर के इन चुनाओं पर केन्द्रित हो रही हैं राज्य गहन राजनीतिक गतिविधियों का केंद्र बन गया है, जहां नेता और पार्टी कार्यकर्ता समर्थन जुटाने के लिए जोरदार प्रचार कर रहे हैं।

जम्मू और कश्मीर विधानसभा चुनावों की लंबे समय से प्रतीक्षित तिथियों की घोषणा कर दी गई है। चुनाव तीन चरणों में आयोजित किए जाएंगे। पहले चरण का मतदान, जिसमें 24 सीटें शामिल हैं, 18 सितंबर को होगा। दूसरे चरण में 26 सीटों पर 25 सितंबर को मतदान होगा, और तीसरे चरण में 40 सीटों पर 1 अक्टूबर को मतदान होगा। चुनाव परिणाम 4 अक्टूबर को घोषित किए जाएंगे। यह उल्लेखनीय है कि सुप्रीम कोर्ट ने जम्मू और कश्मीर में 30 सितंबर, 2024 तक विधानसभा चुनाव कराने के आदेश दिये थे। यह जम्मू और कश्मीर में अनुच्छेद 370 के उन्मूलन/निरस्तीकरण के बाद पहला विधानसभा चुनाव होगा. निरस्तीकरण 5 अगस्त, 2019 को हुआ था।

पहले, जम्मू और कश्मीर में कुल 111 विधानसभा सीटें थीं, जिनमें जम्मू में 37, कश्मीर में 46, और लद्दाख में 4 सीटें थीं। इसके अलावा, पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर (पीओके) के लिए 24 सीटें निर्धारित थीं। हाल ही में हुई परिसीमन प्रक्रिया के फलस्वरूप सीटों की संख्या परिवर्धित हुयी हैं। अब जम्मू में 43 सीटें होंगी, जबकि कश्मीर में 47 सीटें होंगी। पीओके के लिए यथावत 24 सीटें आरक्षित रहेंगी।

कश्मीरी पंडितों के लिए दो सीटें आरक्षित की गई हैं और उन्हें कश्मीरी प्रवासी/विस्थापित कहा जायगा। इसके अलावा, लेफ्टिनेंट गवर्नर को विधानसभा में तीन सदस्यों को नामित करने का अधिकार होगा, जिनमें से दो कश्मीरी प्रवासी/विस्थापित और एक पीओके से विस्थापित व्यक्ति होगा। दो कश्मीरी प्रवासी नामितों में से एक महिला होनी चाहिए। कश्मीरी विस्थापित को ऐसे व्यक्ति के रूप में परिभाषित किया गया है जो 1 नवंबर, 1989 के बाद घाटी या जम्मू और कश्मीर के किसी भी हिस्से से प्रवास कर गया हो और राहत आयुक्त के यहाँ पंजीकृत हो। जो लोग 1947-48, 1965, या 1971 की घटनाओं के बाद पीओके से प्रवास कर गए, उन्हें विस्थापित व्यक्ति माना जाएगा। प्रवासियों के लिए विशेष रूप से दो सीटों को आरक्षित या नामित करने की पहल के साथ, कश्मीरी पंडित समुदाय के लिए नई आशा जगी है। इस निर्णय से उन्हें अपनी चिंताओं को व्यक्त करने और अपनी लंबे समय से चली आ रही शिकायतों के निवारण की मांग करने के लिए एक मंच मिलने की उम्मीद है।

इसके अलावा, अनुसूचित जाति (एससी) और अनुसूचित जनजाति (एसटी) के लिए 16 सीटें आरक्षित की गई हैं। इनमें से 7 सीटें एससी उम्मीदवारों के लिए आवंटित की गई हैं, जबकि 9 सीटें एसटी उम्मीदवारों के लिए आरक्षित हैं। यहां इस बात का उल्लेख करना आवश्यक है कि जम्मू और कश्मीर में आगामी विधानसभा चुनाव अत्यंत महत्वपूर्ण हैं क्योंकि ये अनुच्छेद 370 के अवसान के बाद पहला चुनाव है और यह चुनाव केंद्र-शासित प्रदेश में लोकतांत्रिक प्रक्रिया को बहाल करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम माना जा रहा है। परिसीमन प्रक्रिया से भी, जिसने जम्मू में विधानसभा सीटों की संख्या बढ़ा दी है, क्षेत्र के राजनीतिक परिदृश्य पर काफी प्रभाव डालने की संभावना है।

जैसे-जैसे चुनाव नजदीक आ रहे हैं, देश और अंतरराष्ट्रीय समुदाय की नजरें जम्मू और कश्मीर के इन चुनाओं पर केन्द्रित हो रही हैं राज्य गहन राजनीतिक गतिविधियों का केंद्र बन गया है, जहां नेता और पार्टी कार्यकर्ता समर्थन जुटाने के लिए जोरदार प्रचार कर रहे हैं। चुनावी- वादे किए जा रहे हैं, और प्रतिस्पर्धी गुटों के बीच आरोपों-प्रत्यारोपों का आदान-प्रदान जारी है। ऐसी स्थिति में, मीडिया की भूमिका न केवल महत्वपूर्ण बल्कि लोकतांत्रिक प्रक्रिया की अखंडता के लिए महत्वपूर्ण हो जाती है। मीडिया राजनेताओं और मतदाताओं के बीच प्राथमिक सेतु है, और इस अवधि के दौरान इसकी जिम्मेदारियां मात्र रिपोर्टिंग से कहीं अधिक हैं। यह आवश्यक है कि मीडिया पत्रकारिता के उच्चतम मानकों का पालन करें और अभियानों की वस्तुनिष्ठ और तथ्यात्मक कवरेज सुनिश्चित करें। सटीकता, निष्पक्षता और सूचना के नैतिक प्रसार के प्रति उनकी प्रतिबद्धता जम्मू और कश्मीर में एक पारदर्शी और निष्पक्ष चुनाव प्रक्रिया सुनिश्चित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगी।

नूपुर शर्मा के बाद कंगना, BJP का सबका विश्वास अपनों पर ही नहीं, ये कदम भक्तों को भी नहीं आ रहा रास

परिवहन विशेष न्यूज

आज के इस एमआरआई स्कैन में बताएंगे कि कंगना ने ऐसा क्या बयान दिया, जिस पर हंगामा मचा है। क्या कंगना को भी नुपूर शर्मा की तरफ बीजेपी किनारे लगा देगी। कंगना के इस बयान का आने वाले हरियाणा विधानसभा चुनाव में क्या असर हो सकता है?

भाजपा सांसद कंगना रनौत को किसान आंदोलन को लेकर बयान देना भारी पड़ गया है। भाजपा ने कंगना के बयान से किनारा कर लिया है और इसके साथ ही उन्हें सख्त निर्देश भी जारी किया है। बीजेपी की ओर से जारी किए गए नोटिस में कहा गया है कि पार्टी की ओर से पार्टी के नीतिगत विषयों पर बोलने के लिए कंगना रनौत को न तो अनुमति है और न ही वो बयान देने के लिए अधिकृत हैं। भाजपा की ओर से कंगना को निर्देशित किया गया है कि वो इस प्रकार के कोई बयान भविष्य में न दे। वहीं कंगना के इस बयान के बाद बीजेपी पर कांग्रेस हमलावर हो गई है। आज के इस एमआरआई स्कैन में बताएंगे कि कंगना ने ऐसा क्या बयान दिया, जिस पर हंगामा मचा है। क्या कंगना को भी नुपूर शर्मा की तरफ बीजेपी किनारे लगा देगी। कंगना के इस बयान का आने वाले हरियाणा विधानसभा चुनाव में क्या असर हो सकता है?

कंगना ने ऐसा क्या कहा, बीजेपी को पल्ला झाड़ना पर गया

अपनी आगामी फिल्म इमरजेंसी के प्रचार कार्यक्रमों में से एक के दौरान, कंगना रनौत ने किसान विरोध के दौरान अपने कार्यों के लिए केंद्र सरकार की प्रशंसा की। उन्होंने तर्क दिया कि अगर नेतृत्व (मोदी सरकार) निर्णायक और मजबूत नहीं होता तो किसानों के विरोध से भारत में बांग्लादेश जैसा संकट पैदा हो सकता था। हैरानी की बात यह है कि कथित किसान नेता राकेश टिकैत ने हाल ही में यही धमकी दी थी। उन्होंने इस बातचीत का एक वीडियो भी अपने ऑफिशियल पर शेयर किया है। वीडियो में कंगना रनौत को यह कहते हुए सुना जा सकता है, बांग्लादेश में जो हुआ, वह यहां भी आसानी से हो सकता था। अगर हमारी लीडरशिप कमजोर होती तो देश में बांग्लादेश जैसी स्थिति हो सकती थी। सभी ने देखा कि किसान आंदोलन के दौरान क्या हुआ था। प्रदर्शन की आड़ में हिंसा फैलाई गई। वहां बलात्कार हो रहे थे। लोगों को मारकर लटकाया जा रहा था। इस स्थित में भारत में बांग्लादेश जैसी स्थिति हो सकती थी। केंद्र सरकार ने जब कृषि कानूनों को वापस लिया तो सभी प्रदर्शनकारी चौंक गए। इस आंदोलन के पीछे एक लंबी प्लानिंग थी। कंगना ने विरोध प्रदर्शन जारी रखने के लिए निहित स्वार्थों और विदेशी शक्तियों की भी आलोचना की, जब सरकार ने तीन किसान कानूनों को वापस ले लिया जो प्रदर्शनकारी किसानों की प्रमुख मांग थी।

बीजेपी ने चेताया

किसान आंदोलन पर कंगना का बयान पार्टी का मत नहीं है। उन्हें पार्टी की ओर से, नीतिगत विषयों पर बोलने की न तो अनुमति है, न ही वह बयान देने के लिए अधिकृत हैं। यह भविष्य में भी ऐसे कोई बयान न दें। चिट्ठी में आगे लिखा गया की पार्टी की ओर से कंगना रनौत को निर्देशित किया गया है कि वह इस प्रकार के बयान भविष्य में ना दें।

किसान संगठन नाराज

ऑल इंडिया किसान सभा ने कंगना रनौत के बयान की निंदा की और कहा कि किसान आंदोलन पर अपमानजनक बातें कहने की उनकी आदत हो गई है। हमारी मांग है कि अपनी पार्टी के सांसद के अपमानजनक बयान पर प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी माफी मांगें। यह पीएम का संवैधानिक दायित्व है। सरकार कंगना के खिलाफ क्रिमिनल केस दर्ज करे, नहीं तो किसान सार्वजनिक तौर पर कंगना रनौत का बहिष्कार करने को बाध्य होंगे।

कांग्रेस ने साधा निशाना

कांग्रेस ने कहा कि अगरं सत्तारूढ़ दल बीजेपी अपनी सांसद की टिप्पणियों से असहमत है तो उन्हें पार्टी से बाहर करे। सरकार को कंगना के इस दावे पर स्पष्टीकरण देना चाहिए कि अमेरिका और चीन देश के अंदर अस्थरिता की साजिश रच रहे थे। हरियाणा का चुनाव का नजदीक है और पता है कि बीजेपी हारने जा रही है। ऐसे में बीजेपी ने बयान जारी कर कंगना की टिप्पणियों से असहमति जताई है। विपक्ष के नेता राहुल गांधी ने सोमवार को कहा कि भारतीय जनता पार्टी की सांसद और अभिनेत्री कंगना रनौत का विवादित बयान भाजपा की किसान विरोधी नीति एवं नीयत का एक और सबूत है। राहुल गांधी ने आरोप लगाया कि किसानों से किए वादों को पूरा करने में नाकाम मोदी सरकार का दुष्प्रचार तंत्र लगातार किसानों का अपमान करने में जुटा हुआ है।

बीजेपी को यूजर्स कर रहे ट्रोल

कंगना रनौत मामले को नूपुर शर्मा वाले मामले से जोड़ते हुए यूजर्स बीजेपी को ट्रोल कर रहे हैं। एक यूजर ने एक्स पर लिखा कि बीजेपी ने नूपुर शर्मा को तब धोखा दिया जब उन्होंने एक साहसिक (लेकिन सत्ता बयान) दिया। बीजेपी ने अब कंगना रनौत से भई पल्ला झाड़ लिया। क्या आप इस पर बीजेपी के रुख का समर्थन करते हैं या कंगना रनौत का? एक अन्य यूजर ने बीजेपी को ट्रोल करते हुए कहा कि जैसे बीजेपी ने नूपुर शर्मा को छोड़ा था। उसी तरह से बीजेपी ने कंगना रनौत से भी किनारा कर लिया है।

हरियाणा विधानसभा पर क्या असर

दूध का जला छाछ भी फूंक फूंक कर पीता है। किसान आंदोलन की वजह से पांच सीटों का नुकसान झेल रही बीजेपी विधानसभा चुनाव में ऐसी कोई गलती नहीं दोहराना चाहती है। हरियाणा में जाट वोट 25 फीसदी है। यानी हरियाणा में चार में से एक वोट जाट समुदाय से आता है। साल 2024 के लोकसभा चुनाव में बीजेपी को पांच सीट का नुकसान देखने को मिला थाय इसके पीछे जाट वोटर्स की नाराजगी थी। लोकसभा चुनाव में बीजेपी को 27 फीसदी जाट वोट मिला और 23 फीसदी वोटों का नुकसान झेलने को मिला। इससे इतर कांग्रेस को 64 फीसदी जाट वोट मिला और 31 फीसदी का फायदा हुआ। हरियाणा में 90 विधानसभा सीटों में से 36 पर जाट वोट निर्णायक भूमिका अदा करते हैं।

– :सौजन्य :–

ईवी ड्राइव द फ्यूचर

टैक्स को लेकर एक बार फिर मुखर हुए राजीव बजाज, बताया बाइक और स्कूटर पर क्यों है इतना जीएसटी, अगले वित्त वर्ष में ई-रिक्शा भी करेंगे लॉन्च

परिवहन विशेष न्यूज

देश की दिग्गज ऑटोमोबाइल कंपनी बजाज ऑटो के सीईओ राजीव बजाज ने एक बार फिर वाहनों पर टैक्स का मुद्दा उठाया है। राजीव बजाज इससे पहले भी कई बार बाइक और स्कूटर पर 28 फीसदी टैक्स के खिलाफ बोल चुके हैं। उन्होंने कहा कि एक तरफ सरकार इलेक्ट्रिक वाहनों पर 5 फीसदी टैक्स लगा रही है, लेकिन सीएनजी बाइक पर 28 फीसदी टैक्स लगाया जा रहा है। बजाज ऑटो ने हाल ही में दुनिया की पहली सीएनजी बाइक फ्रीडम 125 लॉन्च की है।

सीएनबीसी टीवी18 को दिए इंटरव्यू में राजीव बजाज ने कहा कि ईवी स्कूटर बाइक से कहीं आगे हैं। इसलिए कंपनी त्योहारी सीजन तक एक लाख सीएनजी बाइक बेचना चाहती है। बजाज ऑटो भविष्य में कई नए स्वच्छ ऊर्जा वाहन लाने जा रही है। राजीव बजाज ने कहा कि हम जल्द ही एक और सीएनजी मोटरसाइकिल पेश करेंगे।

राजीव बजाज ने कहा कि सीएनजी से चलने वाले वाहनों को स्वच्छ ऊर्जा वाहन माना जाता है। इसके बावजूद हमें इस पर 28 फीसदी टैक्स देना पड़ता है। बजाज ऑटो ने सीएनजी बाइक पर टैक्स छूट की मांग की है।

राजीव बजाज ने कहा कि बजाज ऑटो अगले महीने इथेनॉल से चलने वाली बाइक और थ्री-व्हीलर पेश करने की तैयारी में है। इन्हें वित्त वर्ष 2025 में लॉन्च किया जाएगा। इसके अलावा कंपनी अगले वित्त वर्ष में किफायती और प्रीमियम इलेक्ट्रिक स्कूटर भी लॉन्च करेगी। नए चेतक प्लेटफॉर्म के भी अगले साल की शुरुआत में आने की उम्मीद है। इलेक्ट्रिक बाइक की लॉन्चिंग पर राजीव बजाज ने कहा कि ईवी सेगमेंट में बाइक के मुकाबले स्कूटर ज्यादा सफल हो रहे हैं।

राजीव बजाज ने कहा कि अगस्त में हम करीब 9000 फ्रीडम 125 सीएनजी बाइक की डिलीवरी करेंगे। जनवरी तक हम हर महीने 40 हजार सीएनजी बाइक बेचने लगेंगे। इस बाइक में 2 किलो का सीएनजी सिलेंडर और 2 लीटर का पेट्रोल टैंक है। इसकी रेंज 330 किमी बताई जा रही है। इसकी 2000 यूनिट बिक चुकी हैं। उन्होंने कहा कि हम अगले वित्त वर्ष में ई-रिक्शा भी लॉन्च करेंगे। बजाज ऑटो के सीईओ ने कहा कि हमारा ईवी बिजनेस मुनाफे में है। इस बाजार में कंपनी की 18 फीसदी हिस्सेदारी है। कंपनी के चेतक स्कूटर का टीवीएस आईक्यूब से कड़ा मुकाबला है।

सितंबर 2024 में टाटा से लेकर मर्सिडीज लॉन्च करेंगी चार कारें और एसयूवी, दो ईवी भी शामिल

परिवहन विशेष न्यूज

भारत में जल्द ही फेस्टिव सीजन की शुरुआत होने वाली है। इसके पहले कंपनियों की ओर से चार बेहतरीन कारों और एसयूवी को लॉन्च करने की तैयारी की जा रही है। September 2024 के दौरान किस कंपनी की ओर से किस सेगमेंट में किस गाड़ी को कब लॉन्च (September 2024 Upcoming Cars 2024 India) किया जाएगा। इनकी संभावित कीमत क्या हो सकती है। आइए जानते हैं।

नई दिल्ली। फेस्टिव सीजन से पहले हर साल कंपनियों की ओर से नई कारों और एसयूवी को पेश किया जाता है, जिससे बिक्री बढ़ाने में मदद मिलती है। नई कारों के लॉन्च से ग्राहकों को भी फायदा मिलता है। अगले महीने भारतीय बाजार में किस कंपनी की ओर से कौन सी एसयूवी लॉन्च (upcoming cars in India in September 2024) की जाएगी। हम आपको इस खबर में बता रहे हैं।

Tata Curvv ICE

टाटा मोटर्स की ओर से अगस्त 2024 में नई कूप एसयूवी के तौर पर Tata Curvv EV को लॉन्च किया गया था। इसके लॉन्च के समय ही कंपनी की ओर से जानकारी दी गई थी कि दो सितंबर को बाजार में इस एसयूवी के ICE वर्जन को लॉन्च किया जाएगा। दो सितंबर को इसे पेट्रोल और डीजल इंजन के विकल्प के साथ लॉन्च किया जाएगा। एसयूवी के इलेक्ट्रिक वर्जन को 17.49 लाख रुपये की एक्स शोरूम कीमत पर लॉन्च किया गया था। लेकिन आईसी वर्जन को इससे कम कीमत पर लाया जा सकता है।

Mercedes Benz EQS Electric

लग्जरी वाहन सेगमेंट में भी मर्सिडीज की ओर से EQS इलेक्ट्रिक एसयूवी को लॉन्च किया जाएगा। कंपनी इसे पांच सितंबर को बाजार में आधिकारिक तौर पर लॉन्च करेगी। यह इलेक्ट्रिक मेबैक एसयूवी होगी जिसमें कई बेहतरीन फीचर्स को दिया जाएगा। सिंगल चार्ज के बाद इसे करीब 600 किलोमीटर तक चलाया जा सकेगा।

Hyundai Alcazar Facelift

साउथ कोरियाई वाहन निर्माता हुंडई की ओर से भी नौ सितंबर को अल्काजार एसयूवी के फेसलिफ्ट वर्जन को लॉन्च करने की तैयारी की जा रही है। इस एसयूवी में भी NFC, ADAS जैसे कुछ बेहतरीन फीचर्स को दिया जाएगा। मौजूदा वेरिएंट के मुकाबले इसकी कीमत में मामूली बढ़ोतरी की जा सकती है।

JSW MG Windsor EV

अगले महीने एक और इलेक्ट्रिक गाड़ी को JSW MG मोटर्स की ओर से 11 सितंबर को लॉन्च किया जाएगा। इसे CUV सेगमेंट में लाया जाएगा। JSW MG Windsor EV में भी कुछ बेहतरीन फीचर्स को ऑफर किया जाएगा, जिसमें पैनोरमिक सनरूफ, ADAS, ज्यादा आरामदायक सीटें शामिल हैं। इसे सिंगल चार्ज में 460 किलोमीटर तक की रेंज दी जा सकती है। लॉन्च के समय इसकी एक्स शोरूम कीमत 17 से 20 लाख रुपये के आस-पास हो सकती है।

पुराने वाहनों को कबाड़ में बदलकर नई गाड़ी खरीदने पर मिलेगी तीन फीसदी तक छूट

परिवहन विशेष न्यूज

प्रमुख वाणिज्यिक और यात्री वाहन कंपनियां त्योहारों से पहले पुरानी गाड़ियों को कबाड़ में बदलने के बदले नये वाहन खरीदने पर 1.5 से तीन प्रतिशत तक छूट देंगी। एक आधिकारिक बयान में मंगलवार, 27 अगस्त को कहा गया कि केंद्रीय सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी के साथ एक बैठक में वाहन मैन्यूफैक्चरों ने ये सहमति जताई। बयान में कहा गया है कि ये पहल देश में संसाधनों के अनुकूलतम उपयोग (सर्कुलर) वाली अर्थव्यवस्था को गति देने और स्वच्छ, सुरक्षित और ज्यादा कुशल वाहनों के इस्तेमाल को बढ़ावा देने की दिशा में अहम कदम है। गडकरी ने मंगलवार को भारत मंडपम में वाहन कंपनियों के टॉप निकाय सियाम के प्रतिनिधिमंडल के साथ बैठक की अध्यक्षता की।

बयान में कहा गया है, ''बातचीत के दौरान, सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री की सलाह पर सकारात्मक रूप से गौर करते हुए और वाहनों के आधुनिकीकरण और संसाधनों के अनुकूलतम उपयोग वाली अर्थव्यवस्था के महत्व को पहचानते हुए कई वाणिज्यिक वाहन और यात्री वाहन विनिर्माताओं ने जमा प्रमाणपत्र (स्क्रैपेज सर्टिफिकेट) के बदले सीमित अवधि के लिए छूट देने पर सहमति जताई है।'' इसमें कहा गया है कि वाणिज्यिक वाहन मैन्यूफैक्चरर दो साल और यात्री वाहन विनिर्माता एक साल के लिए छूट देने को तैयार हैं। बयान में कहा गया है कि ये छूट पुराने वाहनों को कबाड़ में तब्दील करने के लिए प्रोत्साहित करेगी। इससे सड़कों पर सुरक्षित, स्वच्छ और अधिक दक्ष वाहनों का चलना सुनिश्चित होगा। बयान में आगे कहा गया कि मर्सिडीज बेंज इंडिया ने 25,000 रुपये की सीधी छूट देने की पेशकश की है, जो सभी मौजूदा रियायतों के अतिरिक्त होगी।

बयान के अनुसार, मारुति सुजुकी इंडिया लिमिटेड, टाटा मोटर्स, महिंद्रा एंड महिंद्रा, ह्युंदई मोटर इंडिया, किआ मोटर्स, टोयोटा किर्लोस्कर मोटर, होंडा कार्स, जेएसडब्ल्यू एमजी मोटर, रेनो इंडिया, निसान इंडिया और स्कोडा फॉक्सवैगन इंडिया जैसे यात्री वाहन विनिर्माता वाहनों को कबाड़ में बदलने के बदले नई गाड़ी लेने पर छूट देंगे। पिछले छह महीनों में कार मालिक के स्क्रैप किए गए यात्री वाहन के बदले नई कार लेने पर शोरूम कीमत का 1.5 प्रतिशत या 20,000 रुपये (जो भी कम हो) की छूट दी जाएगी। टाटा मोटर्स, वोल्वो आयशर, अशोक लेलैंड, महिंद्रा एंड महिंद्रा, फोर्स मोटर्स जैसे वाणिज्यिक वाहन विनिर्माता 3.5 टन से अधिक के वाणिज्यिक कार्गो वाहन के लिए शोरूम कीमत के तीन प्रतिशत के बराबर छूट की पेशकश करेंगे। सूत्रों ने बताया कि इस बैठक में वाहन उद्योग के टॉप अधिकारी शामिल हुए। इनमें सियाम के अध्यक्ष विनोद अग्रवाल, मारुति सुजुकी इंडिया के प्रबंध निदेशक और मुख्य कार्यपालक अधिकारी हिसाशी ताकेउची, टाटा मोटर्स के कार्यकारी निदेशक गिरीश वाघ, अशोक लेलैंड के प्रबंध निदेशक और सीईओ शीनू अग्रवाल और टीवीएस मोटर कंपनी के सीईओ के एन राधाकृष्णन शामिल हैं।

मारुति सुजुकी की नजर 2025-26 तक छोटी कारों के पुनरुद्धार, ग्रामीण विस्तार और ईवी निर्यात पर: आरसी भार्गव

परिवहन विशेष न्यूज

नई दिल्ली। घरेलू वाहन निर्माता कंपनी मारुति सुजुकी का ध्यान एसयूवी बाजार पर है, जहां बिक्री में उछाल देखने को मिल रहा है। हालांकि, कंपनी की 43वीं वार्षिक आम बैठक (एजीएम) के दौरान चेयरमैन आरसी भार्गव ने इस बात पर जोर दिया कि कंपनी अपनी छोटी कार लाइनअप के लिए प्रतिबद्ध है और 2025-26 तक इस सेगमेंट में सुधार की उम्मीद है।

उन्होंने कहा, ₹हमारा दृढ़ विश्वास है कि हमारी आर्थिक और सामाजिक परिस्थितियों में कम लागत वाली और छोटी कारें आवश्यक हैं। मांग में अस्थायी गिरावट से हमारी रणनीति में कोई बदलाव नहीं आने वाला है।₹

मारुति सुजुकी की छोटी कारों की बिक्री 2023 की शुरुआत से ही घट रही है। कंपनी के नवीनतम बिक्री आंकड़ों के अनुसार, अप्रैल-जुलाई 2024 में इसके मिनी और कॉम्पैक्ट सेगमेंट वाहनों की बिक्री में पिछले साल की समान अवधि की तुलना में लगभग 12% की गिरावट आई है। इसके विपरीत, इसी अवधि के दौरान इसके यूटिलिटी व्हीकल सेगमेंट की बिक्री में 16.44% की वृद्धि देखी गई।

2023 के मध्य में जिम्नी और फ्रोंक्स के लॉन्च ने एसयूवी बाजार में मारुति की सफलता में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। बलेनो, सेलेरियो, डिजायर, इग्निस, स्विफ्ट और वैगनआर जैसे प्रमुख मॉडल कंपनी की रणनीति के केंद्र में बने हुए हैं, जिनकी कीमतें लगभग ₹5-8 लाख के बीच हैं।

मारुति सुजुकी ने पुष्टि की है कि भारतीय बाजार के लिए उसका पहला ऑल-इलेक्ट्रिक वाहन, ईवीएक्स जनवरी 2025 में उत्पादन शुरू करेगा। ईवीएक्स का उत्पादन मारुति सुजुकी के हाल ही में अधिग्रहित सुजुकी मोटर गुजरात प्लांट में किया जाएगा और यह टाटा नेक्सन ईवी, आगामी हुंडई क्रेटा ईवी और होंडा एलिवेट ईवी जैसे प्रतिद्वंद्वियों के खिलाफ मध्यम आकार के इलेक्ट्रिक एसयूवी बाजार में प्रतिस्पर्धा करने के लिए तैयार है।

2024-25 की पहली तिमाही में मारुति सुजुकी का उत्पादन सालाना आधार पर 7.4% बढ़कर 4,96,000 यूनिट हो गया, हालांकि बिक्री केवल 1.2% बढ़कर 4,27,000 यूनिट हो गई। इस उत्पादन वृद्धि के बावजूद, भारतीय कार बाजार में 40% हिस्सेदारी रखने वाली कंपनी ने लंबित ऑर्डर या बिना बिकी इन्वेंट्री के बारे में विवरण का खुलासा नहीं किया है।

मंदी के लिए कई कारक जिम्मेदार हैं, जिसमें उपभोक्ता मांग में कमी और डीलरों के पास स्टॉक में वृद्धि शामिल है। फेडरेशन ऑफ ऑटोमोबाइल डीलर्स एसोसिएशन (फाडा) की रिपोर्ट के अनुसार डीलरों के पास लगभग 7,30,000 बिना बिके वाहन हैं, जबकि सोसायटी ऑफ इंडियन ऑटोमोबाइल मैन्युफैक्चरर्स (सियाम) के अनुमान के अनुसार लगभग 4,00,000 वाहन बिना बिके हैं।

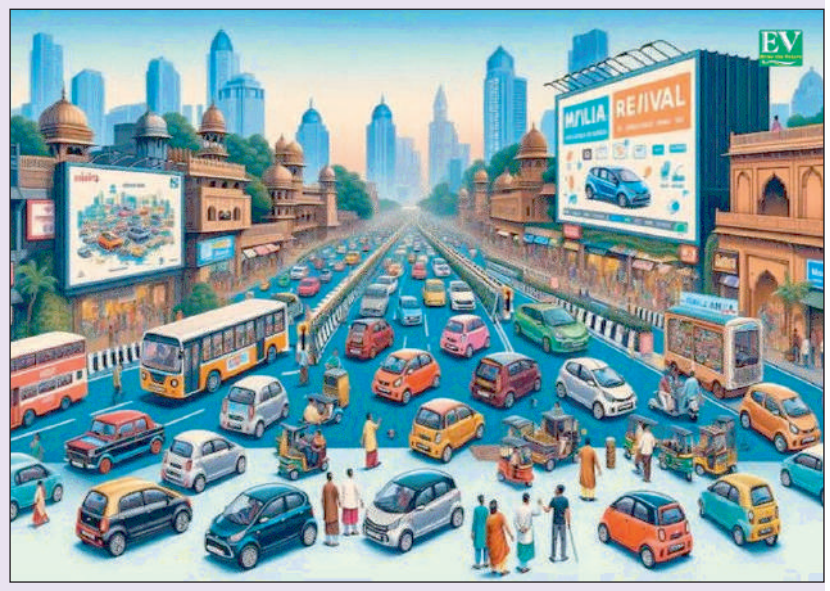

एजीएम में भार्गव ने भारत की आर्थिक और सामाजिक स्थितियों को देखते हुए छोटी कारों के महत्व पर प्रकाश डाला और कहा कि मारुति सुजुकी ग्रामीण क्षेत्रों और छोटे शहरों में अपनी बिक्री और सेवा नेटवर्क का विस्तार कर रही है ताकि पहुंच में सुधार हो सके। कंपनी अपनी उत्पादन क्षमता भी बढ़ा रही है, खरखौदा प्लांट से वाहनों की बिक्री 2025-26 में बढ़ने की उम्मीद है।

उन्होंने गुरुग्राम स्थित ऑटोमेकर के सामने आने वाली इन्वेंट्री चुनौतियों पर भी बात करते हुए कहा, ₹हम ग्रामीण क्षेत्रों और छोटे शहरों में अपने बिक्री और सेवा नेटवर्क को और मजबूत कर रहे हैं। कर्मचारियों और सहयोगियों के साथ साझेदारी और टीमवर्क की हमारी अवधारणा यह सुनिश्चित करती है कि सभी हमारे साथ आगे बढ़ें। हम अकेले समृद्धि का द्वीप नहीं बन सकते।₹

भार्गव ने कहा कि मारुति सुजुकी बाजार की मांग के अनुरूप अपनी उत्पादन प्रक्रियाओं को बेहतर बना रही है, जिससे अधिक उत्पादन या कमी का जोखिम कम हो जाएगा।

भार्गव ने कहा कि निर्यात क्षेत्र मारुति सुजुकी के लिए एक और विकास क्षेत्र है, कंपनी को इस साल 3,00,000 इकाइयों को पार करने की उम्मीद है। उन्होंने खुलासा किया कि मारुति सुजुकी द्वारा उत्पादित इलेक्ट्रिक कारों का पहला बैच यूरोप और जापान को निर्यात किया जाएगा, जिसमें फ्रोंक्स मॉडल पहले ही जापान भेजा जा चुका है।

फॉर्च्यूनर को चुनौती देने वाली एसयूवी को सस्ते में खरीदने का बेहतरीन मौका, मिल रहा छह लाख का डिस्काउंट

परिवहन विशेष न्यूज

भारत में वाहन निर्माताओं की ओर से अपनी कारों और एसयूवी पर हर महीने हजारों लाखों रुपये के डिस्काउंट ऑफर दिए जाते हैं। फुल साइज एसयूवी सेगमेंट में टोयोटा फॉर्च्यूनरको चुनौती देने वाली जेएसडब्ल्यू एमजी मोटर्स की Gloster को भारी बचत के साथ खरीदने का मौका मिल रहा है।

नई दिल्ली। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक ब्रिटिश वाहन निर्माता JSW MG की Gloster SUV को खरीदने पर लाखों रुपये की बचत की जा सकती है। इस एसयूवी पर कितना डिस्काउंट मिल रहा है। इसमें किस तरह के फीचर्स को दिया जाता है। हम आपको इस खबर में बता रहे हैं।

होगी लाखों रुपये की बचत

रिपोर्ट्स के मुताबिक JSW MG Gloster को खरीदने पर लाखों रुपये की बचत की जा सकती है। इस एसयूवी पर डीलरशिप स्तर पर छह लाख रुपये तक के डिस्काउंट ऑफर्स दिए जा रहे हैं। एसयूवी की एक्स शोरूम कीमत 38.80 लाख रुपये से शुरू होती है, ऐसे में इसे खरीदने पर तगड़ी बचत की जा सकती है।

क्यों मिल रहा ऑफर

जानकारी के मुताबिक कंपनी इस एसयूवी को मिड लाइफ फेसलिफ्ट देने की तैयारी कर रही है। ऐसे में बची हुई यूनिट्स का स्टॉक जल्द से जल्द खत्म करने के लिए ही कंपनी के अलावा डीलर्स की ओर से भी ऑफर दिया जा रहा है।

मिलते हैं बेहतरीन फीचर्स

JSW MG Gloster में कई बेहतरीन फीचर्स को दिया जाता है। इसमें ADAS, 7 टैरेन मोड्स, 4X4, पैनोरमिक सनरूफ, छह और सात सीटों का विकल्प, एंबिएंट लाइट्स, छह एयरबैग, एचएचसी, ईएसपी, एचडीसी, आई-स्मार्ट 2.0, एलईडी लाइट्स जैसे कई फीचर्स मिलते हैं।

मिलता है दमदार इंजन

JSW MG Gloster SUV में दो लीटर की क्षमता का डीजल टर्बो और ट्विन टर्बो इंजन दिया जाता है। जिससे इसे 161 पीएस की पावर और 373.5 न्यूटन मीटर का टॉर्क मिलता है। इसमें 8स्पीड ऑटोमैटिक ट्रांसमिशन मिलता है।

Toyota, Skoda से होता है मुकाबला

JSW MG Gloster एसयूवी को बाजार में फुल साइज एसयूवी सेगमेंट में ऑफर किया जाता है। इसका सीधा मुकाबला Toyota Fortuner, Jeep Meridian, Skoda Kodiaq, Nissan X-Trail जैसी एसयूवी के साथ होता है।

एलियांज पार्टनर्स इंडिया और पल्स एनर्जी ने ईवी स्वामित्व में बदलाव लाने के लिए की साझेदारी

परिवहन विशेष न्यूज

पल्स एनर्जी और एलियांज पार्टनर्स इंडिया के बीच रणनीतिक गठबंधन का उद्देश्य पूरे देश में इलेक्ट्रिक वाहनों (ईवी) के स्वामित्व के अनुभव में क्रांतिकारी बदलाव लाना है।

पल्स एनर्जी के अत्याधुनिक रोमिंग-हब-ए-ए-सर्विस प्लेटफॉर्म को एलियांज पार्टनर्स के विशाल मोबिलिटी असिस्टेंस नेटवर्क के साथ एकीकृत करके, सहयोग का उद्देश्य एलियांज पार्टनर्स के ग्राहकों के लिए ईवी स्वामित्व अनुभव को बेहतर बनाना है। संगठन ईवी उपयोगकर्ताओं को एक सहज और सर्वांगीण अनुभव प्रदान करेगा, जो रेंज चिंता, चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर तक पहुंच और तकनीकी सहायता जैसी उनकी मुख्य चिंताओं को दूर करेगा।

इस साझेदारी से ग्राहकों को कई नई सुविधाएँ और लाभ मिलेंगे, जिसमें उन्हें चार्जर के स्थानों तक वास्तविक समय में पहुँच, चार्जिंग प्रक्रियाओं पर रिमोट कंट्रोल और रेंज की चिंता को कम करने के लिए रोमिंग क्षमताओं के साथ सहज चार्जिंग का आनंद मिलेगा। एक अभिनव ईवी ट्रिप प्लानर तनाव मुक्त यात्रा के लिए उपलब्ध चार्जर और आस-पास की सुविधाओं के साथ मार्गों का नक्शा तैयार करेगा।

इसके अतिरिक्त, चैटबॉट के माध्यम से एआई-संचालित तकनीकी सहायता किसी भी ईवी और चार्जर से संबंधित समस्याओं के लिए तत्काल समाधान प्रदान करेगी।

एलियांज पार्टनर्स इंडिया की प्रबंध निदेशक चारू कौशल ने कहा, ₹यह साझेदारी एलियांज पार्टनर्स इंडिया की स्थायी गतिशीलता के प्रति प्रतिबद्धता को दर्शाती है। पल्स एनर्जी के साथ सहयोग करना भारत में ईवी स्वामित्व अनुभव को बढ़ाने के हमारे प्रयासों में एक महत्वपूर्ण मील का पत्थर है।

उनकी उन्नत प्लेटफॉर्म को अपनी सेवाओं के साथ एकीकृत करके, हम एक निर्बाध, अभिनव समाधान प्रदान करने के लिए प्रतिबद्ध हैं जो टिकाऊ गतिशीलता का समर्थन करता है और ग्राहकों की बढ़ती जरूरतों को पूरा करता है।"

पल्स एनर्जी के सह-संस्थापक अखिल जयप्रकाश ने कहा, "एलियांज पार्टनर्स के साथ साझेदारी भारत में ईवी इंफ्रास्ट्रक्चर को बदलने के हमारे मिशन में एक बड़ा कदम है। एलियांज पार्टनर्स इंडिया के व्यापक मोबिलिटी सहायता नेटवर्क के साथ हमारे प्लेटफ़ॉर्म की क्षमताओं को मिलाने से हम वास्तव में एकीकृत समाधान पेश करने में सक्षम होंगे जो ईवी स्वामित्व को सरल बनाता है और इलेक्ट्रिक वाहन बाजार के विकास का समर्थन करता है।"

विश्व बैंक रिपोर्ट को खारिज करे भारत

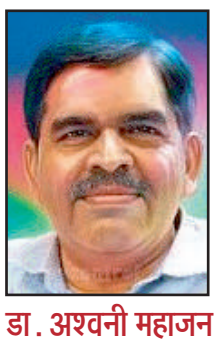

डा. अश्वनी महाजन

विश्व बैंक को यह अवश्य पता होना चाहिए कि वर्तमान में क्रय शक्ति समता के आधार पर भारत की प्रति व्यक्ति आय 10000 अमेरिकी डॉलर से ऊपर पहुंच रही है, जो अमेरिका की प्रति व्यक्ति आय का 10 फीसदी से भी अधिक है'...

एक अगस्त 2024 को विश्व बैंक ने अपनी विश्व विकास रिपोर्ट 2024 जारी की। इसमें आर्थिक शब्दावली का इस्तेमाल करते हुए विश्व बैंक द्वारा न केवल भारत बल्कि इंडोनेशिया, वियतनाम, दक्षिण अफ्रीका जैसी उभरती अर्थव्यवस्थाओं के बारे में भी नकारात्मक टिप्पणी की गयी है। भारत के संदर्भ में विश्व विकास रिपोर्ट का कहना है कि भारत को अमेरिका की प्रति व्यक्ति आय के एक-चौथाई तक पहुंचने में 75 साल लगेंगे। यानी एक तरह से भारत के 2047 तक विनिर्माण विकास पर सवार होकर विकसित अर्थव्यवस्था बनने के संकल्प का मजाक उड़ाने की कोशिश की गई है। विश्व बैंक का दावा है कि यह रिपोर्ट 108 मध्यम आय वाली अर्थव्यवस्थाओं के आंकड़ों पर आधारित है, जिनमें दुनिया की 75 प्रतिशत आबादी रहती है और जो सकल घरेलू उत्पाद का 40 प्रतिशत उत्पन्न करते हैं। विश्व बैंक की रिपोर्ट ने भारत और इंडोनेशिया की औद्योगिक नीति की आलोचना करते हुए कहा है कि बहुत अधिक विकास के आधार पर तेजी से अमीर बनने के बजाय उन्हें लंबी अवधि के लिए धीमी लेकिन निरंतर वृद्धि का लक्ष्य रखना चाहिए। रिपोर्ट में सुझाव दिया गया है कि मध्यम आय वाले देशों को घरेलू प्रौद्योगिकी विकास का मोह छोड़ देना चाहिए और अन्य देशों, विशेष रूप से विकसित देशों और उनकी कंपनियों द्वारा विकसित प्रौद्योगिकी का उपयोग करना चाहिए, क्योंकि स्वयं की प्रौद्योगिकी विकसित करने का प्रयास, संसाधनों की बर्बादी होगी। इस मामले में, इस रिपोर्ट ने सरकारी सहायता देकर विदेशी प्रौद्योगिकी को अपनाने को प्रोत्साहित करने के लिए दक्षिण कोरिया की प्रशंसा करते हुए, ब्राजील की यह कहकर आलोचना की है कि उसने अंतरराष्ट्रीय बौद्धिक संपदा पर कर लगाकर विदेशी प्रौद्योगिकी को हतोत्साहित किया, जिसके लिए उसे परिणाम भुगतने पड़े।

भारत को आगाह किया गया है कि वह अपनी खुद की तकनीक विकसित करने की कोशिश न करे, जैसा कि मलेशिया और इंडोनेशिया ने करने की कोशिश की है। हैरानी की बात यह है कि भारत की सेमीकंडक्टर नीति और रक्षा आत्मनिर्भरता नीति की भी आलोचना की गई है। दि इकोनॉमिस्ट लिखता है कि भारत द्वारा 509 रक्षा उत्पादों के आयात पर प्रतिबंध लगाने के बाद भारत दुनिया के शीर्ष 25 रक्षा निर्यातकों की सूची से बाहर हो गया है। रिपोर्ट में प्रसिद्ध अर्थशास्त्री शुम्पीटर के नाम का इस्तेमाल करते हुए लेखकों ने यह कहने की कोशिश की है कि भारत में सरकारी संरक्षण और नई (विदेशी) फर्मों के प्रवेश पर प्रतिबंधों के कारण, कुशल फर्म भी कुशल नहीं रह पाएंगी। रिपोर्ट कहती है कि जहां एक औसत अमेरिकी फर्म 40 साल में आकार में 7 गुना बढ़ जाती है, वहीं भारत में यह केवल दोगुनी होती है।

विश्व बैंक की रिपोर्ट में कहां गलती हुई : ऐसा लगता है कि विश्व बैंक इस बात से नाराज है कि भारत सरकार ने टेस्ला इलेक्ट्रिक कार कंपनी के प्रस्ताव और शर्तों को खारिज कर दिया है और आयात शुल्क में पूरी छूट देने से इनकार कर दिया है। विश्व बैंक की रिपोर्ट के लेखकों को शायद यह नहीं पता कि भारत के ऑटोमोबाइल उद्योग का दुनिया में अपना एक अलग स्थान है, जिसके कारण देश में ऑटोमोबाइल कंपनियों ने बड़ी मात्रा में इलेक्ट्रिक वाहनों का निर्माण शुरू कर दिया है। भारत ऑनलाइन लेन-देन (विश्व प्रसिद्ध यूपीआई) में तेजी से विकास कर रहा है, जिसे खुद विश्व विकास रिपोर्ट ने भी स्वीकार किया है कि इसने किस तरह से व्यवसायों, खासकर छोटे व्यवसायों में क्रांति ला दी है। आज भारत का यूपीआई ऑनलाइन लेन-देन में दुनिया में अपनी जगह बना रहा है और कई देश इसे अपनाने के लिए उत्सुक हैं। चूंकि भारत ने यह तकनीक विकसित कर ली है, इसलिए वह स्विफ्ट जैसी अपनी खुद की भुगतान प्रणाली बना सकता है। भारत ने मित्र देशों से रुपए में तेल खरीदने जैसे लेन-देन करना शुरू कर दिया है, जो जाहिर तौर पर अमेरिका और यूरोप के देशों को पसंद नहीं है। भारत में इस तकनीक के विकसित होने के बाद वीजा और मास्टर कार्ड जैसी कंपनियां बाजार से लगभग बाहर हो गई हैं। अंतरिक्ष क्षेत्र एक और उदाहरण है जहां भारत ने अपनी स्वदेशी तकनीक विकसित कर पीएसएलवी और चंद्रयान जैसी परियोजनाओं को सफलतापूर्वक लॉन्च किया। आज स्थिति यह है कि चंद्रयान बनाकर भारत चंद्रमा के अंधेरे हिस्से में पहुंचने वाला पहला देश बन गया। जिस लक्ष्य के लिए अमेरिका को 166 अरब डॉलर खर्च करने पड़े, भारतीय वैज्ञानिकों ने उसे सिर्फ 615 करोड़ रुपए में हासिल कर लिया। जबकि विश्व बैंक को समझना होगा कि पिछले 5 वर्षों में भारत का रक्षा निर्यात कई गुना बढ़ गया है और भारत रक्षा उत्पादों के लिए आकर्षण का केंद्र बन गया है। भारत आज बड़ी तोपों, मिसाइलों, राइफलों और यहां तक कि लड़ाकू विमानों के निर्यात में भी आगे निकल रहा है। नहीं भूल सकते कि जब भारत ने इन देशों से अंतरिक्ष क्षेत्र में तकनीक मांगी थी, तो भारत की मांग को सिरे से खारिज कर दिया गया था।

रक्षा क्षेत्र में भारत की बढ़ती भूमिका को लेकर विश्व बैंक का चिंतित होना स्वाभाविक है, क्योंकि इसके साथ ही विकसित औद्योगिक देशों के रक्षा बाजार अब सिकुड़ रहे हैं और दुनिया रक्षा वस्तुओं के लिए भारत की ओर रुख कर रही है। विश्व बैंक यह क्यों भूल जाता है कि इन सभी तथाकथित 'गलतियों' के बावजूद भारत दुनिया की सबसे तेजी से बढ़ती अर्थव्यवस्था बना हुआ है, जबकि विकसित देश भयंकर मुद्रास्फीति और संकुचन या ठहराव की स्थिति से गुजर रहे हैं। अधिकांश यूरोपीय देश सबसे खराब मुद्रास्फीति, आर्थिक गिरावट और कर्ज के बोझ से गुजर रहे हैं और भारत भुगतान संतुलन में घाटे से बाहर आ रहा है। रुपए में पहले से बेहतर स्थिरता है, बुनियादी ढांचे में लगातार सुधार हो रहा है, बौद्धिक संपदा में निरंतर प्रगति हो रही है और पहले की तुलना में कई गुना अधिक पेटेंट दिए जा रहे हैं, 2023 में ही भारतीय पेटेंट कार्यालय द्वारा एक लाख पेटेंट दिए गए। 2024-25 के केंद्रीय बजट में देश में नवाचार को बढ़ावा देने के लिए एक लाख करोड़ रुपए का कोष बनाया गया है। बहुआयामी गरीबी में अभूतपूर्व कमी आई है और सभी बेघरों को घर दिए जा रहे हैं। गरीबों को सरकारी सहायता, बिजली, पानी, शौचालय, शिक्षा, स्वास्थ्य सुविधाओं की व्यवस्था गरीबों के जीवन में बदलाव ला रही है।

इन सबके लिए संयुक्त राष्ट्र के यूएनडीपी जैसी संस्थाओं द्वारा भारत की प्रशंसा की जा रही है। विश्व बैंक को यह अवश्य पता होना चाहिए कि वर्तमान में क्रय शक्ति समता के आधार पर भारत की प्रति व्यक्ति आय 10000 अमेरिकी डॉलर से ऊपर पहुंच रही है, जो निश्चित रूप से अमेरिका की प्रति व्यक्ति आय का 10 फीसदी से अधिक है। इसलिए, अगले 23 वर्षों में उच्च आय वाला देश बनने के भारत के संकल्प का मजाक उड़ाना निश्चित रूप से उचित नहीं है। कई आलोचकों का मानना है कि यदि विश्व बैंक भारत के विकास के मार्ग की आलोचना कर रहा है, तो निश्चित रूप से भारत का विकास का मार्ग सही है। अतीत में भी विश्व बैंक और अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष द्वारा विकसित देशों के इशारे पर कई शर्तें लगाकर भारत के मार्ग में बाधा डालने की कोशिश की गयी, और विश्व बैंक ऐसी रिपोर्टों के माध्यम से अपना एजेंडा आगे बढ़ाने की कोशिश कर रहा है। वर्तमान रिपोर्ट के लेखकों को 'मध्यम आय जाल' के नाम पर अपने तर्कों को सही साबित करना है। उन्हें पता होना चाहिए कि आत्मनिर्भर भारत की जो रणनीति अपनाई जा रही है, वह विश्व बैंक द्वारा बताए जा रहे निरर्थक सिद्धांतों पर आधारित नहीं है, बल्कि यह रणनीति अतीत की सीखों और वैश्वीकरण के अंधे रास्ते से मिली सीखों का परिणाम है। भारत के नीति-निर्माताओं से अनुरोध है कि ऐसी रिपोर्टों को न केवल खारिज किया जाए, बल्कि सरकार भी विरोध दर्ज कराए।

संपादक की कलम से

बीड़ तेरा मर्ज यह है

हिमाचल अपनी विडंबनाओं और अस्पष्ट नीतियों के बीच फंसकर इसलिए भी रह गया, क्योंकि तुकबंदी का विकास केवल सियासत का गहना बन गया है। एक ही परिदृश्य के विरोधाभास में जब दूसरा दृश्य पनपता है, तो टकराव की स्थिति में ठहराव आ जाता है। मौजूदा राज्य सरकार भी ऐसे जनांदोलनों को समझने के द्वंद्व में फंसी है। बीड़-बिलिंग का सुनहरा पक्ष इलाके को आर्थिक पैगाम दे रहा है, लेकिन सुधरने को पीढ़ियां तैयार नहीं। दो से नौ नवंबर के बीच पैराग्लाइडिंग का वर्ल्ड कप इस स्थान को आर्थिक संभावनाओं के नए कक्ष में ले जाएगा। पिछले दस सालों में हिमाचल में एकमात्र यह स्थान है जिसने पैराग्लाइडिंग की ख्याति से खुद को न केवल पर्यटन डेस्टिनेशन बनाया, बल्कि निजी निवेश के जरिए रोजगार के अवसर भी बढ़ाए हैं। पंजीकृत या गैर पंजीकृत होम स्टे व अन्य पर्यटन इकाइयों की शुमारी अब ढाई-तीन सौ तक पहुंचने वाली है। कई ट्रैवल-ट्रैकिंग एजेंसियों के कारण पर्यटन की महफिल बढ़ रही है, तो होटल इंडस्ट्री का पौधारोपण बीड़-बिलिंग से आगे निकल कर आसपास के छोटे-छोटे गांवों तक पहुंच गया है। पशुपालन करने वाले अब पर्यटक पालना तक पहुंच गए। खेतों में धान की जगह बेतरतीब होम स्टे उग आए। बाजार लंबे, लेकिन संकरे होने लगे। सडक़ों पर गाडियां परेशान करने लगीं, तो जल निकास की प्राकृतिक सोहबत बदलकर अतिक्रमण करने लगी। अभी इस दौर में कुछ और भी आएगा, चिलम से आगे चिट्टा घर तक आएगा। ऐसे में जनता को नए विकास का अगर भागीदार होना है, तो नए नियमों, नीतियों व कार्यक्रमों का समर्थक भी बनना होगा। बीड़-बिलिंग में विकसित होती पर्यटन आर्थिकी के समक्ष भविष्य की चुनौतियां भी हैं और अगर इन्हें यूं ही छोड़ दिया जाए तो ये कस्बे बिगड़े हुए कसोल बन जाएंगे। इसी परिप्रेक्ष्य में विशेष क्षेत्र विकास प्राधिकरण यानी साडा का दायरा बीड़-बिलिंग के आसपास खींचा गया है।

पहले सात गांव इसके तहत लाए गए थे, जबकि अब पांच नए जोड़ कर 'साडा' की प्रस्तुति में इलाके की प्लानिंग होगी। नए गांव इस पक्ष के विरोध में लामबंद हो रहे हैं और इस तरह भविष्य के सवाल पर सियासत का बवाल ऊंचे स्वर में गूंज रहा है। यही विडंबना हिमाचल के हर फैसले पर आमादा रही है। एक ओर वर्ल्ड पैराग्लाइडिंग प्रतियोगिता के प्रांगण में बीड-बिलिंग की अंतरराष्ट्रीय मान्यता इससे वैश्विक स्तर की अधोसंरचना व व्यवस्था चाहती है, तो दूसरी ओर जनता सिर्फ सत्ता की घोषणाओं-योजनाओं के नतीजे देखने के लिए ही खुद को आजमाना चाहती है। हमने हिमाचल को नागरिक दायित्व से दूर करके भ्रम के ऐसे मोहजाल में फंसा दिया, जहां हर आरजू का आसमान कर्जधारी राज्य है। दूसरा यह भी कि टीसीपी कानून की पालना से न सरकार की संवेदना, कार्यान्वयन और प्रतिज्ञा जाहिर हुई और न ही इसके उद्देश्यों से कोई मॉडल स्थापित हुआ। बेशक शहरी विकास योजनाएं बनीं या साडा की पहरेदारी का डंडा तैयार हुआ, लेकिन कसौटी पर कत्र्तव्य पूरा नहीं हुआ। जिस प्रदेश की जनता चूल्हा कर देना नहीं चाहती, उसे नियम समझाने के लिए कोई तो मॉडल सामने रखना होगा। मसलन बीड़-बिलिंग के साडा के तहत आने वाले बारह गांवों की पहचान से कहीं ज्यादा जरूरी है वहां के लिए भविष्य की एक 'क्षेत्र विकास योजना', लेकिन इतने लंबे डग जनता के सहयोग के बिना तो भरे नहीं जा सकते। जिस राज्य में विधायक यह मांग करते हैं कि उनके क्षेत्र की शहरी विकास योजना की हद से गांव हटा दें, वहां बीड़-बिलिंग के विधायक से उम्मीद कैसे करें कि वह 'साडा' के उद्देश्य को सुनिश्चित करेंगे। अब वक्त आ गया है जब पूरे प्रदेश को नगर एवं ग्राम योजना कानून के तहत लाकर, निर्माण गतिविधियों को एक आचार संहिता के अनुरूप अमल में लाया जाए।

राय

पेंशन योजनाओं की राजनीति

सरकारी कर्मचारियों की पेंशन की राजनीति भी भिन्न है। हरियाणा और जम्मू-कश्मीर में चुनाव घोषित हो चुके हैं और महाराष्ट्र, झारखंड में अगले माह चुनावों की घोषणा निश्चित है। चुनावों के मद्देनजर ही केंद्रीय कैबिनेट ने जिस 'यूनिफाइड पेंशन स्कीम' (यूपीएस) को स्वीकृति दी है, उससे 23 लाख से अधिक केंद्रीय कर्मचारियों को लाभ होगा। मोदी सरकार ने इस स्कीम को 'सुनिश्चित आर्थिक सुरक्षा' करार दिया है। अलग-अलग श्रेणियों में जो पेंशन बनेगी, वह 'सुनिश्चित' तौर पर सेवानिवृत्त हो रहे कर्मचारी को मिलेगी। पेंशन के साथ 'महंगाई राहत' को भी जोड़ा गया है। यदि राज्य सरकारें भी इस नई घोषित स्कीम से जुडऩा चाहती हैं, तो कुल 90 लाख के करीब कर्मचारी इसके दायरे में होंगे। यह स्कीम 1 अप्रैल, 2025 से लागू होगी। इससे पहले 'ओल्ड पेंशन स्कीम' (ओपीएस) थी, जिसमें संशोधन कर तत्कालीन प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी ने 'न्यू पेंशन स्कीम' (एनपीएस) बनवाई थी। यह दीगर है कि केंद्र में सत्ता बदल गई, लेकिन प्रधानमंत्री डॉ. मनमोहन सिंह की सरकार ने एनपीएस को लागू किया। गौरतलब है कि चुनावी राजनीति के मद्देनजर ही केरल, राजस्थान, पंजाब, छत्तीसगढ़, कर्नाटक और हिमाचल की सरकारों ने ओपीएस लागू करने की घोषणाएं की थीं। तब राजस्थान और छत्तीसगढ़ में कांग्रेस की सरकारें थीं। अब भाजपा सरकारें हैं, लिहाजा राजनीति बदल गई है। महाराष्ट्र में भाजपा, शिवसेना और एनसीपी की 'महायुति सरकार' है। इधर केंद्र ने स्कीम की घोषणा की, उधर 'महायुति सरकार' ने भी स्वीकृति दे दी। यह विशुद्ध राजनीति है। बहरहाल सवाल है कि नई पेंशन स्कीम क्यों घोषित की गई है? यूपीएस में ओपीएस और एनपीएस के तत्त्व भी शामिल हैं। यह दोनों पेंशन योजनाओं के बीच का रास्ता है। पेंशन में आर्थिक सुधार किए जा सकते थे। अब राजनीति के मद्देनजर असमंजस बने रहेंगे कि यूपीएस लागू करें या ओपीएस को लागू करने के प्रयास किए जाएं।

बेशक यूपीएस की घोषणा से खासकर केंद्रीय कर्मचारी गदगद हैं, क्योंकि प्रधानमंत्री मोदी ने सीधे ही उनके संगठनों के साथ विमर्श किया। उनके पक्ष और तर्क सुने गए। बेशक मोदी सरकार ने 2023 में, पेंशन सुधार के संदर्भ में ही, एक उच्च स्तरीय कमेटी का गठन किया था। उसने कई देशों की पेंशन-व्यवस्था का अध्ययन किया। विश्व बैंक की रपटें भी पढ़ीं। अंततः यूपीएस की व्यवस्था और उसकी विशेषताएं तय की जा सकीं। भारत 144 करोड़ की आबादी का देश है, जिसमें 65-70 करोड़ ही कामगार हैं। उनमें भी केंद्र और राज्य सरकारों के करीब 90 लाख कर्मचारी हैं, जो पेंशनधारक रहेंगे और उनकी मृत्यु के बाद पत्नी या पति को 60 फीसदी पेंशन मिलती रहेगी। यूपीएस का सरकारी खजाने पर अतिरिक्त बोझ पडऩा निश्चित है। खुद सरकार ने बताया है कि नई योजना से, पहले वर्ष में ही, 6250 करोड़ रुपए का अतिरिक्त बोझ पड़ेगा। जो कर्मचारी एनपीएस के दौर में, 2004 में, सेवानिवृत्त हुए थे, उनके एरियर भुगतान के लिए भी 800 करोड़ रुपए खर्च करने पड़ेंगे। केंद्र और राज्य सरकारों के बजट में पेंशन पर खर्च करने के लिए बड़ा हिस्सा आवंटित कर रखा है। 2023-24 में केंद्र और राज्य सरकारों ने पेंशन के लिए क्रमशः 2.3 लाख करोड़ रुपए और 5.2 लाख करोड़ रुपए आवंटित किए थे। राज्यों और संघशासित क्षेत्रों के पेंशन के लिए बजट को इक_ा कर दिया जाए, तो 2023-24 में उनके राजस्व व्यय का अनुमानतः 12 फीसदी बनता है।

कर्ज पर कर्ज, जनता त्रस्त, माननीय मस्त

शराब की हर बोतल पर दुग्ध उत्पादन को प्रोत्साहित करने के लिए दस रुपए गाय उपकर और दस रुपए गाय के संरक्षण के लिए दूध उपकर लिया जा रहा है, फिर भी गौवंश सडक़ों पर क्यों है, इस विषय में सरकार के साथ समाज को सोचना होगा'...

लोकतंत्र के सभी स्तम्भ खोखले हो चुके हैं, सरकारें निरंकुश चल रही हैं, मतों को साधने के लिए फैसले लिए जा रहे हैं, खर्चे बढ़ रहे हैं तो जाहिर सी बात है कर्ज का बोझ भी बढ़ेगा, आमदनी का जरिया कोई है नहीं, फिर भी शौक पूरे किए जा रहे हैं। कर्ज पर कर्ज, जनता त्रस्त, लेकिन माननीय मस्त हैं। खाली खजाने पर असंवैधानिक पदों का बोझ, मित्रों को खुश करने की कवायद में पिस रहा आम आदमी किसी को दिखाई नहीं दे रहा। सत्ताधारियों को चिंता केवल सरकारों को चलाने की ही नहीं, पार्टी फंड के लिए पैसा जुटाने की भी है। महंगे चुनाव, बिकते किरदार, लालची अवाम के लिए मुफ्त की गारंटी, अपने वफादारों और मित्रों की हसरतें पूरा करने के लिए धन की आवश्यकता तो होगी ही, अब सत्ता पर अगर काबिज होना है तो हाईकमान को खुश करना भी एक मजबूरी हो जाता है। इसलिए सरकारें अप्रिय फैसले लेने से गुरेज नहीं करतीं। सत्ता के नशे में मदमस्त होकर जो फैसले लिए जाते हैं उनमें स्वयं हित देखा जाता है, प्रदेश और जनता का हित -अहित नहीं देखा जाता। आज प्रदेश के हालात कुछ ऐसे ही हैं। जनता नई आशाओं के साथ सरकारें बदलती है, परंतु हर बार हाथ वही आता है ढाक के तीन पात! हिमाचल में भी सरकार बदली, नया चेहरा नए मुख्यमंत्री कुछ नया होने की उम्मीद थी, परंतु सरकार के एकतरफा फैसलों से सरकार की छवि पर ग्रहण लग रहा है।

सब जानते हैं कि सरकारी खजाना खाली है, इसलिए मुफ्त बांटने में सरकार असमर्थ है, फिर भी किसी बाहरी दबाव के कारण घोषणा पत्र में की गई गारंटियों में से कुछ तो पूरी करनी हैं, इसी कारण से पिछली सरकार द्वारा चलाई गई योजनाओं पर कैंची चलना भी स्वाभाविक था, चाहे वो जनमानस के भले की ही क्यों न हों। निजी अस्पतालों की लूट का हवाला देकर निजी अस्पतालों को हिमकेयर योजना से बाहर करना, आयुष्मान भारत योजना में गड़बड़ी का हवाला देकर सरकार द्वारा केस ईडी को सौंपना जैसे कृत्यों से राजनीतिक दुश्मनों को किनारे लगाने की साजिश गली-मुहल्ले की चर्चा बन गई है। क्या सरकार ने जब ईडी को केस सौंपा होगा, तो अपने साथियों को आगाह नहीं किया होगा और उन्हें संभलने का मौका नहीं दिया होगा, सवाल तो यहां भी बहुत हैं। राजनीति में एक तीर से कई निशाने साधे जाते हैं। बस ईडी के बहाने यही सब हुआ। भले ही भाजपा की गुटबाजी और बेवकूफियों से सरकार चुनाव जीतती चली गई हो, परंतु सरकार के प्रति जनाक्रोश बढ़ता जा रहा है। अवैध खनन हो या ड्रग्स तस्करी, सरकार दोनों पर लगाम लगाने और कानून व्यवस्था को दुरुस्त करने में असफल रही है। पिछले दिनों पौधारोपण के दौरान खनन माफिया द्वारा सुलह विधानसभा क्षेत्र की एक पंचायत के प्रधान और उपप्रधान पर हुए जानलेवा हमले के बाद अपराधियों का खुले में घूमना भी सरकार को कटघरे में खड़ा करता है। अपराधियों को सरकार के नजदीकी का संरक्षण प्राप्त है, इस संदेह से भी इंकार नहीं किया जा सकता। सरकार द्वारा वर्षों पुरानी माइनिंग पॉलिसी तक को बदल कर माइनिंग के लिए भारी भरकम मशीनों के

प्रयोग की अनुमति देना भी कई प्रकार के संशय पैदा करता है।

पर्यावरण और संस्कृति को ताक पर रख कर लिए जा रहे फैसलों पर विवाद और विरोध दोनों का होना कोई नई बात नहीं है। कुछ दशक पहले मनाली में प्रोपोज्ड स्की विलेज पर विवाद और विरोध के बाद अब पालमपुर में बनने वाला टूरिज्म विलेज विवादों में घिर गया है। एक शैक्षणिक संस्थान की भूमि पर बनने वाले इस टूरिज्म विलेज पर पूर्व स्वास्थ्य मंत्री विपिन सिंह परमार ने सरकार पर गंभीर आरोप लगाए हैं तथा दुबई की किसी कम्पनी और माननीयों द्वारा वहां की मेहमाननवाजी का भी जिक्र किया है। शैक्षणिक संस्थान के कर्मचारियों, अध्यापकों, आम जनता के बाद अब विरोध राजनीतिक रूप भी अख्तियार कर चुका है। हैरानी है इतने विरोध के बावजूद सरकार पीछे हटने को तैयार नहीं, बल्कि एक कार्यकारी कुलपति से भूमि का एनओसी तक ले लिया गया। दाल में कुछ तो काला है, वर्ना वाइल्ड फ्लॉवर हॉल के लिए लम्बी मुकदमेबाजी के बाद भी सरकार अपनी भूमि फिर से किसी निजी क्षेत्र को सौंपने के लिए इतनी उतावली क्यों होती? टूरिज्म के नाम पर भ्रष्टाचार को बढ़ावा दिया जा रहा है। शैक्षणिक संस्थान की भूमि पर शिक्षा संस्थान के बदले जुआ और फूहड़पंथी को लाकर सरकार किसे फायदा पहुंचाने चली है, यह सवाल हर किसी के मानसपटल पर है। भ्रष्ट और नकारा अफसरशाही के बलबूते चल रही सरकार शानन पावर हाउस मामले में अब तक अपना पक्ष रखने में पूरी तरह से असफल रही है। खाली खजाना होने के बावजूद सरकार जमीनों के सर्कल रेट रिवाइज करने में आनाकानी कर किसे फायदा पहुंचा रही है, सवाल तो यह भी है। शराब की हर बोतल पर दुग्ध उत्पादन को प्रोत्साहित करने के लिए दस रुपए गाय उपकर और दस रुपए गाय के संरक्षण के लिए दूध उपकर लिया जा रहा है, फिर गौवंश सडक़ों पर क्यों है? पालमपुर के नगरी में बनी गौशाला बन कर तैयार हो जाने के बावजूद इसे प्रयोग में लाने के लिए विलंब क्यों हो रहा है?

उद्योग मंत्री हर्षवर्धन चौहान ने विधानसभा में प्रश्नकाल के दौरान जनवरी में कहा था कि हिमाचल प्रदेश सरकार ने शराब पर प्रति बोतल 10 रुपए के दूध उपकर से 90.78 करोड़ रुपए अर्जित किए हैं और यह आंकड़ा 100 करोड़ रुपए तक पहुंचने की संभावना है, तो फिर गौवंश के हिस्से का 100 करोड़ रुपया कहां गया? कब तक सरकारें टूरिज्म के नाम पर युवाओं को बहलाती-फुसलाती रहेंगी? टूरिज्म इंडस्ट्री केवल धनाढ्य व्यक्तियों के हित साधती है, गरीब तबका केवल नौकर बनकर रह जाता है, इसलिए उन्हें डेयरी खोलने, मछली उत्पादन, फल उत्पादन और कृषि के लिए प्रेरित किया जाना चाहिए।

पीए सिद्धार्थ

भूख नहीं है'

झुन्नू लाल आजकल एक दुर्गम इलाके में तैनात हैं। गोल-मटोल से झुन्नू हैं तो ख़ानदानी, मां-बाप का दिया सब कुछ है। शहर के बीचों-बीच कई एकड़ ज़मीन है, दो-दो घर हैं, मां-बाप की पेंशन है। सबसे बड़ी बात कि ख़ुद तो सरकार में बड़े अफसर हैं ही, पत्नी भी बड़े ओहदे पर हैं। लेकिन मोह इतना कि जेब से दमड़ी भी निकालनी हो तो दस मर्तबा सोचते हैं। सोचते रहते हैं कि क्या यह चीज़ इतनी ज़रूरी है कि इसके ऊपर ख़र्च किया जाए। इसी कशमकश में कई बार भूखे रह कर भी काम चला लेते हैं। देर शाम को सोचते हैं कि अभी तो खाया था दोपहर में। अब क्या खाना? पानी पीकर सो जाते हैं या फिर हिम्मत करके थोड़ा दूध पी लेते हैं या बिस्किट खाकर सो जाते हैं। बड़ी भूख हुई तो सुबह या दोपहर का कुछ फ्रिज में पड़ा होने पर अपनी क्षुधा शांत कर लेते हैं। नहीं तो नींद में छप्पन भोग का आनंद लेते हुए रात गुज़ार लेते हैं। एक बार उनकी पत्नी ने दफ्तर से छुट्टियां लीं तो झुन्नू बोले कि हो सकता है अगले साल मेरा ट्रांसफर हो जाए। बेहतर है बेटे को साथ लेकर दोनों घूमने आ जाओ। उत्साहित पत्नी हिल स्टेशन में घूमने की उमंग लेकर गोलू के साथ पहुंच गईं। पहुंचते-पहुंचते तीन बज चुके थे। रास्ते में दोनों ने यह सोचकर कुछ नहीं खाया कि झुन्नू जी के साथ लंच करेंगे। लेकिन हर बार की तरह झुन्नू जी बोले कि मुझे तो भूख है नहीं। तुम दोनों कुछ खा लो। तीनों पास के रेस्टोरेंट पहुंचे। घड़ी में चार बजते देख पत्नी और बेटे ने लंच की जगह स्नैक्स लेने का फैसला किया। हर बार की तरह झुन्नू जी दोनों को देखकर तृप्त होते रहे। हर बार की तरह पत्नी ने ही बिल अदा किया। बड़े साहिब को आया देख रेस्टोरेंट के मालिक ने उनसे कहा, 'मेम साहिब तो आज चार सौ मील का सफर तय करके आई हैं। थकी होंगी।

अगर आप कहें तो शाम के लिए बाज़ार से कोई लोकल सब्ज़ी मंगवा दूं।' लेकिन झुन्नू लाल बोले, 'अरे पांच बजे तो खाया है। रात को क्या भूख लगेगी? अगर कुछ होगा तो बाद में बता देंगे।' करीब सात बजे पत्नी बोलीं कि रात को भूख लगेगी। आप रेस्टोरेंट के मालिक को फोन करके दाल-रोटी के लिए बोल दें। झुन्नू लाल जी ने मन में यह सोचते हुए कि इनके आने से ख़र्च बढ़ जाता है, रेस्टोरेंट वाले को सिम्पल दाल-रोटी के लिए बोल दिया। करीब नौ बजे रेस्टोरेंट में पहुंचे तो रेस्टोरेंट के मालिक ने दाल-रोटी के साथ चावल, मिक्स वैज, रायता और सलाद भी सर्व करवा दिया। उसने सोचा कि आखिर इतने बड़े साहिब हैं। पैसे की तंगी तो है नहीं। फिर विभाग से भी दस तरह के काम पड़ते रहते हैं। साहिब से बना कर तो रखनी होगी। हर बार की तरह झुन्नू जी को फिर भूख नहीं थी। पत्नी और बेटे को भी ज़्यादा भूख नहीं थी। दोनों ने दाल के साथ एक-दो चपातियां ले लीं। कुछ देर बाद मेज पर सजे खाने को देखकर झुन्नू जी की भूख जाग उठी। लेकिन पत्नी और बेटे से बोले, 'मुझे भूख तो नहीं है। पर तुम लोगों के साथ देने के लिए कुछ खा लेता हूं।' इसके बाद झुन्नू जी ने देखते-देखते डोंगे में रखे सारे चावल, चार रोटियां, दाल, पूरी सब्ज़ी, रायता और सलाद साफ कर डाला। पत्नी और गोलू उन्हें हैरानी के साथ देखते हुए सोच रहे थे कि अगर भूख न होने के बाद यह आदमी इतना खा सकता है तो भूखा होने पर क्या करेगा? उधर झुन्नू जी ने खाना हजम करने के बाद हर बार की तरह उद्घोषणा की, 'मुझे भूख तो नहीं थी, पर तुम लोगों का साथ देने में इतना खा लिया है कि कल दिन भर भूख नहीं लगेगी। अरे हां, मैं पर्स घर में भूल आया हूं। तुम बिल दे देना।' इतना कहते-कहते उन्होंने मीठी सौंफ से मुंह भर लिया।

पेट्रोल-डीजल के रेट्स हो गए अपडेट, चेक करें कहां मिलेगा सबसे सस्ता फ्यूल

तेल कंपनियां हर दिन सुबह 6 बजे पेट्रोल-डीजल के दाम रिवाइज करती है। आज सुबह भी 27 अगस्त के लिए दाम जारी हो गए हैं। चूंकि सभी शहरों में इनके दाम अलग हैं तो गाड़ीचालक को लेटेस्ट रेट चेक करने के बाद ही तेल भरवाना चाहिए। आपको बता दें कि कुछ महानगरों और शहरों के मुकाबले सस्ता तेल राजधानी दिल्ली में मिल रहा है।

परिवहन विशेष न्यूज

नई दिल्ली। तेल कंपनियों ने 27 अगस्त (मंगलवार) के लिए फ्यूल प्राइस अपडेट कर दिये हैं। बता दें कि रोजाना सुबह 6 बजे इनकी कीमत अपडेट होती है। ऐसे में गाड़ीचालक को ताजा कीमत जान लेने के बाद ही तेल भरवाना चाहिए।

सभी शहरों में फ्यूल प्राइस अलग हैं। इसका मतलब है कि पटना, दिल्ली, नोएडा,चेन्नई में पेट्रोल-डीजल के भाव में अंतर है। दरअसल, तेल की कीमतों पर जीएसटी नहीं लगता है। इस पर राज्य सरकार वैट लगाती है। इस वजह से अलग-अलग शहरों में इसके अलग-अलग दाम है।

आइए, जानते हैं कि आज आपके शहर में एक लीटर पेट्रोल-डीजल कितने रुपये में मिल रहा है।

इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन लिमिटेड (IOCL) की ऑफिशियल वेबसाइट के अनुसार महानगरों और शहरों में पेट्रोल-डीजल की ताजा कीमत क्या है-

महानगरों में पेट्रोल- डीजल के दाम

- दिल्ली में एक लीटर पेट्रोल की कीमत 94.72 रुपये और डीजल की कीमत 87.62 रुपये प्रति लीटर है।
- मुंबई में पेट्रोल की कीमत 103.44 रुपये प्रति लीटर और डीजल की कीमत 89.97 रुपये प्रति लीटर है।
- कोलकाता में पेट्रोल की कीमत 104.95 रुपये प्रति लीटर और डीजल 91.76 रुपये प्रति लीटर है।
- चेन्नई में पेट्रोल की कीमत 100.75 रुपये प्रति लीटर और डीजल की कीमत 92.34 रुपये प्रति लीटर है।

अन्य शहरों में पेट्रोल- डीजल के दाम

- नोएडाः पेट्रोल 94.83 रुपये प्रति लीटर और डीजल 87.96 रुपये प्रति लीटर
- गुरुग्रामः पेट्रोल 95.19 रुपये प्रति लीटर और डीजल 88.05 रुपये प्रति लीटर
- बेंगलुरुः पेट्रोल 102.86 रुपये प्रति लीटर और डीजल 88.94 रुपये प्रति लीटर
- चंडीगढ़ः पेट्रोल 94.24 रुपये प्रति लीटर और डीजल 82.40 रुपये प्रति लीटर
- हैदराबादः पेट्रोल 107.41 रुपये प्रति लीटर और डीजल 95.65 रुपये प्रति लीटर
- जयपुरः पेट्रोल 104.88 रुपये प्रति लीटर और डीजल 90.36 रुपये प्रति लीटर
- पटनाः पेट्रोल 105.18 रुपये प्रति लीटर और डीजल 92.04 रुपये प्रति लीटर

1 अक्टूबर से लागू होंगे PPF-सुकन्या समृद्धि योजना के नए नियम, आपको होगा लाभ या नहीं

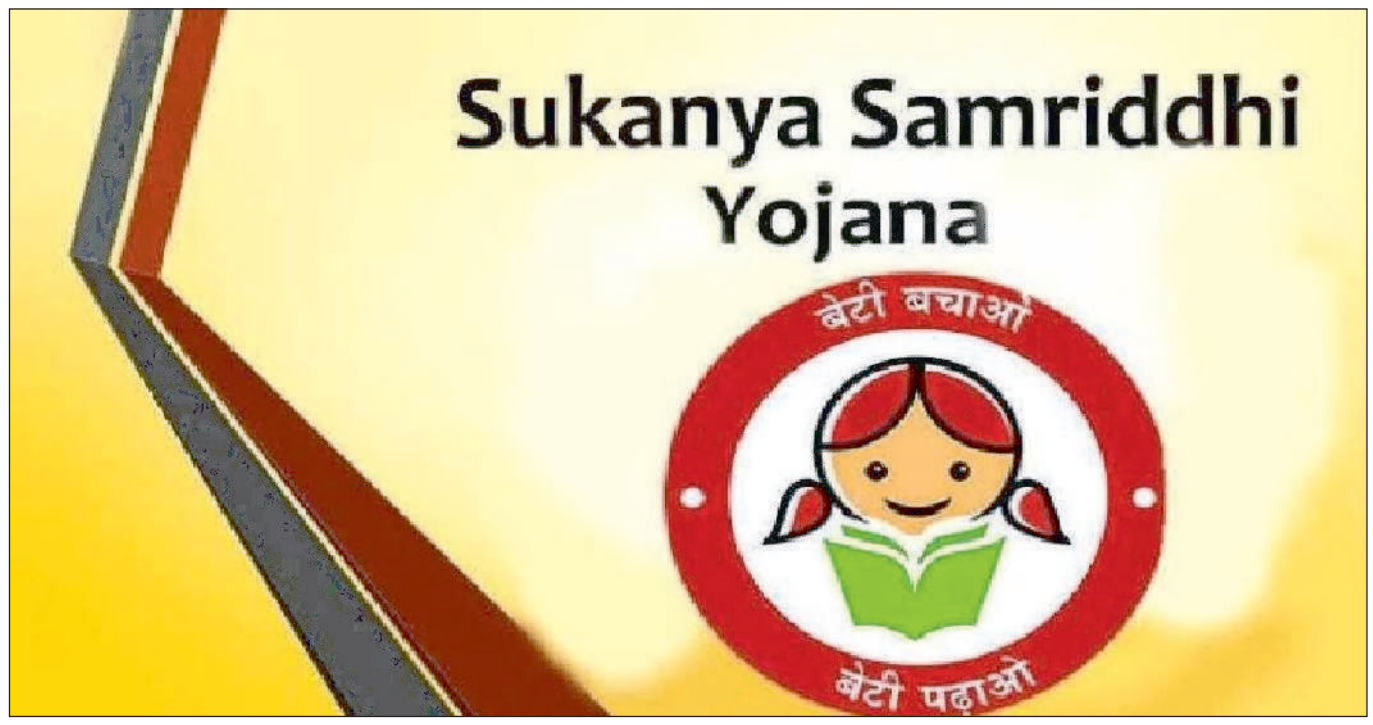

परिवहन विशेष न्यूज

1 अक्टूबर 2024 से स्मॉल सेविंग स्कीम्स के नियमों में बदलाव हो जाएगा। इन बदलावों को लेकर मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के इकोनॉमिक अफेयर्स डिपार्टमेंट ने सर्कुलर जारी किया। सर्कुलर के अनुसार अनियमित अकाउंट से लेकर रेगुलर अकाउंट के नियम 1 अक्टूबर से बदल जाएंगे। स्मॉव सेविंग स्कीम्स में पीपीएफ सुकन्या समृद्धि योजना शामिल हैं।

नई दिल्ली। मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के इकोनॉमिक अफेयर्स डिपार्टमेंट ने सर्कुलर जारी किया। इस सर्कलर के अनुसार 1 अक्टूबर 2024 से स्मॉल सेविंग्स स्कीम्स (Small Savings Schemes New Rules 2024) के लिए नए नियम जारी हो जाएंगे। यह नियम अनियमित अकाउंट से लेकर रेगुलर अकाउंट होल्डर्स के लिए भी हैं।

विभाग ने योजना में शामिल होने वाले सभी कैटेगिरी की पहचान की और हर कैटेगरी के लिए दिशानिर्देश जारी किए हैं।

नेशनल स्मॉल सेविंग्स अकाउंट्स (National Saving Scheme)

2 अप्रैल 1990 से पहले जितने अकाउंट ओपन किए गए हैं उनपर मौजूदा स्कीम रेट लागू होंगे। वहीं, पोस्ट ऑफिस सेविंग अकाउंट (POSA) में रेट प्लस 2 फीसदी का ब्याज मिलेगा। 1 अक्टूबर के बाद से इन दोनों अकाउंट पर 0 फीसदी का ब्याज मिलेगा।

2 अप्रैल 1990 के बाद ओपन हुए अकाउंट में भी मौजूदा स्कीम रेट लागू होगा। POSA में भी अकाउंट रेट लागू होगा। लेकिन 1 अक्टूबर के बाद इन दोनों अकाउंट पर कोई ब्याज नहीं मिलेगा।

अगर किसी के पास 2 से ज्यादा अकाउंट्स है तो तीसरे अतिरिक्त अकाउंट पर कोई ब्याज नहीं मिलेगा। इसके अलावा तीसरे अकाउंट का प्रिंसिपल अमाउंट भी वापस हो जाएगा।

पब्लिक प्रोविडेंट फंड (PPF)

अगर किसी नाबालिग का पीपीएफ अकाउंट ओपन हुआ है तो 18 साल तक उसे पोस्ट ऑफिस सेविंग अकाउंट (Post Office Saving Account) के हिसाब से ब्याज मिलेगा। जैसे ही नाबालिग की उम्र 18 साल की हो जाती है तब से उसे पीपएफ का ब्याज दर का लाभ मिलेगा। यहां तक कि इसमें मैच्योरिटी की कैलकुलेशन भी नाबालिग के 18वें जन्मदिन से होगी।

किसी निवेशक के पास एक से ज्यादा पीपीएफ अकाउंट (PPF Account) है तो सेकेंडरी अकाउंट को प्राइमरी अकाउंट से मर्ज कर दिया जाएगा। दो से ज्यादा अकाउंट में ओपनिंग की तारीश से 0 फीसदी का ब्याज मिलेगा।

एनआरआई के पीपीएफ अकाउंट होल्डर्स को भी 30 सितंबर तक POSA ब्याज मिलेगा। इसके बाद यानी अक्टूबर से ब्याज दर 0 फीसदी होगी।

सुकन्या समृद्धि योजना (Sukanya Samriddhi Yojana)

दादा-दादी ने सुकन्या समृद्धि अकाउंट (Sukanya Samriddhi Account) ओपन किया है तो ऐसे में अकाउंट को अभिभावक या बायोलॉजिकल माता-पिता को ट्रांसफर कर दी जाएगी। वहीं दो से ज्यादा अकाउंट होता है तो अतिरिक्त अकाउंट को बंद कर दिया जाएगा।

पोस्ट ऑफिसों के लिए निर्देश

पोस्ट ऑफिस को अकाउंट होल्डर्स या अभिभावकों की पैन कार्ड (Pan Card) और आधार कार्ड (Aadhaar Card) डिटेल्स कलेक्ट करनी होगी। पोस्ट ऑफिस की जिम्मेदारी हैं कि वह ग्राहक को इन नए नियमों के बारे में जानकारी दें और उन्हें गाइड करें।

बिना फाइन के अब भी दाखिल कर सकते हैं जीरो रिटर्न, मिलेंगे पांच धांसू फायदे

परिवहन विशेष न्यूज

जिन लोगों की कमाई टैक्स के दायरे में नहीं आती वे आईटीआर नहीं फाइल करते। लेकिन शून्य टैक्स देनदारी होने पर भी आपको जीरो रिटर्न फाइल करना चाहिए। इसमें आपको एक भी रुपया टैक्स नहीं देना होता इसलिए इसे जीरो रिटर्न कहते हैं। इसका मतलब कि इनकम टैक्स विभाग को यह बताना होता है कि आपकी कमाई टैक्सेबल इनकम से नीचे है इसलिए आपने टैक्स का भुगतान नहीं किया।

नई दिल्ली। इनकम टैक्स रिटर्न (ITR) दाखिल करने की आखिरी तारीख 31 जुलाई बीत चुकी है। अब इनकम टैक्स फाइल करने के लिए जुर्माना देना होगा। लेकिन, जीरो रिटर्न यानी शून्य टैक्स देनदारी वाला रिटर्न अब भी बिना किसी जुर्माने के फाइल किया जा सकता है। इसमें ध्यान रखने वाली बात यह है कि आप कोई डिडक्शन क्लेम नहीं कर सकेंगे। आपकी कुल कमाई सीधे बेसिक एग्जेम्पशन लिमिट के अंदर आनी चाहिए।

न्यू टैक्स रिजीम में बेसिक एग्जेम्पशन लिमिट सभी के लिए 3 लाख रुपये है। वहीं, ओल्ड टैक्स रिजीम में 60 साल से कम उम्र वालों के लिए बेसिक एग्जेम्पशन लिमिट 2.5 लाख रुपये है। 60-80 साल के लिए 3 लाख रुपये और 80 साल से अधिक उम्र के लोगों के लिए 5 लाख रुपये है। इस दायरे में आने वाले लोग बिना जुर्माने के रिटर्न फाइल कर सकते हैं।

आइए जानते हैं कि जीरो रिटर्न क्यों फाइल कर सकता है, इसे फाइल क्यों दाखिल किया जाता है, इसके क्या फायदे हैं।

आसानी से मिलता है लोन

इनकम टैक्स रिटर्न आपकी कमाई के सबूत के रूप में काम करता है। जब आप ITR फाइल करते हैं, तो वह इस बात पुख्ता सबूत हो जाती है कि आपकी किसी सोर्स से कमाई हो रही है। इससे आपकी क्रेडिट प्रोफाइल भी बन जाती है। इससे आपको बैंक या फिर NBFC (नॉन-बैंकिंग फाइनेंस कंपनीज) से कर्ज आपने में आसानी हो जाती है।

TDS का मिल जाएगा रिफंड

अगर आप नौकरीपेशा हैं और फॉर्म 15G/H जमा नहीं कर पाए, तो आपके वेतन से TDS (टैक्स डिडक्शन एट सोर्स) कटौती हो जाएगी। ऐसे में जीरो रिटर्न आपको नुकसान से बचा सकता है। इसकी मदद से आप उस TDS रकम की वापसी का क्लेम कर सकते हैं, जिसे आपकी कंपनी ने सैलरी से काटा है।

घाटा दिखाने का फायदा

अगर आप बिजनेस या शेयर मार्केट में निवेश करते हैं, तो आपको वित्त वर्ष के दौरान नुकसान भी हो सकता है। ऐसे में आप जीरो रिटर्न को फाइल करके अपने नुकसान को दिखा सकते हैं। जब आने वाले समय में आपको मुनाफा होगा, तो आप उस घाटे को टैक्सेबल इनकम में एडजस्ट करा सकते हैं। इससे आपकी टैक्स देनदारी कम हो जाएगी।

आसानी से मिलेगा वीजा

जीरो आईटीआर से आपको कई देशों का वीजा आसानी से मिल सकता है। कई बार वीजा अधिकारी विदेश यात्रा के लिए कुछ साल आईटीआर मांग लेते हैं। वे असल में आपके इनकम-लेवल को वेरिफाई करना चाहते हैं। ऐसे में बैंक स्टेटमेंट और दूसरे फाइनेंशियल डॉक्युमेंट के साथ आईटीआर की भी जरूरत पड़ सकती है।

स्कॉलरशिप के लिए भी मददगार

कई स्कॉलरशिप या फेलोशिप आय के हिसाब से दी जाती है। अगर आपने जीरो आईटीआर फाइल कर रखा है, तो आप अपनी इनकम लिमिट को आसानी से दिखा सकते हैं। इससे आपको उन सरकारी फेलोशिप को पाने में आसानी होगी, जो खासकर कम आय वाले परिवारवाले के लिए होती है।

सरकारी दफ्तर के नहीं लगाने पड़ेंगे चक्कर, समय और पैसे बचाने के लिए फोन में रखें ये ऐप

अगर आपके पास स्मार्टफोन है तो आप कई काम चंद मिनटों में निपटा सकते हैं लोगों का समय और पैसा बचें इसके लिए सरकार ने भी कई ऐप लॉन्च किये हैं। इन ऐप्स के जरिये आप कई जानकारी हासिल कर सकते हैं। इस लेख में हम आपको बताएंगे कि आपको अपने फोन में कौन-से सरकारी ऐप्स रखने चाहिए। पढें पूरी खबर..

नई दिल्ली। इस डिजिटल जमाने में स्मार्टफोन हमारी लाइफ का अहम हिस्सा बन गया है। अब पेमेंट से लेकर कई जरूरी काम हम आसानी से कर सकते हैं। लेकिन जब बात सरकारी काम की आती हैं तो अक्सर हमें गवर्नमेंट ऑफिस जाना पड़ता है। हालांकि, सरकार ने लोगों को सहूलियत दी है कि वह ऐप के जरिये कई काम निपटा लें या फिर उन्हें ऐप पर ही जानकारी मिल जाए।

जी हां, सरकार ने कई ऐप्स लॉन्च किये हैं। इन ऐप्स के जरिये आप कई डिटेल्स हासिल कर सकते हैं। यह सरकारी ऐप्स (Government Apps) कई कामों को आसान कर देता है। आज हम आपको बताएंगे कि आपको अपने फोन में कौन-से सरकारी ऐप्स रखने चाहिए, जिससे आप सरकारी दफ्तर के चक्कर काटने से बच सकते हैं।

उमंग ऐप (UMANG App)

एक ही जगह पर आधार कार्ड (Aadhaar Card), डिजिलॉकर (DigiLocker), पासपोर्ट (Passport) और ईपीएफओ (EPFO) जैसे सरकारी सर्विस की डिटेल्स जानने के लिए उमंग ऐप (UMANG) बहुत मददगार साबित है। दरअसल, उमंग ऐप को सभी सर्विसेज के लिए इंटीग्रेट कर दिया गया है। ऐसे में अब अलग-अलग कामों के लिए अलग-अलग मोबाइल ऐप्स की जरूरत नहीं पड़ेगी।

एमआधार ऐप (mAadhaar App)

आधार कार्ड से जुड़ी सभी जानकारी के लिए एमआधार ऐप (mAadhaar App) काफी मदद करता है। इस ऐप से आप आधार कार्ड डाउनलोड भी कर सकते हैं और साथ ही आधार कार्ड को अपडेट कर सकते हैं। इसके अलावा आधार से जुड़े कई कामों को निपटाने के लिए भी आप इस ऐप का इस्तेमाल कर सकते हैं।

डिजीलॉकर ऐप (DigiLocker App)

सरकार ने डिजिटल लॉकर की भी सुविधा दी है। डिजीलॉकर ऐप (DigiLocker App) एक तरह का डिजिटल लॉकर है। इसमें आप ऑनलाइन डॉक्यूमेंट्स को स्टोर कर सकते हैं। इस लॉकर की खासियत है कि इसे केवल आधिकारिक तौर पर ही इस्तेमाल किया जा सकता है। आप डिजीलॉकर में ड्राइविंग लाइसेंस, वाहन रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट, पैन कार्ड जैसे डॉक्यूमेंट्स को स्टोर कर सकते हैं।

MyGov

आम जनता की राय के लिए सरकार ने MyGov ऐप लॉन्च किया। यहां तक कि इस ऐप के जरिये आप सरकारी योजना और नीतियों के बारे में जानकारी भी पा सकते हैं।

mParivahan App

अपने व्हीकल से जुड़ी जानकारी को पाने के लिए mParivahan ऐप काफी कारगार साबित हो सकता है। इस ऐप की मदद से आप अपनी गाड़ी का रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट यानी RC डाउनलोड कर सकते हैं। इसके अलावा चालान की पेमेंट भी कर सकते हैं। व्हीकल की डिटेल्स को अपडेट करने के लिए भी आप इस ऐप का इस्तेमाल कर सकते हैं।

बर्गर किंग को बॉम्बे हाई कोर्ट से राहत, 6 सितंबर तक पुणे का रेस्तरां नहीं इस्तेमाल कर पाएगा ब्रांड का नाम

पिछले हफ्ते अमेरिकी की दिग्गज फास्ट-फूड कंपनी बर्गर किंग (Burger King) ने बॉम्बे हाई कोर्ट में याचिका दायर की थी। इस याचिका में कंपनी ने पुणे अदालत को चुनौती दी। अब हाई कोर्ट ने ट्रेडमार्क उल्लंघन के एक मामले में पुणे स्थित एक रेस्तरां 6 सितंबर तक ब्रांड का नाम इस्तेमाल करने पर रोक लगा दी। आइए इस रिपोर्ट में विस्तार से जानते हैं।

परिवहन विशेष न्यूज

नई दिल्ली। बॉम्बे हाई कोर्ट ने अमेरिकी की दिग्गज फास्ट-फूड कंपनी बर्गर किंग (Burger King) को अंतरिम राहत दी है। कोर्ट ने ट्रेडमार्क उल्लंघन के एक मामले में पुणे स्थित एक रेस्तरां 6 सितंबर तक ब्रांड का नाम इस्तेमाल नहीं कर सकता है। कोर्ट ने ब्रांड के नाम यूज करने पर रोक लगा दी।

पिछले हफ्ते बर्गर किंग ने हाई कोर्ट में याचिका दायर किया था। इस याचिका नें कंपनी ने पुणे की अदालत के आदेश को चुनौती दी थी। पुणे अदालत ने पुणे में स्थित बर्गर किंग भोजनालय के खिलाफ ट्रेडमार्क उल्लंघन का आरोप वाले मुकदमे को खारिज कर दिया था। जिला अदालत से मुकदमा खारिज होने के बाद बर्गर किंग ने हाई कोर्ट का दरवाजा खटखटाया।

बॉम्बे हाई कोर्ट ने लगाई रोक

बर्गर किंग के याचिका पर न्यायमूर्ति ए.एस. चंदुरकर और न्यायमूर्ति राजेश पाटिल की खंडपीठ ने 26 अगस्त 2024 (सोमवार) को कहा कि कोर्ट 6 सितंबर को कंपनी की अर्जी पर सुनवाई करेगी। कंपनी ने रेस्तरां के खिलाफ अंतरिम निषेधाज्ञा की मांग की अर्जी दी है। हाई कोर्ट ने कहा कि 2012 में पुणे की अदालत द्वारा जारी अंतरिम आदेश को बढ़ाया जाएगा। इसके तहत अब रेस्तरां ₹बर्गर किंग₹ नाम का इस्तेमाल नहीं कर सकता है।

फास्ट-फूड कंपनी ने भी रेस्तरां के खिलाफ ₹बर्गर किंग₹ नाम का इस्तेमाल पर रोक लगाने के लिए मुकदमा दायर किया था। कंपनी ने कहा कि रेस्तरां भी ₹बर्गर किंग₹ नाम का इस्तेमाल कर रहा है, जिससे कंपनी को कारोबार में नुकसान के साथ उसकी प्रतिष्ठा को भी नुकसान पहुंच रहा था।

2011 में दायर में हुआ था मुकदमा

बर्गर किंग कॉरपोरेशन ने साल 2011 में पुणे अदालत में मुकदमा दायर किया था। इस मुकदमें में कंपनी ने कहा था कि पुणे का एक रेस्तरां ₹बर्गर किंग₹ नाम का इस्तेमाल कर रहा है। जबकि भारत में दुकान खोलने से भी पहले अमेरिकी में बर्गर किंग कंपनी खुल गई थी।

पुणे कोर्ट तके अंतरिम आदेश के बाद अब कंपने ने उच्च न्यायालय में आवेदन दिया है। कंपनी ने अपील की है कि रेस्तरां ₹बर्गर किंग₹ नाम का इस्तेमाल न करें। कोर्ट से नाम का उपयोग करने पर अंतरिम रोक लगाने की मांग की है।

UPI से पेमेंट करने जितना आसान होगा कर्ज लेना, RBI ने कर दिया है इंतजाम

परिवहन विशेष न्यूज

नई दिल्ली। अभी लोन लेने की प्रक्रिया अभी काफी जटिल है। आपको तमाम कागजी कार्यवाही पूरी करनी पड़ती है। रोजाना बैंकों के चक्कर पड़ते हैं। लेकिन, सरकार अब इस प्रोसेस को काफी आसान करने वाली है। रिजर्व बैंक (RBI) के गवर्नर शक्तिकांत दास ने पेमेंट ऐप UPI की तरह यूनिफाइड लेंडिंग इंटरफेस (ULI) प्लेटफॉर्म लाने का एलान किया है।

RBI ने पिछले साल (अगस्त 2023) फ्रिक्शनलेस क्रेडिट यानी आसानी से कर्ज उपलब्ध कराने के लिए एक टेक्निकल प्लेटफॉर्म का पायलट प्रोजेक्ट लॉन्च था। केंद्रीय बैंक ने एक साल के पायलट प्रोजेक्ट के दौरान किसान क्रेडिट कार्ड (KCC) लोन, डेयरी लोन, MSME लोन, पर्सनल लोन और होम लोन पर फोकस किया, जिनकी डिमांड अधिक रहती है।

उपभोक्ताओं को क्या फायदा होगा?

अभी भी कई ऐप तुरंत कर्ज देने का दावा करते हैं। लेकिन, इन पर RBI का नियंत्रण काफी सीमित है। इन ऐप पर कई बार मनमानी और मानसिक उत्पीड़न करने का आरोप भी लगता है। लेकिन, ULI प्लेटफॉर्म वाले ऐप्स पर आरबीआई की सीधी नजर रहेगी, तो किसी गड़बड़ी की गुंजाइश भी कम रहेगी। इससे ऋण मूल्यांकन में काफी आसानी होगी, खासकर ग्रामीण और छोटे उपभोक्ताओं के लिए।

कर्ज लेना आसान कैसे होगा?

यूनिफाइड लेंडिंग इंटरफेस (ULI) से कर्ज लेने की पूरी प्रक्रिया आसान होगी। यह क्रेडिट प्रोसेसिंग में लगने वाले वक्त और पेपर वर्क को कम करने के हिसाब से डिजाइन किया गया है। यह ओपन आर्किटेक्चर को ओपन एप्लीकेशन प्रोग्रामिंग इंटरफेस (API) के साथ मिलाता है। इस वजह से फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन 'प्लग एंड प्ले' मॉडल में आसानी से जुड़ सकते हैं।

ULI प्लेटफॉर्म काम कैसे करेगा?

ULI ऐप आधार, ई-KYC, राज्य सरकार के लैंड रिकॉर्ड, पैन वैलिडेशन और अकाउंट एग्रीगेटर समेत अलग-अलग सोर्सेज से डेटा जुटाएगा। इसे डेयरी सहकारी समितियों से दूध के डेटा और घर या संपत्ति सर्च डेटा जैसी सर्विसेज के साथ भी लिंक किया जाएगा। आप जैसे यूपीआई में बस पिन डालकर पेमेंट कर देते हैं, उसी तरह से पात्र होने पर पिन डालकर कर्ज भी ले सकेंगे।

UPI जितना सफल होगा ULI?

यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस (UPI) को अप्रैल 2016 में लॉन्च हुआ था। अपने 8 साल के सफर में यूपीआई ने डिजिटल पेमेंट की दुनिया बदल कर रख दी। पान की दुकान से लेकर सब्जी के ठेले तक आपको क्यूआर कोड स्कैनर लगे दिख जाएंगे। कई अन्य देशों ने भी यूपीआई मॉडल को अपनाया है। ULI को यूपीआई वाली कामयाबी दोहराने के लिए यूजर को वैसा ही एक्सपीरियंस देना पड़ेगा।

संस्कारशाला: मानसिक स्वास्थ्य का महत्व

सोशल मीडिया की बढ़ती भूमिका और सामाजिक जुड़ाव की कमी

-डॉ. अंकुर शरण

आज के दौर में मानसिक स्वास्थ्य का महत्व तेजी से बढ़ता जा रहा है। जहां एक ओर तकनीकी प्रगति और डिजिटल युग ने हमारी जिंदगी को आसान बना दिया है, वहीं दूसरी ओर, यह हमारे मानसिक स्वास्थ्य पर भी गहरा प्रभाव डाल रहा है। सोशल मीडिया, जो एक समय पर लोगों को जोड़ने का एक साधन माना जाता था, अब कई मायनों में उन्हें वास्तविक दुनिया से दूर कर रहा है।

सोशल मीडिया पर बिताया जाने वाला समय लगातार बढ़ रहा है। लोग अपने दिन का एक बड़ा हिस्सा सोशल मीडिया प्लेटफार्मों पर बिताते हैं, जिससे वे वास्तविक जीवन के अनुभवों से वंचित रह जाते हैं। यह डिजिटल जुड़ाव हमें अपनों से दूर कर रहा है, और एक प्रकार का ₹वर्चुअल₹ जीवन जीने की आदत डाल रहा है।

सोशल मीडिया पर लगातार उपस्थिति ने लोगों के व्यवहार में भी परिवर्तन लाया है। कई लोग अपने दोस्तों और परिवार से अधिक सोशल मीडिया पर ध्यान केंद्रित करने लगे हैं, जिसके परिणामस्वरूप उनके आपसी संबंध कमजोर हो रहे हैं। यह असंतुलन मानसिक स्वास्थ्य के लिए हानिकारक साबित हो सकता है, क्योंकि व्यक्ति को वास्तविक समर्थन और सहारा नहीं मिल पाता।

सोशल मीडिया पर ₹परफेक्ट₹ जीवन की तस्वीरें देखकर कई बार लोग अपने जीवन से असंतुष्ट हो जाते हैं। यह असंतोष और तुलना की भावना उनकी खुशी को प्रभावित करती है, जिससे मानसिक तनाव, चिंता और अवसाद जैसी समस्याएं उत्पन्न होती हैं। इसके अलावा, सोशल मीडिया पर मिले फीडबैक और लाइक्स की संख्या से लोगों का आत्मविश्वास और आत्म-सम्मान भी प्रभावित होता है।

आज की स्थिति में, मानसिक स्वास्थ्य के प्रति जागरूकता बढ़ाने की आवश्यकता है। हमें समझना होगा कि सोशल मीडिया का उपयोग सोच-समझकर और सीमित मात्रा में करना चाहिए। साथ ही, हमें अपने असली जीवन के रिश्तों को महत्व देना चाहिए और उनके साथ समय बिताना चाहिए। वास्तविक सामाजिक जुड़ाव और आपसी समर्थन मानसिक स्वास्थ्य को मजबूत बनाता है, और हमें जीवन में सच्ची खुशी और संतोष का अनुभव कराता है।

अंत में, मानसिक स्वास्थ्य के प्रति सचेत रहते हुए, हमें यह समझना होगा कि सोशल मीडिया एक साधन है, न कि हमारे जीवन का आधार। इस डिजिटल युग में हमें संतुलन बनाकर चलने की आवश्यकता है, ताकि हम एक स्वस्थ और खुशहाल जीवन जी सकें।

मानसिक स्वास्थ्य को बेहतर बनाने के लिए मूल्यवान सुझाव और तकनीकें

आज के समय में मानसिक स्वास्थ्य का महत्व तेजी से बढ़ रहा है। सोशल मीडिया और डिजिटल उपकरणों का अत्यधिक उपयोग न केवल मानसिक स्वास्थ्य पर बुरा प्रभाव डालता है, बल्कि हमारी आंखों और सुनने की शक्ति को भी प्रभावित करता है। ऐसे में, जरूरी है कि हम अपने समय का सही उपयोग करें और कुछ स्वस्थ आदतें अपनाएं, जो हमारे मानसिक और शारीरिक स्वास्थ्य को बेहतर बनाए।

यहां कुछ महत्वपूर्ण सुझाव और तकनीकें दी गई हैं, जो आपको मानसिक स्वास्थ्य को बेहतर बनाने और डिजिटल उपकरणों के अत्यधिक उपयोग से बचने में मदद कर सकती हैं:

अपने शौक को प्राथमिकता दें:

अगर आप किसी शौक जैसे पेंटिंग, संगीत, बागवानी, योगा, या पढ़ने में रुचि रखते हैं, तो उन्हें अपने दैनिक जीवन का हिस्सा बनाएं। ये शौक न केवल आपके दिमाग को शांत रखते हैं, बल्कि आपको सकारात्मक ऊर्जा भी प्रदान करते हैं।

अपने शौक के लिए समय निकालना आपको मानसिक रूप से मजबूत बनाता है और आपको खुश रखने में मदद करता है।

नियमित शारीरिक गतिविधि अपनाएं:

व्यायाम, योग, या ध्यान जैसी शारीरिक गतिविधियों को अपने दैनिक रूटीन में शामिल करें। ये न केवल आपके शारीरिक स्वास्थ्य को सुधारते हैं, बल्कि मानसिक तनाव को भी कम करते हैं।

रोजाना सुबह या शाम की सैर आपके मानसिक स्वास्थ्य के लिए अद्भुत होती है। ताजगी से भरी हवा में कुछ समय बिताना आपके मूड को बेहतर करता है।

समय का सही प्रबंधन करें:

अपने दिन की शुरुआत और अंत एक अच्छी योजना के साथ करें। समय का सही प्रबंधन आपके जीवन में संतुलन लाता है और आपको मानसिक शांति प्रदान करता है।

स्क्रीन टाइम को नियंत्रित करें और उसे सीमित करें। डिजिटल डिटॉक्स जैसे अभ्यास को अपनाएं, जहां आप कुछ समय के लिए सभी डिजिटल उपकरणों से दूर रहते हैं।

सकारात्मक सामाजिक संबंध बनाए रखें:

अपने परिवार और दोस्तों के साथ समय बिताएं। उनके साथ खुलकर बातचीत करें और अपनी भावनाओं को साझा करें। वास्तविक जीवन के सामाजिक संबंध मानसिक स्वास्थ्य को मजबूत बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं।

सामाजिक और सामुदायिक गतिविधियों में भाग लें, जो आपको लोगों से जोड़ती हैं और आपकी सामाजिक चेतना को बढ़ाती हैं।

क्रिएटिविटी को बढ़ावा दें:

अपनी रचनात्मकता को समय दें। कुछ नया सीखें, जैसे कि कोई नई भाषा, कुकिंग, या हस्तशिल्प। रचनात्मक कार्य आपके मस्तिष्क को सक्रिय रखते हैं और आपको मानसिक रूप से स्वस्थ बनाते हैं।

अपने विचारों और भावनाओं को लिखने की आदत डालें। यह आत्मनिरीक्षण को प्रोत्साहित करता है और आपको अपने मानसिक स्वास्थ्य को समझने में मदद करता है।

प्रकृति से जुड़ें:

प्रकृति के साथ समय बिताएं। बागवानी, टहलने, या आउटडोर खेलों में भाग लें। यह न केवल आपके मानसिक स्वास्थ्य को बेहतर करता है, बल्कि आपको जीवन की सरल खुशियों का अनुभव भी कराता है।

प्राकृतिक ध्वनियों का आनंद लें, जैसे पक्षियों की चहचहाहट, पानी की धारा, या हवा की सरसराहट। ये ध्वनियाँ आपकी सुनने की शक्ति को भी बढ़ाती हैं।

डिजिटल डिटॉक्स:

समय-समय पर डिजिटल डिटॉक्स करें, यानी कुछ समय के लिए अपने फोन, टैबलेट और कंप्यूटर से दूरी बनाएं। यह आपको मानसिक और शारीरिक रूप से ताजगी देता है।

रात के समय स्क्रीन के उपयोग से बचें, खासकर सोने से पहले, ताकि आपकी नींद पर असर न पड़े।

इन तकनीकों को अपनाकर आप न केवल अपने मानसिक स्वास्थ्य को बेहतर बना सकते हैं, बल्कि अपने जीवन को भी अधिक सार्थक बना सकते हैं। याद रखें, आपका मानसिक और शारीरिक स्वास्थ्य सबसे महत्वपूर्ण है, और इसे बनाए रखने के लिए आपको सक्रिय प्रयास करने की आवश्यकता है।

हैदराबाद जिडिमिटेला जन्माष्टमी पर सीरवी समाज जिडीमिटेला स्थित आईमाता जी बडेर में काफी हर्ष उल्लास के साथ श्री कृष्ण जी का जन्मदिन मनाया, पुजा अर्चना श्रंगार किया।भगत भजन मण्डली जगतगीरीगुटा भेराराम सैणचा, भुराराम सैणचा द्वारा भजन प्रस्तुत किया। बडेर अध्यक्ष मांगीलाल काग, उपाध्यक्ष अर्जुन लाल बर्फा, कोषाध्यक्ष भंवरलाल काग, महा सभा सदस्य राजुराम बर्फा, कानाराम देवड़ा, भगवान राम, चुतराराम सोनपुरा, भींयाराम, समस्त कार्यकारणी पदाधिकारी एवं सदस्य एवं महिला मंडल व समाज बन्धु उपस्थित रहे (फोटो जगदीश सीरवी)

हैदराबाद बालाजी नगर स्थित जन्माष्टमी पर आईजी गौशाला बालाजी नगर में सभी गौ भक्तों ने काफी हर्ष उल्लास के साथ श्री कृष्ण जी का जन्मदिन मनाया। पंडित गोविंद शर्मा व मंगलाराम द्वारा पुजा अर्चना श्रंगार एवं 56 भोग लगाय।भजन प्रस्तुत करते हुए आईमाता भजन मण्डली बालाजी नगर अचलाराम हाम्बड़ व मोहनलाल भायल एड पार्टी श्री आईजी गौशाला अध्यक्ष मंगलाराम पंवार, सचिव हुक्माराम सानपुरा, सह सचिव ढगलाराम सेपटा कोषाध्यक्ष नारायण परिहार, भगाराम मुलेवा, मोतीलाल काग, भंवरलाल मुलेवा, बाबूलाल मुलेवा, मोहनलाल हाम्बड़, हिरालाल चोयल, चेनाराम परिहार, पारसमल शर्मा, किशनलाल पंवार, बाबूलाल मुलेवा, रतनलाल सानपरा, गोपाराम मुलेवा, मांगीलाल परिहार, नारायण लाल गहलोत, ताराराम सुथरा, लादुराम सीरवी, ओमप्रकाश परिहार, ओमप्रकाश काग, मोतीलाल राठौड़, सरिया बाई शर्मा, मैना देवी सीरवी सुगना बाई सीरवी पारी बाई सीरवी, नितु सीरवी, गणकी सीरवी, कमला सीरवी, श्री आईजी गौशाला समस्त कार्यकारणी व गौभक्त उपस्थित रहे।

पांच दिवसीय शोध कार्यशाला का आयोजन

अनूप कुमार शर्मा

भीलवाड़ा स्थानीय संगम विश्वविद्यालय के शोध विभाग ने पांच दिवसीय शोध कार्यशाला का आयोजन किया गया। विश्वविद्यालय के रिसर्च डीन प्रोफ़ेसर राकेश भंडारी ने बताया कि विश्वविद्यालय के रिसर्च स्कॉलर के शोध गुणवत्ता विकसित करने हेतु शोध कार्यशाला में शोध गुणवत्ता का विकास कैसे किया जाए, विषय पर पांच दिवसीय शोध कार्यशाला का आयोजन किया गया।प्रथम दिन उद्घाटन अवसर पर प्रोफेसर जी सोरल द्वारा शोध प्रपोजल निर्माण पर अपने विचार रखे।उद्घाटन अवसर पर विश्वविद्यालय के कुलपति प्रो करुणेश सक्सेना, प्रो वीसी मानस रंजन पाणिग्रही, रजिस्ट्रार प्रो राजीव मेहता, सभी विभाग के डीन उपस्थित थे। कार्यशाला के दूसरे दिन उप कुलपति प्रोफेसर मानस रंजन पाणिग्रही ने सिनॉप्सिस तैयारी पर विचार रखे, जिसके बाद कुलपति प्रोफेसर करुणेश सक्सेना ने परीक्षा की तैयारी के लिए व्यावहारिक सुझावों पर विचार रखे। डॉ. राकेश भंडारी ने शोध डिजाइन के सिद्धांतों पर सत्र लिया, जिसके बाद प्रोफेसर विनेश अग्रवाल ने डेटा संग्रह और विश्लेषण पर सत्र लिया, डा विकास सोमानी ने आईसीटी लैब पर सत्र लिया तथा अच्छे शैक्षणिक शोध का फ्रेमवर्क बताया। कार्यशाला के तीसरे दिन प्रोफेसर केके शर्मा ने साहित्य समीक्षा और डॉ. तनुजा ने शोध समस्या निर्माण एवं विधि पर सत्र लिया।दोपहर के समय छात्रों को चित्तौड़गढ़ किले के भ्रमण के लिए ले जाया गया।अगले दो दिनों तक डिप्टी डीन रिसर्च प्रोफेसर अर्चना अग्रवाल द्वारा नैतिकता और निष्कासन पर सत्र लिया गया और डॉक्टर किरण सोनी ने रिसर्च के लिए एसपीएसएस टूल के उपयोग पर सत्र लिया। शोध विभाग से विशाल यादव, दिव्या खेत्रपाल ने कार्यक्रम को सफल बनाया।

श्री साहिब पहने होने के कारण हवाई अड्डे पर रोकना सिख धर्म का अपमान: परमजीत सिंह सरना

स्वतंत्र सिंह भुल्लर

नई दिल्ली। पंजाब के संघर्षशील किसान नेता जगजीत सिंह डल्लेवाल और अन्य नेता, जो कि तमिलनाडु में किसान मांगों से संबंधित सम्मेलन में शामिल होने जा रहे थे। उन्हें श्री साहिब पहने होने के कारण हवाई अड्डे के सुरक्षा कर्मियों द्वारा रोका जाना किसानों के प्रति केंद्र की नफरत का प्रदर्शन है। साथ ही यह सिखों की धार्मिक आज़ादी पर भी केंद्र का हमला है। क्या अब अमृतधारी गुरसिख देश में अपने धार्मिक विश्वास के साथ स्वतंत्र रूप से विचरण नहीं कर सकते? क्या यह सिखों के प्रति नस्ली अपराध नहीं है?

केंद्र सरकार ने पहले ही किसान मुद्दों के प्रति जो बेरुखी अपनाई है, जैसे कि किसान इस देश के नागरिक ही न हों, और भाजपा के नेता भी समय-समय पर किसानों के प्रति अपनी नफरत का प्रदर्शन करते रहे हैं। और अब अमृतधारी किसान नेताओं को श्री साहिब पहने होने के कारण रोका जाना साबित करता है कि केंद्र सरकार शासन करने के धर्म का पालन करने में बिल्कुल असफल रही है।

जैसा कि किसान नेताओं ने भी कहा है कि देश में सिखों को गुलामी का एहसास करवाया जा रहा है। एक ओर सरकार खुद को सिख हितैषी बताती है, लेकिन हर मसले पर सिखों से वैर दिखाकर

अपने सिख विरोधी होने का प्रमाण देने में कोई कसर नहीं छोड़ती। केंद्र सरकार को चाहिए कि वह अपना अहंकार छोड़कर न केवल किसानों के मुद्दों का समाधान करे बल्कि इस घटना के लिए माफी मांगते हुए संबंधित कर्मियों पर उचित कार्रवाई करे।

इन शब्दों को शिरोमणि अकाली दल की दिल्ली इकाई के अध्यक्ष श्री परमजीत सिंह सरना द्वारा प्रेस को जारी एक बयान के माध्यम से व्यक्त किया गया।

राष्ट्रीय राजमार्गों पर अवैध कब्जों पर सुप्रीम कोर्ट ने जताई चिंता, अतिक्रमण हटाने को जारी किए दिशानिर्देश

नई दिल्ली। सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार से देश के राष्ट्रीय राजमार्गों और राज्य राजमार्गों पर अतिक्रमण और अवैध कब्जों पर चिंता जताई है। साथ ही सर्वोच्च अदालत ने मंगलवार को केंद्रीय सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय को निर्देश दिया है कि वह राष्ट्रीय राजमार्गों पर अतिक्रमण का नियमित मुआयना करने और अतिक्रमण हटाने के लिए टीमें गठित करे। इसके साथ ही वह एक पोर्टल बनाएं जहां लोग राष्ट्रीय राजमार्गों पर अतिक्रमण के बारे में शिकायत कर सकें और उसकी फोटो अपलोड कर सकें। ये निर्देश जस्टिस अभय एस. ओका व अगस्टिन जार्ज की पीठ ने राष्ट्रीय और राज्य राजमार्गों पर अतिक्रमण के संबंध में सुनवाई के दौरान दिए। पीठ ने पोर्टल का व्यापक प्रचार प्रसार करने के निर्देश देने के अलावा सरकार से एक टोल फ्री नंबर भी जारी करने को कहा है जिस पर लोग राजमार्गों पर अतिक्रमण की शिकायत कर सकें। इस मामले में कोर्ट नेशनल हाई वे (लैंड एंड ट्रैफिक) एक्ट 2002 के प्रविधान लागू करने और राजमार्गों से अतिक्रमण हटाए जाने की मांग पर सुनवाई कर रहा था। सुनवाई के दौरान कोर्ट की मदद कर रही न्यायमित्र वकील स्वाती घिल्डियाल ने कहा कि मंत्रालय ने 18 मार्च 2020 को एक सर्कुलर जारी किया था जिसमें हाई वे पर अतिक्रमण की सतत निगरानी के लिए टीमें गठित करने की बात की गई थी। अगर राष्ट्रीय राजमार्ग और राज्य राजमार्गों पर अतिक्रमण रोकना है तो जरूरी होगा कि इसकी सतत निगरानी के लिए टीमें गठित हों और अगर कोई अतिक्रमण पाया जाता है तो ये टीमें अतिक्रमण हटाए जाने के लिए सक्षम अथारिटी को रिपोर्ट करें।

इससे साफ हो गया है कि ममता महंत दोबारा राज्यसभा जाएंगी

मनोरंजन सासमल, स्टेट हेड उडीशा

भुबनेश्वर: अंततः, जगन्नाथ प्रधान ने पद छोड़ दिया। राज्यसभा चुनाव के लिए नामांकन पत्र दाखिल करने वाले भाजपा नेता जगन्नाथ प्रधान ने आखिरकार अपना नामांकन पत्र वापस ले लिया है। मंगलवार को उन्होंने विधानसभा जाकर रिटर्निंग ऑफिसर के सामने अपनी उम्मीदवारी वापस ले ली।अब यह साफ हो गया है कि जगा प्रधान के नामांकन पत्र वापस लेने के बाद ममता महंत राज्यसभा जाएंगी। दूसरी ओर, ममता महंत राज्यसभा सांसद का पद बरकरार रखेंगी क्योंकि बीजू जनता दल या कांग्रेस से किसी ने भी नामांकन पत्र दाखिल नहीं किया है। लेकिन इस बार ममता महंत, जो उस समय बीजे में थीं, अब बीजेपी से राज्यसभा जा रही हैं। हालांकि, जगन्नाथ प्रधान की उम्मीदवारी वापस लेने के बाद अब ममता महंत राज्यसभा के लिए चुनी गई हैं। ममता महंत आसानी से राज्यसभा के लिए चुनी गईं क्योंकि कांग्रेस और बीजेडी की ओर से किसी ने भी उम्मीदवार नहीं बनाया था।

नैतिक जागरूकता लाने के लिए जमाअत-ए-इस्लामी हिंद महिला विभाग का राष्ट्रव्यापी अभियान

शम्स आगाज़

नई दिल्ली, : जमाअत-ए-इस्लामी हिंद के महिला विभाग की ओर से सितंबर 2024 में एक महीने का राष्ट्रव्यापी अभियान शुरू किया जा रहा है। इस अभियान का विषय है 'नैतिकता ही स्वतंत्रता का आधार'। अभियान का उद्देश्य लोगों में जागरूकता पैदा करना और उन्हें यह बताना है कि सच्ची स्वतंत्रता क्या है और इसे नैतिकता से कैसे जोड़ा जाए। ये बातें: जमाअत-ए-इस्लामी हिंद की राष्ट्रीय सचिव सुश्री रहमतुन्निसा ने नई दिल्ली स्थित जमाअत के मुख्यालय में आयोजित एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहीं। उन्होंने देश में महिलाओं और लड़कियों के खिलाफ बढ़ती यौन हिंसा और हत्याओं पर दुख जताया और कहा, "हमारे समाज में महिलाओं के प्रति गहरी सामाजिक असमानताएं, स्त्रीद्वेष, पूर्वाग्रह और भेदभाव स्थिति को और भी जटिल बना दिया है। विशेषकर जब बात उपेक्षित वर्गों जैसे दलितों, आदिवासियों, अल्पसंख्यकों और विकलांग महिलाओं के खिलाफ यौन हिंसा की हो।

कोलकाता (पश्चिम बंगाल) में आरजी कर अस्पताल में बलात्कार और हत्या, गोपालपुर (बिहार) में 14 वर्षीय दलित लड़की के साथ सामूहिक बलात्कार और हत्या, उधम सिंह नगर (उत्तराखंड) में एक मुस्लिम नर्स के साथ बलात्कार और हत्या तथा बदलापुर (महाराष्ट्र) के एक स्कूल में दो किंडरगार्टन बच्चियों के साथ यौन उत्पीड़न जैसी घटनाएं साबित करती हैं कि हमारे देश में महिलाओं और लड़कियों के प्रति मानसिकता और दृष्टिकोण पर गंभीर आत्मनिरीक्षण की आवश्यकता है।

केरल में आंशिक रूप से जारी हेमा समिति की रिपोर्ट से पता चलता है कि मनोरंजन उद्योग जैसे अत्यंत उदार कार्यस्थलों पर भी महिलाओं की सुरक्षा में कमी है। राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो (एनसीआरबी) और राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वेक्षण (एनएफएचएस) के आंकड़ों के अनुसार, महिलाओं के खिलाफ अपराध साल दर साल बढ़ रहे हैं। हालाँकि, ये संख्याएँ तो केवल एक झलक है, क्योंकि ये दर्ज मामलों पर आधारित हैं। जानबूझकर या अन्यथा दबाए गए या अनदेखा किए गए मामलों की संख्या काफी अधिक है। इस चिंतनीय प्रवृत्ति का एक और उल्लेखनीय पहलू बिलकिस बानो (जिनके साथ 2002 के गुजरात दंगे में सामूहिक बलात्कार हुआ था) द्वारा न्याय के लिए किया गया कठिन संघर्ष है। उसका (बिलकिस) मामला हमारी संस्थाओं में व्याप्त प्रणालीगत पूर्वाग्रह और असंवेदनशीलता का स्पष्ट प्रमाण है।

सुश्री रहमतुन्निसा ने कहा कि "महिलाओं पर अत्याचार की मानसिकता एक महामारी की तरह फैल गई है जो हमारे देश की शांति और विकास को प्रभावित कर रही है।₹ इस अभिशाप का मुख्य कारण स्वतंत्रता के नाम पर नैतिक मूल्यों का पतन है। समाज में नैतिक मूल्यों की कमी, महिलाओं को वस्तु मानना, यौन शोषण और दुर्व्यवहार, वेश्यावृत्ति, विवाहेतर संबंध, शराब और नशीली दवाओं का बढ़ता उपयोग आदि जैसी समस्याएं उत्पीड़न और शोषण को जन्म देती हैं। इसी तरह, यौन संचारित संक्रमण (एसटीआई), गर्भपात, यौन हिंसा और बलात्कार में वृद्धि के अलावा, पारिवारिक इकाई का टूटना एवं निर्लज्जता की व्यापकता समाज के नैतिक ताने-बाने को तेजी से नष्ट कर रही है। इसके अलावा, सांप्रदायिक और जाति-आधारित राजनीति के बढ़ते प्रभाव, कुछ समुदायों और जातियों को नीच समझने और उन पर हावी होने की चाहत ने स्थिति को और खराब कर दिया है। अपराधियों और आरोपियों को राजनीतिक और भौतिक हितों के लिए नायक के रूप में प्रस्तुत किया जाता है, जबकि उनकी निंदा की जानी चाहिए।

'नैतिकता ही स्वतंत्रता का आधार' शीर्षक वाले राष्ट्रव्यापी अभियान के बारे में बात करते हुए, जमाअत-ए-इस्लामी हिंद की राष्ट्रीय संयुक्त सचिव सुश्री शाइस्ता रफत ने कहा कि "इस तथ्य से इनकार नहीं किया जा सकता है कि कोई व्यक्ति केवल नैतिक मूल्यों का अनुसरण करके ही वास्तविक जीवन और स्थायी स्वतंत्रता प्राप्त कर सकता है। इस अभियान का उद्देश्य जाति, समुदाय, रंग और नस्ल, लिंग, धर्म और क्षेत्र के भेदभाव के बिना सभी के लिए बुनियादी जरूरतों को पूरा करने और बुनियादी अधिकारों को प्राप्त करने के लिए आवश्यक स्वतंत्रता सुनिश्चित करना है।

हैदराबाद: देवेन्द्र नगर स्थित कुमावत समाज शाखा देवेन्द्र नगर कुमावत समाज तेलंगाना प्रदेश अध्यक्ष तिलायचा सोनाराम कुमावत एवं कार्यकरणी ओर परामर्श दाता सदस्य मदनलाल मोटावत, माणिक चंद, नारायणलाल घोड़ावड़, रूपाराम भोबरिया, बुधाराम होतवाल, धर्माराम डेया, अणदाराम मनावत द्वारा कुमावत समाज देवेन्द्र नगर कुकटपली, (शाखा) के अध्यक्ष बाबूलाल मालीवाड़, पारसमल मोटावत, हीरालाल हिंदड़, रामलाल जकिया, दिनेश दुबलदिया, रामेश्वर लाल, ढगलाराम, राजूराम बाकरेचा, लालाराम, हरीराम लारणा, बाबुलाल घोड़ावाड़, प्रकाश मालिया, राजूराम खेड़ावत, केसाराम नागौरा एवं शाखा अन्य सदस्य को परिवारिक विवरण बुक को सुपर्द करते हुवे। मरुधरा से पधारे हुवे बगदाराम डेया, भून्डारामजी घोड़ावड़, जयरामजी चांदोरा, कालुरामजी लारणा भी उपस्थित थे। तिलायचा सोनाराम ने सभी समाज बंधुओं को धन्यवाद दिया।

स्वामी, मुद्रक, प्रकाशक एवं संपादक संजय कुमार बाटला द्वारा इम्प्रेशंस प्रिंटिंग एंड पैकेजिंग लिमिटेड, सी-18,19,20 सेक्टर 59, नोएडा (उत्तर प्रदेश) से मुद्रित एवं 3, प्रियदर्शनी अपार्टमेंट ए-4, पश्चिमी विहार, नई दिल्ली- 110063 से प्रकाशित। सम्पर्क : 9212122095, 9811902095. newstransportvishesh@gmail.com
(इस अंक में प्रकाशित समस्त समाचारों के चयन एवं संपादन पी.आर.बी. एक्ट के अंतर्गत उत्तरदायी) किसी भी कानूनी विवाद की स्थिति में निपटारा दिल्ली के न्यायालय के अधीन होंगे। RNI No :- DELHIN/2023/86499. DCP Licensing Number F.2 (P-2) Press/2023